चिंतन

धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ होने पर दोषी को सजा मिले

मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शुक्रवार दोपहर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं और बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो गए। यह पहला मामला नहीं है कि धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह का हादसा हुआ हो। कौन भूल सकता है कि कुछ दिन पूर्व यूपी के हाथरस में हुए ऐसे ही हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में 2008 में एक धार्मिक समारोह में भगदड़ मचने से 162 लोगों की जान चली गई थी, मध्य प्रदेश के दतिया में 115 लोगों की मौत हो गई, केरल के सबरीमाला में 104 की मौत हुई, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में 27 तीर्थयात्रियों की जान गई। इन चंद हादसों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा भी ऐसे दर्जनों धार्मिक आयोजन की लंबी सूची है, जिसमें भगदड़ मचने से श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब ऐसे हादसे होते हैं तो हम दुःखी होते हैं। तरह-तरह की चर्चाएं भी होती हैं। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम को ढोल पीटा जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद न केवल हम बल्कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन और हमारा प्रशासनिक अमला लापरवाह होता है जब तक कि कोई दूसरा हादसा नहीं हो जाता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2000 से 2013 तक, भगदड़ में लगभग 2,000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (आईजेडीआरआर) द्वारा प्रकाशित 2013 के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 79 फीसदी भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थयात्राओं के कारण होती हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों में भीड़-भाड़ से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पर होती हैं। अक्सर ऐसी धार्मिक सभाएं ऐसी जगह होती हैं, जहां से निकलने का केवल एक रास्ता होता है और वो भी संकरा। इससे तीर्थयात्रियों के लिए जोखिम पैदा होता है। भगदड़ के कई कारण होते हैं, जैसे क्षमता से ज्यादा भीड़ होना, भीड़ पर खराब नियंत्रण, खराब तरीके से चुना गया कार्यक्रम स्थल, संकीर्ण स्थान, लेकिन हादसा हो जाता है तब हम इस पर चर्चा करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रशासन क्यों इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। किसी अधिकारी को दंडित क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों की मंजूरी तो वही देते हैं। आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। अब हाथरस हादसे को ही लें, न तो आयोजकों का कुछ बिगड़ा और न ही मंजूरी देने वाले अधिकारियों का। इसी का परिणाम है कि मेरठ में एक और हादसा हो गया। हालांकि बचाव रहा है कि कुछ महिला श्रद्धालु ही चोटिल हुई। वैसे भी ऐसे हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं ही होती हैं। क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं तो ऐसे आयोजनों में ज्यादा पहुंचती हैं। वे भागदौड़ में शारीरिक तौर उतनी मजबूत नहीं होती हैं। महिलाओं में घबराहट भी तुरंत बढ़ जाती है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है या दम घुट जाता है। इतना ही नहीं महिलाएं भागते लोगों के पैरों के नीचे आकर कुचली जाती हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं जागते। कानून कहता है कि अगर सत्संग किसी घर या निजी स्थान पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें केवल कुछ लोग शामिल हैं, तो आमतौर पर किसी औपचारिक परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सत्संग किसी सार्वजनिक स्थान, जैसे कि पार्क या सामुदायिक केंद्र में आयोजित किया जा रहा है, तो प्रशासन से अनुमति जरूरी है। अगर अनुमति ली गई है और उसके बाद हादसा होता है तो इसके लिए मंजूरी देने वाले अधिकारी और आयोजक दोनों को ही दंडित किया जाना जरूरी है। तभी ऐसे हादसों पर लगाम लग पाएगी।

क्रिकेट से संन्यास

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

रविचंद्रन अश्विन : एक सुनहरे युग का अंत

भारतीय क्रिकेट हमेशा से स्पिन गेंदबाजों का गढ़ रहा है। इस परंपरा ने क्रिकेट की दुनिया को अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, और रविचंद्रन अश्विन जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी दिए हैं। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, और उनके इस निर्णय ने क्रिकेट प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। अश्विन ने न केवल भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि विश्व क्रिकेट में भी अपने कौशल का परचम लहराया। रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट बेडूस स्कूल से प्राप्त की और बाद में एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। हालांकि उनका झुकाव हमेशा क्रिकेट की ओर रहा। शुरू में एक बल्लेबाज के रूप में खेलने वाले अश्विन ने जल्दी ही महसूस किया कि उनकी असली प्रतिभा ऑफ स्पिन गेंदबाजी में है। अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से की। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई और अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रविचंद्रन अश्विन का क्रिकेट करियर आंकड़ों के लिहाज से अद्वितीय रहा है। उन्होंने 94 टेस्ट मैचों में 474 विकेट लिए, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक बनाता है। इसके अलावा, वनडे और टी20 प्रारूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।अश्विन ने न केवल गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम को मजबूती दी। उन्होंने 5 शतक और 13 अर्धशतक बनाए हैं, जो यह दर्शाता है कि वे एक ऑलराउंडर के रूप में कितने सक्षम थे। अश्विन ने वनडे में 151 विकेट और टी20 में 72 विकेट लिए। हालांकि, उनका प्रमुख योगदान टेस्ट क्रिकेट में ही देखा गया। अश्विन का गेंदबाजी स्टाइल उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी में विविधता, फ्लाइट, और गति का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। उनकी 'कैरम बॉल' ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाई। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के संन्यास के बाद भारतीय टीम में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत थी जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकाल सके और कठिन परिस्थितियों में टीम का साथ दे सके। अश्विन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कुंबले की तरह, अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। हरभजन की तरह, उन्होंने भी आक्रामकता और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने की कला सीखी। अश्विन की सफलता केवल भारतीय धरती तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी गेंदबाजी हमेशा यादगार रही है। 2016 में, अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला, जो उनकी प्रतिभा और योगदान को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है। अश्विन का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा है। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलना जारी रखने का संकेत दिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी अनुपस्थिति को महसूस किया जाएगा। उनके संन्यास का फैसला कई कारणों से लिया गया हो सकता है, जिनमें उम्र, शारीरिक थकान, और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की भावना शामिल हो सकती है। अश्विन का प्रभाव केवल उनके प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और स्पिन गेंदबाजी की नई परिभाषा गढ़ी है। उनकी सोच, तकनीक, और रणनीतियां भारतीय क्रिकेट के लिए एक धरोहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और कई मैच जिताए। उन्होंने दिखाया कि एक स्पिनर भी ऑलराउंडर बन सकता है। अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर टीम में हैं, लेकिन अश्विन जैसी विविधता और अनुभव हासिल करने में समय लगेगा। रविचंद्रन अश्विन का करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज रहेगा। उन्होंने न केवल स्पिन गेंदबाजी को नई ऊंचाई दी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों को कई यादगार पल भी दिए। उनके संन्यास के बाद टीम में उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मानदंड आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। अश्विन को इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए हमेशा आभार।

असीमित है ध्यान की महिमा

ध्यान दिवस

विकेश कुमार बडोला

आज इक्कीस दिसंबर 2024 को प्रथम ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान व्यक्ति को अंतर्यात्रा करवाता है। यह व्यक्ति की एकल आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा के विविध अनुभव ही उसे वह व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, जो एक पूर्णरूपेण आदर्श होता है। ध्यान के प्रवाह में भौतिक व बाहरी जगत शून्य हो जाता है। इस आध्यात्मिक युक्ति द्वारा व्यक्ति स्वयं का इष्टतम बौद्धिक-मानसिक उपचार करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के अहं, स्व, मैं व मेरे के साधारण भाव विराट कर्तव्य बोध में रूपांतरित होने लगते हैं। ध्यान की गहनता में स्थिर होकर व्यक्ति व्यक्तिगत दोषों को स्पष्ट देखता है, उन्हें स्वीकार करता है तथा उन्हें समाप्त करने का संकल्प करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के पौराणिक महत्त्व को समझते हुए 21 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस घोषित किया है। आज इक्कीस दिसंबर 2024 को प्रथम ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व भारत के आग्रह पर महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया था। इस प्रकार भारतीय आह्वान पर दो महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दिवसों का आयोजन हमारे देश के लिये गर्व का विषय है। ध्यान शब्द अत्यंत व्यापक है। ध्यान की महिमा असीमित है। इसका प्रतिफल सर्वश्रेष्ठ है। इसमें मनुष्य की मौलिकता, नैतिकता, नवीनता और व्यक्तित्व की श्रेष्ठता समाहित है। संसार की साधारण गतिविधियों को निःस्वार्थ व निर्मोही होकर ग्रहण करके जीवन में संतोष के बिंदु पर स्थिर होना ही ध्यान है।

ध्यान व्यक्ति को अंतर्यात्रा करवाता है। यह व्यक्ति की एकल आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा के विविध अनुभव ही उसे वह व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, जो एक पूर्णरूपेण आदर्श होता है। ध्यान के प्रवाह में भौतिक व बाहरी जगत शून्य हो जाता है। इस आध्यात्मिक युक्ति द्वारा व्यक्ति स्वयं का इष्टतम बौद्धिक-मानसिक उपचार करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के अहं, स्व, मैं व मेरे के साधारण भाव विराट कर्तव्य बोध में रूपांतरित होने लगते हैं। ध्यान की गहनता में स्थिर होकर व्यक्ति व्यक्तिगत दोषों को स्पष्ट देखता है, उन्हें स्वीकार करता है तथा उन्हें समाप्त करने का संकल्प करता है। अंतर्मन की ऐसी स्थिति मनुष्य को हरसंभव विधि से वही विचार व भाव अपनाने की शिक्षा देती है, जो मानव कल्याण के लिए अभीष्ट है। ध्यान एक आंतरिक एकांत है। मन में एक शांत विश्राम ग्रहण कर श्वास-निःश्वास पर केंद्रित होना ध्यान का आरंभिक चरण है। यदि यह अवस्था दीर्घावधि तक रहती है तो निश्चित रूप में मनुष्य का तन-मन व आत्मा आश्चर्यजनक ढंग से बलवान होने लगते हैं। विचारों एवं भावनाओं में सकारात्मकता, आशा व नवीन ऊर्जा का संचार होने लगता है। जैसे-जैसे ध्यान का विस्तार होता जाता है, उसी अनुपात में आत्मविश्वास एवं आत्मचेतना विकसित होने लगती है। जगत में परिव्याप्त अनेक बुराइयों, कठिनाइयों व संघर्षजन्य कष्टों के मध्य अविचलित होकर स्थिर रहने तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निरंतर उन्मुख होने की जीवनशक्ति का निर्माण ध्यान के अगणित आत्मतत्वों से ही होता है। क्यों तक ध्यानस्थ रहने-होने का अभ्यास मनुष्य को न केवल स्वयं के लिए, अपितु अन्य मनुष्यों व समाज के लिए भी उपयोगी बनाता है। कल्पना करते हैं कि यदि संसार के आधि से भी अधिसंख्य मनुष्यगण ध्यानाभ्यास करें तो मनुष्यों का समग्र सांसारिक जीवन कितने आनंद व कितनी समृद्धि से भर जाएगा! प्रायः अधिसंख्य मनुष्यों के मन में एक विचित्र हलचल होती है। वे विचलित होते हैं। उनमें एक विकलता लहराती रहती है। यह अनेक प्रचलित विषयों, मतों, विचारों व सिद्धांतों के प्रति असहमति का अंतर्द्वंद्व होता है। अंतर्द्वंद्व का यह उद्वेग यदि अधिक समय तक अथवा निरंतर बना रहता है तो व्यक्ति का भौतिक एवं मानसिक जीवन तनाव से घिरने लगता है। इस समय जगत के विभिन्न देशों के शासक एवं

लोग इसी प्रकार के द्वंद्व से घिरे हुए हैं। इसीलिए जग में अशांति है। इसी कारण दुनिया पारस्परिक भेदों से ग्रसित है। इसी अवगुण की दुष्प्रेरणा से प्रत्येक देश एवं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ मान रहा है और दूसरे की उपेक्षा व अपमान में लिप्त है। एक ही देश में राजनीति के प्रतिनिधि विभिन्न दलों की भी यही स्थिति है। इन दलों से जुड़े हुए लोग भी विषय, मत, विचार व सिद्धांत की परस्पर प्रतिस्पर्द्धा में लिप्त हैं। यही धारा समाज व सार्वजनिक जीवन से होते हुए परिवारों तक फैल गई है। यह अहं, स्वार्थ, मैं, मेरा व मेरी की दुर्भावना बढ़ा रहा है। परिणाम में दुनिया में दो देशों के मध्य सैन्य युद्ध, शीत युद्ध एवं अर्थ युद्ध हो रहे हैं। एक ही देश में एक राजनीतिक दल व इनके सदस्यों का दूसरे राजनीतिक दल व उनके सदस्यों के साथ विषय विकार का युद्ध चल रहा है। समाज में पद, प्रतिष्ठा, गौरव व अस्मिता प्राप्त करने की अभिलाषा से भी लोगों के मध्य पारस्परिक प्रतियोगिता बढ़ रही है। परिवार ऐसी स्थिति में अप्रभावित कैसे हो सकता है।

फलतः पारिवारिक सदस्यों के मध्य भी अनावश्यक मतभेद बढ़ रहे हैं। आज चहुंओर दृष्टि घुमाने पर संवेदनशील व्यक्ति को यही दिखाई देता है और वही अनुभव हो रहा है कि मानवता समाप्ति की सीमा पर है। भौतिक, औद्योगिक व वैज्ञानिक उन्नति ने मनुष्य के जीवन को वस्तुओं एवं सेवाओं के स्तर पर तो सुगम बनाया है, किंतु ऐसी उन्नत स्थिति ने अपने व्यापक नकारात्मक परिणाम भी प्रकट किए हैं। ये परिणाम मनुष्यों के मन-मस्तिष्क एवं भावना-आत्मा को भी मानुषिक चेतना से रिक्त कर चुके हैं। इस कारण मानव प्राकृतिक मानवीय गुणों से वंचित हो रहा है।

इन स्थितियों में व्यक्तित्व के विकास को प्राथमिकता दी जानी होगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व शांत, संतुलित व समुचित होगा तो ही देश व दुनिया का विकास उचित अर्थों में फलीभूत हो सकेगा। इस प्रयोजन हेतु व्यक्ति की दिनचर्या ध्यान द्वारा परिष्कृत किए जाने की अति आवश्यकता है। जब व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय ध्यानपूर्वक बैठकर आंतरिक विचार-विमर्श करेगा, स्वयं के जीवन के मौलिक अस्तित्व व उद्देश्य से परिचित होगा तथा ध्यानाभ्यास की ऐसी शक्ति से अपने भौतिक व व्यावहारिक कार्य संपन्न करेगा तो फलस्वरूप उसका ही नहीं, अपितु समाज व राष्ट्र का भी यथोचित उपकार होगा। भारत भूमि पौराणिक समय से ही ध्यानियों की भूमि रही है। समय-समय पर अनेक साधकों, साधुओं, संतों व ज्ञानियों ने व्यक्तिगत ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जीवन के मर्म को समझा। उन्होंने जीवन ही नहीं, मृत्यु के सत्य का भी गहन आंतरिक निरीक्षण किया। ध्यान द्वारा प्रतिपादित अपनी साधनाओं द्वारा उन्हें जीवन-मृत्यु, आत्मा-परमात्मा, मोक्ष-मुक्ति, इत्यादि विषयों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान परंपरा के आधार पर भारतीय लोकजीवन में धर्म की उत्पत्ति हुई। यह असाधारण उपलब्धि थी। मानव के स्वरूप में विद्यमान साधकों के ऐसे आध्यात्मिक रूपांतरण द्वारा ही संसार में धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक तथा मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उद्गम हुआ। ध्यान के बल पर अर्जित ऐसा पौराणिक ज्ञान सदैव ही मानवों का पथ-प्रदर्शक रहा है तथा उन्हें सन्मार्ग की ओर प्रशस्त करता रहा है। आज संसार के प्रत्येक मनुष्य को भारत के पौराणिक, आदिकालिक ध्यान-साहित्य से परिचित होने की आवश्यकता है। देश, काल, व्यक्ति व परिस्थिति के अनुसार जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करने हेतु व्यक्ति को सबसे पहले आत्मदर्शन करने होते हैं। आत्मदर्शन की सुविधा ध्यान आरंभ करने पर प्राप्त होती है। राष्ट्र, समाज, परिवार और मानवों में पारस्परिक दायित्व की शुद्ध भावना तब ही आकार लेती है जब ध्यानकेंद्रित होकर जीवन के उद्देश्यों व लक्ष्यों की चेतना उत्पन्न होती है। आदर्श तथा कम से कम मनुष्योचित आचार-व्यवहार सुरक्षित रखने के लिए मनुष्यों को ध्यान के योग व उपयोग को अंगीकार करना ही होगा। मानवीय जीवन में मानवता की पुनःप्राप्ति के लिए ध्यान अति आवश्यक है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

संपूर्ण ब्रह्मांड है शिव जी का रूप

संकलित

दर्शन

जिस क्षण आपका तन अस्तित्व में आया, यह मात्र एक कोशिका के रूप में था। एक कोशिका आपका पूरा शरीर बन गई। उस कोशिका को ठीक-ठीक ज्ञात था कि आंखें कहां बनानी हैं, कान कहां बनाने हैं, गुर्दे कहां होने चाहिए, हृदय कहां होना चाहिए और एक कोशिका ने स्वयं को कई अलग-अलग ढंग से गुणित किया, जैसे कि नाखून, केश, जिह्वा, मांसपेशियां, अस्थियां और शरीर के अन्य सभी अंग। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? एक कोशिका ने बहुगुणित होकर मानव शरीर के इतने सारे अंग बनाए। मानव शरीर एक है, फिर भी यह अपनी प्रकृति और बनावट में बहुत विविधता पूर्ण है। विविधता में यह एकता संपूर्ण सृष्टि में भी नजर आती है। संपूर्ण सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, बादल, जल, पृथ्वी एक ही पदार्थ से बने हैं। हर वस्तु एक तत्व से बनी है। उस एक तत्व को शिव कहा जाता है, जिसकी हम श्रावण के इस शुभ महीने में पूजा करते हैं। शिव तत्व के बारे में बात करना बहुत कठिन है क्योंकि इसे केवल महसूस किया जा सकता है। शब्द बहुत निकट जाते हैं लेकिन वापस लौट आते हैं। क्या शिव कोई सत्ता है? क्या उसका कोई रूप है? क्या वह किसी स्थान पर विराजमान कोई व्यक्ति है? नहीं, शिव संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। शिव तत्व वह है जहां से सब कुछ आया है, सब कुछ स्थित है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि आप किसी भी समय शिव तत्व से बाहर निकल सकें क्योंकि शिव ही संपूर्ण सृष्टि हैं।

झूठ बोलकर हासिल ज्ञान ज्यादा दिन नहीं चलता

संकलित

प्रेरणा

परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, योद्धा और गुरु हैं। महाभारत के समय भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण इनके शिष्य थे। परशुराम जी से ज्ञान हासिल करने के लिए कर्ण ने झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, क्योंकि उस समय परशुराम जी ब्राह्मणों को ही ज्ञान दे रहे थे। कर्ण परशुराम जी का शिष्य बन गया और ज्ञान हासिल करने लगा। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय कर्ण की जांघ पर एक बड़े कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद न टूटे से सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं जगाया। नींद से जागने पर जब परशुराम ने देखा कि कर्ण के पैर से खून बह रहा है तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है। तब परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया था कि मेरी सिखाई हुई विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। महाभारत युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना-सामना हुआ, उस समय कर्ण अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट करने की विधि भूल गए थे। इसके बाद अर्जुन ने श्रीकृष्ण के कहने पर कर्ण का वध कर दिया। झूठ बोलकर हासिल की गई विद्या लंबे समय तक साथ नहीं देती है। ज्ञान सीखने के लिए त्याग और तप दोनों ही करना पड़ता है तब कहीं सही मायनों में ज्ञान अर्जित हो पाता है। दूसरा सही गुरु का मिलना भी जरूरी है अन्यथा भटकते रहना पड़ता है।

अंतर्मन

आज की पाती

नक्सलवाद पर कब लगेगी रोक?

भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक साल के भीतर देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है। पता नहीं, इस शुभ कार्य में भारत की सारी व्यवस्था कहां और कब तक सफल होती है? इसका उत्तर तो निकट भविष्य के गर्भ में ही छुपा है, तथापि इस घोषणा का स्वागत और प्रशंसा तो की ही जा सकती है। नक्सलवाद के संस्थापक चारु मजूमदार और कानू सान्याल ने तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक कुव्यवस्था द्वारा की गई घोर यातना और भयंकर कष्ट को झेला और सहा था।

- सांकेत अग्रवाल, कांकेर

ट्रेंड

कांग्रेस माफी मांगे

अवतार जिंदगीभर और अवधीवासी श्री राहुल गांधी द्वारा दो बीजेपी सांसदों पर किया गया शारीरिक हमला हमारे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए!

-किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री

शब्दों को वापस लें शाह

अमित शाह द्वारा संसद में दीक्षित के मसीहा बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन शब्दों को वापस लेकर इनसे पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए!

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

पूर्वांचली समाज देगा जवाब

नागरिक अवधेश जोशी नहीं जी ने संसद में हमारे पूर्वांचली भाइयों पर टिप्पणियां, नागरिकताओं और पुरुषोत्तमों से तुलना की। दिल्ली का पूरा पूर्वांचली समाज अब नागरिक को जवाब देगा।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

एक अच्छी शुरुआत

एक अच्छी शुरुआत हुई है मेरे फैनक्लब मीनल इंटरनेशनल की। एक्टर हो तो है ही, साथ एक और साथ साथ हो गया है सनातन मंच। दोनों को सनातनी ज्ञान जानने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का मौका।

-मुकेश खन्ना, अभिनेता

करंट अफेयर

पाक के लंबी दूरी मिसाइल कार्यक्रम से अमेरिका चिंतित

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को समर्थन देने से इनकार करना वाशिंगटन की पुरानी नीति है। यह टिप्पणी बाइडन प्रशासन की ओर से पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाली प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा एजेंसी-राष्ट्रीय विकास परिसर (एनडीसी) पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आई है। विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, ''यह इनकार पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के संबंध में हमारी चिंताओं पर आधारित है, लेकिन इनसे अन्य क्षेत्रों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मौजूद व्यापक सहयोग प्रभावित नहीं होता।'' अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने के आरोप में चार पाकिस्तानी कंपनियों पर बुधवार को प्रतिबंध लगाया था। इनमें इस्लामाबाद स्थित एनडीसी के अलावा कराची स्थित अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं।

ऑफ बीट

सनग्लास बचाते हैं आंखों को यूवी किरणों के दुष्प्रभाव से

पराबैंगनी विकिरणें मानव शरीर के लिए बेहद हानिकारक मानी जाती हैं। हालांकि, हम अपनी त्वचा को तो यूवी विकिरणों के दुष्प्रभाव से बचाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन आंखों की रक्षा करना अक्सर भूल जाते हैं। पिछली गर्मियों में, यूवी विकिरणों का स्तर चरम पर होने के दौरान खुले आसमान के नीचे समय बिताने वाले महज 60 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने सनग्लास का इस्तेमाल किया। सनग्लास सिर्फ फैशन का जरिया भर नहीं हैं। ये आंखों को यूवी विकिरणों के दुष्प्रभाव से बचाने में भी मददगार हैं। आइए जाने कि हम अपनी आंखों के लिए उपयुक्त सनग्लास कैसे चुन सकते हैं। यूवी विकिरण क्या है? -यूवी विकिरण सूर्य जैसे स्रोतों से उत्पन्न एक प्रकार की ऊर्जा है। ये विकिरण तीन तरह की होती हैं : यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। यूवीए और यूवीबी हमारी त्वचा और आंखों को सूरज से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। यूवी विकिरणे प्रत्यक्ष, बिखरी हुई या परावर्तित हो सकती हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 263

ईवी चार्जिंग का हो बेहतर इंतजाम

वर्ष 2023-24 में देश में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों का बाजार कुल यात्री वाहन बाजार में बमुश्किल दो फीसदी का हिस्सेदार रहा। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 में इसमें 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी होगी। इसमें आधे से अधिक ईवी बाजार दोपहिया वाहनों का है। परंतु कार निर्माता इन आंकड़ों से कतई विचलित नहीं हैं। इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर के अनुसार देश की शीर्ष कार कंपनियां आने वाले वर्ष में 15 से 20 नए ईवी पेश कर सकती हैं। 2024 में उन्होंने सात से आठ नई इलेक्ट्रिक कारें पेश की थीं। इनमें से अधिकांश ईवी महंगे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो सकते हैं। कार निर्माता शायद भविष्य पर दांव लगा रहे हैं। मोटे तौर पर उन्हें लगता है कि खर्च करने योग्य आय बढ़ने से 2030 तक 15 फीसदी बाजार ईवी का हो जाएगा और चार्जिंग के ढांचे में जबरदस्त विस्तार होगा। दोनों बातों में दम तो है। परंतु हाल फिलहाल के रुझानों पर नजर डाली जाए तो चार्जिंग या बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का नेटवर्क ईवी की चाल को सुस्त कर सकता है।

2015 में देश में फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ऐंड हाइब्रिड व्हीकल्स (फेम) के रूप में ईवी कार्यक्रम की शुरुआत हुए नौ वर्ष बीत चुके हैं। परंतु देश में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12,000 से कुछ ज्यादा ही हैं जबकि सड़कों पर 17 लाख ईवी दौड़ रहे हैं। एसऐंडपी ग्लोबल मोबिलिटी के अनुसार इस वर्ष के अंत तक करीब 9,000 नए चार्जिंग पॉइंट तैयार हो जाएंगे। फिर भी आंकड़ा जरूरत से बहुत कम होगा। चीन में दो करोड़ ईवी हैं और उनके लिए 32 लाख सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट हैं। वाहन कंपनियां भी ऐसे नेटवर्क में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए टाटा पावर ने दो कंपनियों के साथ समझौता करके चार्जिंग स्टेशन बनाना शुरू किया है। टाटा मोटर्स ने शेल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बीपी के नेटवर्क की सहायता लेकर 5,000 चार्जिंग पॉइंट बनाने पर काम शुरू किया है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, ह्युंडै और एमजी मोटर भी चार्जिंग नेटवर्क कायम करने की योजना बना रही हैं। सवाल यह है कि बड़ी कंपनियों की इन योजनाओं से भारी तादाद में चार्जिंग पॉइंट बन पाएंगे। अभी अधिकांश चार्जिंग पॉइंट स्टार्टअप या छोटे-मझोले उपक्रम चला रहे हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि गाड़ियां बढ़ने पर चार्जिंग स्टेशन बढ़ाएं या स्टेशन बढ़ने पर ईवी की तादाद खुद ब खुद बढ़ जाएगी। चार्जिंग ढांचे की कमी से ईवी बाजार छोटा रह गया है और केवल पांच फीसदी चार्जिंग ढांचे का इस्तेमाल देख कर उसका विस्तार कौन करे। उसे लगाने के लिए महंगी रियल एस्टेट, चार्जर और बिजली का भी खर्च होता है। बैटरी की अदला-बदली (स्वैपिंग) से ईवी चलते रह सकते हैं। मगर मानकीकरण की कमी और चार्जिंग पॉइंट जैसे भारी खर्च की वजह से भारत में अभी यह लोकप्रिय नहीं हो पाई है।

कुल मिलाकर इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि सरकार को चार्जिंग ढांचे को गति देनी चाहिए। इस मामले में चार्जिंग स्टेशन के लिए नई नीतियां और प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, खासकर राजमार्गों पर। सरकार कह चुकी है कि वह निजी कारोबारियों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। उसने ईवी-सब्सिडी योजना का तीसरा चरण पेश किया है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहैंसमेंट यानी पीएम-ईड्राइव को सितंबर में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह देखना होगा कि यह व्यवस्था कैसे विकसित होती है। जब तक चार्जिंग के लिए एक मजबूत ढांचा नहीं तैयार होता है, कार निर्माताओं के लिए अच्छा होगा कि वे अपने वाहनों को बाजार में न उतारें।

बिनय सिन्हा

आरबीआई की कामयाबी के लिए सरकार का एजेंडा

रिजर्व बैंक विरोधाभासी कामों में उलझा हुआ है। अगर उसे मौद्रिक नीति और नियमन के अपने बुनियादी काम को कारगर तरीके से अंजाम देना है तो इस समस्या को हल करना जरूरी है। बता रहे हैं के पी कृष्णन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए गवर्नर को मुझ जैसे तमाम स्तंभकार उन अहम सवालों के बारे में सलाह दे रहे हैं, जो उनके सामने हैं। मगर इस समय की खास बात यह है कि गवर्नर की सफलता की जिम्मेदारी सरकार पर है।

अधिकतर केंद्रीय बैंकों का काम मौद्रिक नीति पर ध्यान देना ही होता है मगर रिजर्व बैंक की भूमिका काफी लंबी-चौड़ी है। दिक्कत यह है कि रिजर्व बैंक की इन भूमिकाओं में बुनियादी तौर पर आपसी टकराव है। उसकी ज्यादातर दिक्कतें भी इन टकरावों के कारण ही उपजी हैं। ये भूमिकाएं क्या हैं?

1. रिजर्व बैंक एक मौद्रिक प्राधिकरण है और इसके इन कामों पर अब मौद्रिक नीति समिति का नियंत्रण है। इस समिति में गवर्नर और रिजर्व बैंक की बात अंतिम चाहे न हो मगर निर्णायक जरूर होती है।

2. यह बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का नियामक भी है। यह जमा बीमा संस्था का स्वामी भी है, जिसका काम तब शुरू होता है जब बैंक नाकाम हो जाते हैं (जिसमें बैंकिंग नियमन की नाकामी का भी हाथ होता है)।

3. यह भुगतान निपटान का नियामक भी है। इसके पास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का परोक्ष नियंत्रण भी है।

4. यह वित्तीय स्थिरता नियामक भी है जिसका काम सरकार और वित्तीय क्षेत्र की अन्य सांविधिक विनियामक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन नेतृत्व रिजर्व बैंक के हाथों में रहता है।

5. यह सरकार का खजाना और ऋण संभालता है। साथ ही यह सरकारी डेट बाजार का नियामक भी है। यह सरकारी डेट बाजार का सबसे बड़ा भागीदार है तथा ज्यादातर मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स (एमआईआई) का स्वामित्व और परिचालन इसी के पास है।

6. यह विदेशी मुद्रा के प्रवाह को काबू में रखता है और विदेशी मुद्रा बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी है।

7. यह मुद्रा का प्रमुख नियामक है और यही मुद्रा जारी भी करता है। इसके पास मुद्रा छापने वाली प्रेस भी हैं। मगर संसदीय विधानों के तहत मुद्रा से जुड़ी ज्यादातर औपचारिक नियामकीय भूमिका सरकार की ही हैं।

8. यह मुद्रा बाजार का नियमन करता है और उन सभी डेरिवेटिव का भी नियामक है, जिनका विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) नहीं करता।

9. यह प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी चलाता है जिसमें 800 से अधिक कर्मचारी हैं और वह क्लाउड सेवा कंपनी शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

दुनिया में कोई और केंद्रीय बैंक नहीं है जो इतने सारे कामों को एक साथ साध रहा हो। समस्या यह है कि इनमें से कई भूमिकाएं एक दूसरे की विरोधी हैं। सरकार का ऋण संभालने वाले को भूमिका में वह दरें कम रखने की उम्मीद करता है मगर मुद्रास्फीति को काबू में करने की उसकी जिम्मेदारी से इसका सीधा टकराव होता है। इसी प्रकार मजबूत या स्थिर विनिमय दर की उसकी तलाश मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की उसकी भूमिका से टकराती है। बैंकिंग नियमन अधिनियम और उसके तहत सरकारी बैंकों के बारे में भारत सरकार को दी गई भूमिका बैंकिंग नियमन में रिजर्व बैंक और सरकार का सीधा टकराव कराती है। भुगतान नियमन में मजबूत अर्थशास्त्र एनपीसीआई और यूपीआई में सरकारी एकाधिकार से टकराती है।

जो लोग केंद्रीय बैंकिंग में नए हैं वे मंडेल-फ्लेमिंग की 'इंपॉसिबल ट्रिनिटी', टिंबर्जन के 'असाइनमेंट प्रिंसिपल', विवेक, शक्ति विभाजन और अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे सिद्धांतों तथा नियामकीय ढांचे के विरुद्ध किडलैंड/प्रेस्कॉट के निबंधों जैसे सैद्धांतिक विचारों को खारिज कर देते हैं। मगर व्यावहारिक लोग इन सैद्धांतिक मसलों को समझते हैं। आइए, रिजर्व बैंक के कुछ पिछले गवर्नरों के कार्यकाल में ऐसी उथलपुथल भरी परिस्थितियों का परीक्षण करते हैं:

1. वाई वी रेड्डी बनाम वित्त मंत्री का मसला वास्तव में विशाल और लगातार बढ़ते पूंजी प्रवाह और विनिमय दर की स्थिरता के बीच जबरदस्त संघर्ष को संभालने के बारे में था। इस प्रवाह के कारण देश के भीतर नकदी का इतना भंडार हो गया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय कर्ज तेजी से दिया जाने लगा, मुद्रास्फीति का संकट हुआ और उसके बाद बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ।

2. डी. सुब्बाराव बनाम वित्त मंत्री में तो राजकोषीय अनुशासनहीनता के बीच मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा विनिमय दर को कम रखने के आह्वान के बावजूद उसे बाजार के जरिये ही तय होने देने की बात थी।

3. रघुराम राजन बनाम भारत सरकार में मसला नोटबंदी और रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार की परस्पर विरोधी भूमिका के बारे में था। नकदी पर चलने वाली अर्थव्यवस्था में मुद्रा नियामक की भूमिका अहम है। हमारा देश अब भी नकदी पर ही चलता है। इस संदर्भ में याद कीजिए कि रिजर्व बैंक के बोर्ड से जब नोटबंदी पर मशविरा किया गया तो उसने बहुमत के खिलाफ राय नहीं दी। ये तथ्य अब इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में हैं।

4. ऊर्जित पटेल का कार्यकाल सरकारी बैंकों के नियमन में टकरावों से भरा था।

5. विगत कुछ महीनों के दौरान सरकारी अधिकारियों द्वारा शक्तिकांत दास के विरुद्ध असंतोष का सार्वजनिक प्रकटीकरण भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और उचित मुक्त पूंजी प्रवाह के साथ विनिमय दर को स्थिर रखने के बारे में था।

नए गवर्नर को डेरिवेटिव बाजार में भारी भरकम सटोरिया गतिविधियों का सिरदर्द विरासत में मिला है। इस दौरान रुपये में गिरावट से खजाने को नुकसान की आशंका के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के सभी गवर्नरों को इन कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा है? इनमें से प्रत्येक एक शानदार व्यक्ति है, जिसमें अद्भुत बौद्धिक क्षमता, परिपक्वता और व्यक्तिगत निर्णय की क्षमता है। शायद इसे शेक्सपियर ने ज्यादा अच्छी तरह से समझाया था, 'प्यारे ब्रूटस, गलती हमारी नहीं हमारे सितारों की है।'

आरबीआई की जिम्मेदारी, उसकी बुनियाद और व्यापक भूमिका विष के प्याले की तरह है, जो एक गवर्नर से दूसरे गवर्नर के हाथ में पहुंचता रहता है। समाधान आरबीआई की तय भूमिका के सही क्रियान्वयन में नहीं बल्कि इस बात में है कि भारत सरकार इन टकरावों को दूर करने की दिशा में प्रयास करे। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने के लिए कानून बनाया था।

वित्तीय क्षेत्र का नियमन करने वाली तमाम एजेंसियां संसद द्वारा कार्यपालिका की सलाह पर बनाई जाती हैं। वित्त मंत्रालय इन एजेंसियों की भूमिका, शक्ति, शासन, प्रक्रियाओं और जवाबदेही तय करने वाले कानून बनाता है। 2016 में विधायी बदलावों की मदद से मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने वाली व्यवस्था तैयार की गई थी। अगले बजट में उसे याद करना चाहिए और अगले कुछ साल में रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी को स्पष्ट करने की योजना बनानी चाहिए। ये तमाम विचार और कानूनों के मसौदे विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट में मौजूद हैं खास तौर पर वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की रिपोर्ट में।

हां, गवर्नर को शुभकामनाएं।

(लेखक आईसीपीपी में मानद सीनियर फेलो हैं और अफसरशाह रह चुके हैं)

महाभियोग: विपक्ष का नासमझी भरा दांव!

विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों ने 10 दिसंबर को उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का अभूतपूर्व प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्य सभा में पेश होना था और चूंकि दोनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का बहुमत है, इसलिए हार भी तय थी। आखिरकार राज्य सभा के उप सभापति ने धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का यह नोटिस खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि सदन में तयशुदा हार की बात जानते हुए भी विपक्ष ने आखिर क्यों इसे पेश किया?

पहले तो यह समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग केवल इसलिए नहीं लाया जा सकता कि उनके आचरण से विपक्ष को परेशानी होती है। यह बात अलग है कि धनखड़ भी रूखे लहजे में कानूनी और सियासी तरीके से अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद जया बच्चन ने अगस्त में एक चर्चा के दौरान उनके 'लहजे' पर एतराज जताया था, जिस पर सभापति ने कहा, 'मुझे न सिखाएं। आप कोई भी हों, सेलेब्रिटी ही क्यों न हों, आपको सदन की गरिमा बनाए रखनी होगी।' संसद के बाहर जया ने कहा कि उनके लिए यह बेहद 'अपमानजनक अनुभव' था। लेकिन त्रिवेंद्र मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने स्पष्ट कर दिया कि सपा इसे आधार बनाकर सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाती है तो वे लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे।

वास्तव में किसी का स्वाभिमान आहत होना सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने का आधार नहीं हो सकता और विपक्ष इसे उचित ठहरा भी नहीं सकता। विपक्ष का तर्क है, 'आप हमें बोलने नहीं देते।' विपक्ष ने नियम 267 के तहत (लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के समान इसमें भी मौजूदा प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बाकी सभी मामले रोक दिए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर मतदान भी कराया जाता है) 40 से अधिक प्रस्ताव पेश किए, लेकिन धनखड़ ने एक भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि स्थगन याचिकाओं को उनकी प्रक्रियागत खामियों के कारण खारिज किया गया और इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं था।

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

विपक्षी नेताओं का कहना है कि बोलते समय धनखड़ अक्सर हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनके विचारों का तारतम्य टूट जाता है और सत्ता पक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल जाता है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने वाली कार्यमंत्रणा समिति की एक हालिया बैठक में एक विधेयक पर तीन घंटे की चर्चा पर सहमति बनी। इस पर विपक्ष के एक सांसद ने चुटकी ली, 'दो घंटे विधेयक के लिए और एक घंटा सभापति के लिए।' लेकिन क्या महाभियोग इसलिए लाया जाए क्योंकि सभापति को सदन में अपनी आवाज सुनना पसंद है?

इसके बाद सदस्यों के निलंबन का भी मामला है। अगर कोई व्यक्ति सदन की कार्यवाही में बार-बार बाधा डालता है तो उसे सदन से बाहर किया ही जाएगा। इस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं है। नियमों के अनुसार निलंबन 'सत्र के शेष समय तक' ही लागू रहता है। मगर कई सांसद काफी लंबे समय तक सदन से निलंबित रहे जैसे कि आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को जुलाई 2023 से जून 2024 तक सदन से बाहर रखा गया।

राज्य सभा जो भी करती है वह राज्यों की विधान परिषदों तथा विधान सभाओं के लिए मिसाल होती है। इसलिए राज्य विधायिका में भी विपक्षी विधायकों को महीनों या सालों तक निलंबित करने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि राज्य सभा के सभापति ऐसा कर चुके हैं। यह चिंता की बात है मगर महाभियोग का कारण शायद ही बन पाए। विपक्ष बेशक मानता है कि वह बहुत पक्षपाती हैं मगर धनखड़ ने कानून के जो गुर सीखे हैं, उनके बल पर वे ऐसी मुश्किलों से उबरना भी जानते हैं।

अपने गृह राज्य राजस्थान में धनखड़ को फौजदारी वकील के तौर पर मशहूर हैं। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय से वकालत की शुरुआत की थी और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। जब राज्य में जाट आंदोलन चल रहा था तब सरकार द्वारा हरियाणा और राजस्थान में जाटों के खिलाफ दर्ज हुए दर्जनों मुकदमे लड़ने वह ही खड़े हुए थे। जोधपुर में काले हिरण के अवैध शिकार के विवादास्पद मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को ओर से लड़ रहे वकीलों की टीम में वह भी शामिल थे।

जनसेवा के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वह कांग्रेस में रहे (1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ के विधायक रहे), जनता दल (वी पी सिंह सरकार में सांसद थे और हरियाणा के जाट नेता देवी लाल की सिफारिश पर यह संभव हुआ था) में रहे और चंद्रशेखर सरकार के अल्पकालिक कार्यकाल (1990-91) में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में उनके गुरु भैरो सिंह शेखावत थे, जो उपराष्ट्रपति भी रहे।

भाजपा के साथ उनका जुड़ाव तब शुरू हुआ, जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके स्वामी असीमानंद का पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे थे। असीमानंद पर 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह में बम विस्फोट की साजिश रचने के आरोप थे। बाद में वह इस मामले में बरी हो गए थे। संघ और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कुछ अन्य सदस्यों पर भी इस मामले में आरोप लगे। उनमें दो को इस मामले में दोषी ठहराया गया तथा 2017 में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। धनखड़ ने वह मुकदमा लड़ने में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मदद भी की थी। इसी वजह से उन्होंने राज्य सभा में एक बार खुद को '25 वर्षों तक संघ में एकलव्य' बताया था।

धनखड़ ने उपराष्ट्रपति बनने के बाद जयपुर में आयोजित एक सम्मान समारोह में कहा, 'मैंने ताऊ देवीलाल और भैरो सिंह शेखावत के चरणों में बैठकर जादू सीखा है।' इतना तो तय है कि महाभियोग नहीं आएगा। लेकिन राज्य सभा में सरकार और विपक्ष के बीच जो कड़वाहट दिख रही है उसे कोई जादू ही खत्म कर सकता है।

आपका पक्ष

शिक्षा का अधिकार: लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल

लोक सभा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा साझा की गई जानकारी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। देशभर में 11.70 लाख से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से (7.84 लाख) है। यह आंकड़ा शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार की दिशा में एक बड़ी चुनौती को दर्शाता है। झारखंड और असम जैसे राज्यों में भी हजारों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो यह सिद्ध करता है कि सरकारी योजनाओं और पहलों के बावजूद शिक्षा तक पूरी पहुंच सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य है। इसके पीछे कई कारक हो सकते हैं, जैसे आर्थिक कठिनाइयां, शहरी-ग्रामीण भेदभाव, और शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता। 'प्रबंध' पोर्टल के जरिये सरकार बच्चों की पहचान कर रही है, लेकिन इस पहचान के बाद उनके पुनः शिक्षा व्यवस्था में शामिल होने की प्रक्रिया अब भी धीमी है। राज्य सरकारों के सहयोग और लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से यह चुनौती हल करने का दावा किया गया है, परंतु इसके लिए ठोस और व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता है। अगर सरकार और समाज इस दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाते, तो यह स्थिति और भी विकट हो सकती है, जो देश की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए खतरे की घंटी होगी।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

नोएडा के एक निजी स्कूल को बम की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को बम निरोधक दस्ता जांच करने पहुंचा

आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाना उचित

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) ने परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई मॉडिघूल का उपयोग करने की जो योजना बनाई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता व गोपनीयता कायम रखने के लिए सर्वप्रथम, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन फॉर्म आधार से लिंक करने के निर्देश दिए जाएं। इससे उनके फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ कभी भी चेक किए जा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से फॉर्म लिंक नहीं हो पाते हैं, उनकी भर्ती परीक्षा अलग परीक्षा केंद्र पर ली जाए। परीक्षा केंद्र व परीक्षा से संबंधित अमले का चयन काफी सावधानीपूर्वक करना होगा। जहां तक डमी अभ्यर्थियों का सवाल है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी (एआई) का सहारा लिया जा सकता है और यदि किसी भी तरीके से डमी अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठ भी गया तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को रोक लिया जाए। आमतौर पर जो अभ्यर्थी डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल करते हैं, वो फॉर्म भरते समय अपनी फोटो के बजाय डमी कैंडिडेट की फोटो लगा देते हैं और कई बार डमी कैंडिडेट के साथ अपनी फोटो मर्ज करा लेते हैं। इसका फायदा उठाकर वो एग्जाम सेंटर पर आते हैं और फर्जी आधार कार्ड भी बना लेते हैं। ऐसे में पर्यवेक्षकों की आंखों में धूल झोंक कर परीक्षा देते हैं। उसी से निपटने के लिए हैंडराइटिंग सैंपल लिया जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से हैंडराइटिंग सैंपल लिया जाए और बाद में किसी भी स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर इस हैंडराइटिंग सैंपल के जरिये अभ्यर्थी की जांच की जाए। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

वियतनाम तटरक्षक बल का जहाज सीएसबी 8005 शुक्रवार को कोच्चि से रवाना हुआ। यह जहाज संयुक्त समुद्री अभ्यास के लिए 16 दिसंबर को कोच्चि आया था।

सम्पादकीय

फेडरल रिजर्व के फैसले के गूढ़ अर्थ

बदलती नीतिगत वास्तविकता के मुताबिक ढलना अक्सर वित्तीय बाजारों के लिए मुश्किल होता है। बुधवार को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने दरों में 25 आधार अंकों की कमी की। यह कमी वित्तीय बाजारों की अपेक्षाओं के अनुरूप ही थी। लेकिन शेयर और बॉन्ड बाजार दोनों में बिकवाली हुई। एसऐंडपी 500 में तीन फीसदी की गिरावट आई जबकि 10 वर्ष के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड 13 आधार अंक बढ़कर 4.5 फीसदी हो गई जो कई महीनों का उच्चतम स्तर है। बॉन्ड कीमतें और यील्ड एक दूसरे से उलटी चाल चलते हैं। भारत में बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में गुरुवार को 1.2 फीसदी की गिरावट आई। वित्तीय बाजारों में इस बिकवाली की प्राथमिक वजह एफओएमसी के संशोधित अनुमानों को माना गया। इसने दिखाया कि समिति को अब उम्मीद है कि फेडरल फंड दरों में 2025 में केवल 50 आधार अंकों की कमी होगी जबकि सितंबर में एक फीसदी कमी का अनुमान लगाया गया था।

इस बदलाव की वजह है मुद्रास्फीति। हालांकि मुद्रास्फीति की दर 2022 की ऊंचाइयों से काफी नीचे आई है लेकिन अभी भी यह फेडरल रिजर्व के मध्यम अवधि के दो फीसदी के लक्ष्य से ऊपर है। संशोधित अनुमानों के मुताबिक 2025 में मुद्रास्फीति की दर सितंबर के अनुमान से 40 आधार अंक बढ़कर 2.5 फीसदी रह सकती है। कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन क्षेत्र से परे) के अनुमानों को भी संशोधित करके बढ़ाया गया है। सकारात्मक बात यह है कि एफओएमसी के सदस्यों ने वृद्धि और रोजगार के अनुमानों में भी अनुकूल संशोधन किया है। बहरहाल वित्तीय बाजार 2025 में दरों में अधिक कटौती पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। मुद्रास्फीति के ऐसे नतीजों से परे वित्तीय बाजार डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले नए प्रशासन की अनिश्चित संभावनाओं पर भी चिंतित है। उदाहरण के लिए ट्रंप तमाम वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना चाहते हैं। उनका इरादा चीन जैसे चुनिंदा देशों पर ऊंचा शुल्क लगाने का भी है।

हालांकि दुनिया वास्तविक कारोबार पर नजर रखेगी लेकिन फेड के नजरिये से ऐसे कदम अपरिहार्य रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाएंगे जिसका असर उच्च मुद्रास्फीति में नजर आएगा। हालांकि मुद्रास्फीति पर शुल्क दरों का प्रभाव समय के साथ कम हो सकता है लेकिन यह फेड के काम को जटिल बना सकता है। ऐसे बदलाव वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ाएंगे। तुलनात्मक रूप से ऊंची ब्याज दरें पूंजी प्रवाह को अमेरिका की ओर करेंगी और डॉलर को मजबूती देंगी। यह बात अन्य मुद्राओं पर, खासकर उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव डालेगी। फेड के निर्णय के बाद डॉलर सूचकांक दो वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में गिरावट के अलावा गुरुवार को भारतीय रुपये ने भी डॉलर के समक्ष 85 रुपये का मनोवैज्ञानिक अवरोध भंग कर दिया।

संसद की गरिमा पर संकट : एक चिंताजनक दृश्य

लोकसभा में विपक्ष के नेता पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। क्या यह चिंतनीय और संवेदनशील नहीं है कि संसद अब विवाद और आरोप-प्रत्यारोप की जगह बनती जा रही है ? पता नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उक्त घटना संसद ही नहीं, पूरे देश को शर्मशार करने वाली है। राजनीति का स्तर इतना ओछा व तुच्छ नहीं होना चाहिए कि वह मर्यादा विहीन दिखने लगे। सच तो यह है कि आज राजनीति का स्तर दिन-ब-दिन गिरता ही चला जा रहा है। आज आलोचना का कोई तरीका नहीं रहा।

सुनील कुमार महला

हाल ही में शीतकालीन सत्र में संसद में (बाहर और भीतर) जो हुआ, उससे लगता है कि संसद की गरिमा खतरे में है। यह विडंबना ही है कि संसद परिसर में धक्का-मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। बहुत ही दुखद है कि धक्का मुक्की और हाथापाई में सांसदों को आईसीयू तक में भर्ती कराना पड़ा। वास्तव में यहां यह मानना कठिन है कि यह धक्का-मुक्की अनजाने में हुई। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उन्हें संसद में प्रवेश करने से रोका गया। वो धक्के की बात से अस्वीकार कर रहे हैं। विपक्ष बाबा साहेब के अपमान पर माननीय गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहा है और बाबा साहेब के अपमान पर माफी मांगने की बात कह रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष का घटना के बाद भी अहंकार नहीं टूटा है। नेता प्रतिपक्ष खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जानबूझकर सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच पहुंचे और धक्का मुक्की ही नहीं गुंडागर्दी भी की। सत्ता पक्ष ने यहां तक कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है। बहरहाल, संसद में जो कुछ भी हुआ है वह शर्मनाक होने के साथ ही बहुत ही दुखद भी है। संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का हनन हमारे देश और समाज की प्रतिष्ठा और छवि पर भी निश्चित ही असर छोड़ता है। संसद देश और समाज के विभिन्न मुद्दों पर तार्किक बहस और कानून निर्माण के लिए बनी है, न कि लड़ाई-झगड़े, आपसी विवाद, धक्का मुक्की और हाथापाई के लिए। आलोचना करने का भी एक गरिमामयी तरीका होता है, मर्यादा होती है। कहना गलत नहीं होगा कि आज संसद में आलोचना और निंदा, चर्चा और अपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि आज सांसदों में आपसी राजनीतिक कटुता लगातार पनपनी चली जा रही है और इसकी बेल लगातार और अधिक जहरीली होती चली जा रही है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं का भी एक शालीन और सभ्य तरीका होता है। सदन में बात पूरे सलीके और एक दूसरे के सम्मान, आदर-सत्कार के साथ रखी जाती है।

यह ठीक है कि आलोचना में, देश और समाज के मुद्दों पर आपसी बहस में हल्की-फुल्की तकरार, हल्का-सा गुस्सा, तेवर कभी-कभार संभव हो सकते हैं लेकिन तकरार और गुस्से का यह मतलब तो कतई नहीं है धक्का-मुक्की, हाथापाई तक की ही नौबत आ जाए। राजनेताओं को यह बात याद रखनी चाहिए कि मर्यादा विहीन राजनीति हमेशा केवल धिक्कार की ही पात्र होती है। यह शर्मनाक है कि डा. अंबेडकर के नाम पर पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं? और संविधान के नाम पर होने वाली चर्चा भी आज अपने निम्न स्तर पर चली गई है, जिसमें पक्ष रखने की बजाय एक-दूसरे को बदनाम करने की ओर रुझान ज्यादा है। सच तो यह है कि आज आपसी विचार-विमर्श, संवाद की परिभाषा तो जैसे ही समाप्त हो गई है। सच तो यह है कि आज राजनीति और राजनेता अपने छिछले स्तर पर आ गए हैं। एक समय था जब राजनीति और राजनेताओं की अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा थी, अब ऐसा लगता है कि यह धीरे-धीरे धुमिल सी होती चली जा रही है। इससे बड़ी विडंबना ही क्या हो सकती है कि आज राजनेता अपने चूल्हे के नीचे आंच सरकाने से वास्ता रखने लगे हैं, राष्ट्र और समाज से उन्हें कोई लेना-देना नहीं। सांसदों के बीच कटुतापूर्ण और शत्रुतापूर्ण संबंध लोकतंत्र के लिए सही नहीं ठहराये जा सकते हैं। ऐसा होना भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज हम दुनिया का विशालतम लोकतंत्र कहलाते हैं लेकिन विशालतम लोकतंत्र में यदि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो क्या यह विश्व पटल पर हमें और हमारे देश को शर्मशार नहीं करता है ? आज संसदीय वातालिप बहुत ही निम्न स्तर का , अभद्र और अशोभनीय हो गया है। यह पहली बार नहीं है जब संसद में ऐसी स्थितियां (हाथापाई, धक्का मुक्की) पैदा हुई हैं। इससे पहले भी भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में कई बार झड़प की घटनाएं हो चुकी हैं और इस वजह से कई बार अप्रिय स्थिति पैदा हो चुकी है। बहुत समय पहले तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन में हुई घटनाओं को निंदनीय बताते हुए चेतावनी दी थी कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर 2009 को राज्यसभा में अमर सिंह और भाजपा के आहलूवालिया में हाथापाई हो गई थी। 5 सितंबर 2012 को राज्यसभा में एससी, एसटी कोटा बिल पेश किए जाने के दौरान बीएसपी सांसद अवतार सिंह और एसपी सांसद नरेश अग्रवाल के बीच हाथापाई हुई।13 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर भारत की संसद में बड़े पैमाने पर हुए झगड़े ने अध्यक्ष को कक्ष से भागने पर मजबूर कर दिया और कई सांसदों को अस्पताल ले जाया गया। संसद ही नहीं राज्य विधानसभाओं में भी ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने शर्मसार किया। मसलन बहुत समय पहले जनवरी 1988 में तमिलनाडु विधानसभा में माइक और कुर्सियों का फेंका जाना, 26 मार्च 1989 को जयललिता और करुणानिधि के विधायकों के बीच हिंसा भड़क जाना,16 दिसम्बर 1993 को यूपी विधानसभा में 33 विधायकों का घायल हो जाना,21 अक्टूबर 1997 को यूपी विधानसभा में ही पेपरवेट, फर्नीचर चलने पर 50 सदस्यों का घायल हो जाना,11 दिसंबर 2012 को पश्चिम बंगाल विधानसभा हाथापाई, 2013 में तमिलनाडु विधानसभा में बागी विधायकों के साथ हाथापाई,

13 मार्च 2015 को केरल विधायकों द्वारा कुर्सियां तोड़ना, माइक को फेंकना और मेजों पर चढ़ना,18 फरवरी 2017 को तमिलनाडु विधानसभा में राज्य के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हिंसा और बर्बरता की घटनाएं,14 मार्च 2018 को गुजरात विधानसभा में थप्पड़ व लात-घूंसे चलना के अलावा हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र , पश्चिमी बंगाल और जम्मू-कश्मीर विधानसभा की घटनाओं ने समाज और देश को शर्मशार किया। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय संविधान ने हमें उच्च मानवीय और राजनीतिक संस्कृति प्रदान की है। संविधान सरकारों को समाज और देश को दिशा दिखाने का कार्य करता है।

भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली के प्रमुख तत्व विद्यमान है। यह विडंबना ही है कि आज उसी संविधान के नाम पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने का खेल शुरू हो गया है। असल में संविधान विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का समूह है, जो शासन की मर्यादा, स्वरूप और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। लोकतंत्र में संविधान की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश का संविधान आपसी तालमेल, सहयोग, सह-अस्तित्व, समानता और आपसी संवाद(इंटरेक्शन) की बुनियाद है। संविधान बिना देश कुछ भी नहीं। यह देश का संविधान ही है जो नागरिकों में विश्वास जगाता है। संसद में जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत ही निंदनीय और देश को शर्मसार करने वाला है। ईश्वर संसद को चलाने वालों को सद्बुद्धि दे।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई दिशा संकेतों की पूरा करेंगे। साथ आज यह जरूरत पड़ेगी कि आपके जीवन में ऐसे कौनसे रंग है, जहां आपको विश्वास कुछ लोगों और दूसरों तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। साथ ने किसी लम्बे सफर में और यात्रा पूरी को सुनिश्चित साथ सावधानता और सही संकेत और कामों में साथ प्राप्त होंगे।

मेष
आपको उग्र स्वभाव पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। आज आप मानसिकरूप से थकान का अनुभव करेंगे। अधिक परिश्रम की तुलना में कम फल की प्राप्ति होगी। संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है।

वृष
आज आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है। शारीरिक रूप से आलस्य और अशक्ति का अनुभव करेंगे। मन में चिंता रह सकती है। गलत कामों से दूरी बनाए रखें। किसी भी योजना को सावधानीपूर्वक करें।

मिथुन
आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। आप का हर काम आज सफलता से पूरा होगा। नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है।

कर्क
सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। पेट दर्द से परेशानी हो सकती है। आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। उसमें सफलता भी प्राप्त भी करेंगे। पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है। वाहन सुख मिलेगा।

सिंह
अधिकारियों से काम का उचित फल भी मिल सकता है। भाई-बंधुओं के साथ कोई झगड़ा दूर होगा। विचार लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। आर्थिक विषय में सावधानी बरतनी आवश्यक है। नेगेटिव विचारों से मन परेशान रह सकता है।

कन्या
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी कामों में आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे। नई योजना का आरंभ करने के लिए आज अनुकूल दिन है। सरकारी काम में लाभ होगा। व्यापार में बाधाएं उपस्थित होंगी।

तुला
आप में आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप जल्दबाज़ी में निर्णय ले सकते हैं। पिता तथा बड़ों की ओर से लाभ होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। वाणी में उग्रता ना रखें।

वृश्चिक
आपका आज का दिन शुभफलदायी है। कई क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी हो सकता है। पर्यटन स्थल की सैर आपको रोमांचित करेगी। परिजनों से मुलाकात आनंददायी हो सकती है।

धनु
रोमांस के लिए आज अनुकूल दिन है। आज का हर कार्य आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे। प्रवास-पर्यटन की संभावनाएं है। अच्छा भोजन और नए वस्त्र मिलने का अवसर मिल सकता है। भागीदारी से लाभ होगा।

मकर
आज अचानक धन खर्च होने का योग है। यह खर्च स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है। व्यावहारिक या सामाजिक काम के लिए बाहर जाना हो सकता है। खान-पान में ध्यान रखें। क्रोध तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

कुंभ
आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है। मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है। स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। धार्मिक कामों में धन का खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन
मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव नहीं करेंगे। निराशा और असंतोष की भावना से काम में मन नहीं लगेगा। कुटुंबजनों के साथ किसी विषय पर वाद-विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों को अभ्यास का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारे आज के कॉलम के सुपर स्टार हैं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री बीजू जॉर्ज जोसफ । 22 अक्टूबर सन 1967 में केरल में जन्में बीजू सर भारतीय पुलिस सेवा के मजबूत व दमदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इनका कहना है कि पुलिस कोई पद नहीं बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए समाज का एक विश्वास का नाम है इसलिए पुलिस के स्लोगन आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय को पूरी तरह चरितार्थ करने वाले अधिकारी के रूप में इन्हे जाना जाता है। आज राजस्थान की बड़ी और जिम्मेदारी वाली पोस्ट पुलिस आयुक्त, जयपुर जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व ये अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता राजस्थान जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान ,जयपुर। महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर। पुलिस आयुक्त, जोधपुर। महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेन्ज अजमेर। महानिरीक्षक पुलिस, ऑपरेशन जयपुर। महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेन्ज भरतपुर। पुलिस आयुक्त, जोधपुर।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय) जयपुर। उप पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी(क्राइम) जयपुर। पुलिस अधीक्षक,जयपुर शहर (पूर्व) जयपुर (डीआईजी ग्रेड में)। पुलिस अधीक्षक, अलवर। पुलिस अधीक्षक, सीबीआई बैंगलुरु। पुलिस अधीक्षक, गंगानगर। पुलिस अधीक्षक, धौलपुर। एडीसी राजस्थान के राज्यपाल, जयपुर। कमांडेंट, द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा। सहायक अधीक्षक पुलिस, शहर गंगानगर। सहायक अधीक्षक पुलिस, कोटा (शहर) रहे हैं। अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए सरकार की ओर से इन्हे राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से नवाजा गया है। इसके अलावा विभिन्न संगठनों व संस्थाओं द्वारा इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए इनका भावपूर्ण सम्मान किया गया है।

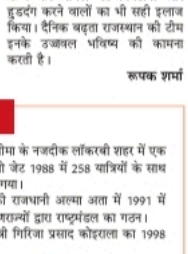

श्री बीजू जॉर्ज जोसफ
(भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी)

इनकी अलवर एसपी शिप के दौरान इनकी कार्यशैली को बेहद करीब से देखने का मौका मिला था जब राजगढ़ में चुनाव के दौरान गढ़ीसवाईराम में आगजनी की घटना हुई ऐसे में वहीं कैम्प कर मामले को निपटाया और हुड़दंग करने वालों का भी सही इलाज किया। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

21 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- जॉन जे 1784 में अमेरिका के पहले विदेश मंत्री बने।
- रसायन शास्त्री पियरे और मेरी क्यूरी ने 1898 में रेडियम की खोज की।
- अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 1921 में धरना प्रदर्शन और काम रोकने को असंवैधानिक घोषित किया।
- ब्रिटेन के संरक्षित राज्य के दर्जे से मुक्त होकर 1923 में नेपाल पूर्ण स्वतंत्र देश बना।
- अर्थर वेन का बनाया दुनिया का पहला क्रॉसवर्ड 1931 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार में प्रकाशित हुआ।
- रंगीन चित्रों और आवाज वाली पहली कार्टून फिल्म- डिजनीस स्नो व्हाइट- का प्रदर्शन 1937 में किया गया।
- पुर्तगाली शासकों ने 1949 में इंडोनेशिया को संप्रभु राष्ट्र घोषित किया।
- सैफुद्दीन किचलू 1952 में तत्कालीन सोवियत संघ का लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने।
- अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ़ कैनेडी और ब्रिटानी प्रधानमंत्री हेरल्ड मैकमिलन ने 1962 में बहामास में बातचीत के बाद एक बहुआयामी नैटो परमाणु बल बनाने का फैसला किया।
- कर्ट वॉल्डहाइम 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चौथे महासचिव बने।
- पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत आईएनएस सतवाहन को 1974 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेडे में शामिल किया गया।
- मेडागास्कर में 1975 में संविधान लागू हुआ।
- स्कॉटलैंड की सीमा के नजदीक लॉकरबी शहर में एक पैन एम का जंबो जेट 1988 में 258 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
- कज़ाकिस्तान की राजधानी अल्मा अता में 1991 में 11 सोवियत गणराज्यों द्वारा राष्ट्रमंडल का गठन।
- नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का 1998 में इस्तीफ़ा।
- गंगनम स्टाइल 2012 में यूट्यूब पर एक अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो बना।

21 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार मान सिंह का जन्म 1550 हुआ।
- बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में जन गाजगणकर्ता सुन्दरलाल शर्मा का जन्म 1881 हुआ।
- छत्तीसगढ़ में 'श्रमिक आन्दोलन' के सूत्रधार तथा 'सहकारिता आन्दोलन' के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 1891 हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव कुर्त वॉल्डहाइम का जन्म 1918 हुआ।
- कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार यू. आर. अनंतमूर्ति का जन्म 1932 हुआ।
- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमचारी श्रीकांत का जन्म 1959 में हुआ।
- वर्ष 2002 बैच के वन सेवा अधिकारी और 2015 में 'रेमन मैग्सेसे पुरस्कार' प्राप्तकर्ता संजीव चतुर्वेदी का जन्म 1974 हुआ।

विशेष आलेख

सांसद भी बिजली चोरी करेंगे तो आम जनता पर क्या असर होगा?

अशोक भाटिया

संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ गुरुवार को यहां दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। देर रात उन पर एफआई की कार्रवाई होने के बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई और बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का लगा जुर्माना ठोक दिया। पुलिस ने बताया कि उनके पिता पर भी बिजली विभाग द्वारा घर के निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है ।बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है। बिजली विभाग ने इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच बुहस्पतिवार सुबह बर्क के आवास पर निरीक्षण शुरू किया था।

बर्क उन लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर को संबल में हुई हिंसा के सिलसिले में भी मामला दर्ज किया गया है। शहर के कोट गर्वी इलाके में अदालत के आदेश पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प में चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। बर्क ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की भी मांग की है।बर्क पर 24 नवंबर को लोगों को भड़काने का आरोप है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा का कारण उनका भड़काऊ भाषण था। रिट याचिका में सांसद ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। उनके वकील के अनुसार, वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्हें प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है। इस बीच, बिजली विभाग के निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में सांसद के पिता के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक (संभल) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सुबह साढ़े सात बजे बिजली विभाग के संतोष त्रिपाठी दीपा सराय में बिजली उपकरणों की जांच कर रहे थे, तभी वह ममलूकुर रहमान बर्क (सांसद के पिता) के घर गए और वहां बिजली उपकरणों की जांच की। इस दौरान ममलूकुर रहमान बर्क ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सरकारी काम में बाधा डाली और कहा कि सरकार बदल जाएगी और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, इसका वीडियो बिजली विभाग ने बनाया है।बिश्नोई ने बताया कि ममलूकुर रहमान बर्क, वसीम, सलमान के खिलाफ नखासा थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संभल के दीपा सराय इलाके में बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास की जांच की। इस दौरान इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिरीष चंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि बिजली विभाग ने दीपा सराय इलाके में सुरक्षित और सुचारू निरीक्षण के लिए पुलिस सहायता मांगी है। फिलहाल निरीक्षण जारी है। निरीक्षण किए जा रहे स्थान के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर एएसपी ने कहा कि यह सांसद का आधिकारिक आवास है, जहां बिजली विभाग जांच कर रहा है। बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सांसद के आवास पर दो-दो किलोवाट के दो कनेक्शन और 10 किलोवाट का सोलर पैनल है। उन्होंने कहा कि हालांकि, उपयोग और उपकरणों के आधार पर आवश्यकता आठ से 10 किलोवाट के बीच होनी चाहिए। सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कासिम जमाल ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि निवास में चार किलोवाट के दो कनेक्शन, 10 किलोवाट का सोलर पैनल और पांच किलोवाट का जनरेटर है। 'सेटअप' में दो 'एयर कंडीशनर', 6-7 'सीलिंग फैन (छत वाले पंखे)', एक रेफ्रिजरेटर और लाइट शामिल हैं। बिल बहुत कम है क्योंकि यहां परिवार के केवल चार सदस्य रहते हैं। सांसद, उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके पिता। विद्युत विभाग का निरीक्षण जारी है क्योंकि अधिकारी अनुमानित खपत के मुकाबले मौजूदा कनेक्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं। इलाके में पुलिस, पीएसी और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों की तैनाती पर अधिवक्ता ने कहा कि यह परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। लम्बे समय से चल रही बिजली चोरी पर इतना सब होने के बाद सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जा रहा है जबकि उनकों हर सुविधा मुफ्त मिलती है । सांसद को सैलरी के साथ अलग-अलग तरह के भत्ते मिलते हैं। अगर सिर्फ भत्तों को जोड़ा जाए तो वो आंकड़ा सैलरी से कहीं ज्यादा होता है। एक सांसद को हर माह 1 लाख रुपए बतौर वेतन मिलते हैं। यह मूल वेतन है।इन्हें हर माह 2 हजार रुपए दैनिक भत्ता, 70 हजार रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60 हजार रुपए कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है। इसके अलावा आवास, निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तीनों टेलीफोनों पर सालाना 1,50,000 फ्री कॉल की जा सकती हैं। किराया मुक्त सरकारी आवास मिलता है। जिसके लिए हर साल 50,000 यूनिट बिजली मिलती है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हथीपगुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

राष्ट्रीय सहारा
पटना • शनिवार • 21 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों का जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए
-चाणक्य

सहयोग और निगरानी

भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों अजित डोभाल और वांग यी के बीच हुई 23 में बैठक में से इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 23 अक्टूबर को बातचीत हुई थी जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बहाल करने पर जोर दिया गया था। डोभाल और वांग ने वार्ता के दौरान विश्वास प्रकट किया कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चार साल तक चले सैन्य गतिरोध से सबक लेना महत्त्वपूर्ण है। दोनों नेताओं ने सीमा पर तनाव के कारण फटरी पर से उतरे अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की। इस बैठक की महत्त्वपूर्ण बात यह भी रही कि भारत और चीन ने

कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा पर नदी सहयोग और नाथूला सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। भारत और चीन के बीच पांच साल के अंतराल के बाद विशेष प्रतिनिधियों की यह महत्त्वपूर्ण बैठक द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के एजेंडे पर आधारित थी। दोनों पक्षों ने निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचा के तहत सीमा विवादों को हल करने पर जोर दिया। लेकिन सीमा विवाद एक ऐसा जटिल मुद्दा है जिसको हल करने की दिशा में दोनों देशों का नजरिया अलग-अलग है। इसको लेकर भारत और चीन के बीच कई चक्र की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन इसे हल करने की दिशा में कभी गंभीर नहीं रहा। चीन चाहता है कि सीमा के मूल मुद्दों को अलग करके द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, जबकि नई दिल्ली का विश्वास है कि सीमा विवाद के मसले जब तक हल नहीं होंगे, आपसी रिश्ते असहज बने रहेंगे। यह मसले कुछ इसी तरह के हैं कि भारत सीमा पर आतंक को रोकने के बाद ही पाकिस्तान से रिश्ते सहज होने की बात करता है। जाहिर है जब तक भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं रहेगी तब तक आपसी रिश्ते भला कैसे सामान्य हो सकते हैं। विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य सहमति की संभावित कमी को इशारा करता है। चीन के वक्तव्य में सर्वसम्मति के छह सूत्रों का उल्लेख किया गया है जबकि भारत की ओर से इस तरह के किसी सर्वसम्मति का हवाला नहीं दिया गया है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे सैन्य गतिरोध से बाहर निकलना और द्विपक्षीय संबंधों को समान स्तर पर बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ाना अच्छे संकेत हैं, लेकिन भारत चीन की सीमा महत्त्वाकांक्षा पर भारत को पैनी नजर रखनी होगी।

अधिकारों की धज्जियां

कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं की भलाई के लिए हैं, न कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने या उन पर हावी होने या जबरन वसूली के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। हिन्दू विवाह को पवित्र प्रथा व परिवार की नींव बताते हुए पीठ ने कहा यह कोई व्यावसायिक समझौता नहीं है। अदालत ने हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों से जुड़ी ज्यादातर शिकायतों में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध व आपराधिक धमकी जैसे अपराधों को शामिल करने की बात भी की। साथ ही कहा यह ऐसी प्रथा है, जिसकी अदालत कई मौकों पर निंदा भी कर चुकी है। पीठ ने महिलाओं को सावधान रहने की बात करते करते

हुए सलाह दी कि आपराधिक कानून के प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इनका गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करती हैं। पीठ वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले को निपटाते हुए कहा, भरण-पोषण कई कारकों पर निर्भर करेगा, न कि पति अपनी पूर्व पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता कितना दे या उसकी आय कितनी है। सुकून वाली बात यह भी है कि इस मामले में अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पुलिस के साथ ही वकील भी अपराध की गंभीरता को बढ़ाने और मामले को भीषण दिखाने के लोभ में अनर्गल आरोप मढ़ने से नहीं चूकते। उक्त मामले में पति अतिसंपन्न की श्रेणी में है। इसलिए बीवी उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप गुजारा-भत्ता पाने का दावा कर रही है। जैसा कि अभी मोटा गुजारा भत्ता मांगने व तलाक के लिए अदालती चक्कर काटने से आजिज आकर बंगलुरु के इंजीनियर की आत्महत्या के बाद लोग काफी गुस्से में हैं। स्थापित कानूनों की आड़ में विवाह जैसे पवित्र बंधन को वसूली का जरिया बनाने की मंशा वालों को सिर्फ हिदायतें ही नहीं दी जानी चाहिए। उनके सलाहकारों, वकीलों व पुलिस के प्रति भी अदालतों को सख्त रवैया अख्तियार करना होगा। गुजरा-भत्ता वसूली का जरिया नहीं है, यह विवाहिताओं को समझाना चाहिए। उन्हें समय रहते अपने स्वाभिमान के साथ ही बमुश्किल मिले इन अधिकारों की धज्जियां उड़ाने से बाज आना चाहिए। करना वास्तव में मजबूर/पीड़ित पत्नियों को न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है।

कटाक्ष/ कबीरदास

शाह तुम डटे रहो!

इसी को कहते हैं, होम करने गए थे, हाथ जलाकर आ गए। बेचारे अमित शाह की क्या गलती थी। वह तो नादां अंबेडकर प्रेमियों को स्वर्ग जाने का सच्चा रास्ता बता रहे थे। एकदम मुफ्त स्वर्ग यात्रा एडवाइज और वह भी बिना मांगे। शुद्ध परोपकार की भावना और उसकी भी इच्छा इतनी उत्कट कि बंदा आ बैल मुझे मार तक के लिए तैयार। पात्र-कुपात्र भी नहीं देखे, लगे समझाने कि अंबेडकर का नाम जपने में कुछ नहीं धरा है, बस इतना ही भगवान का नाम जप लेगा तो स्वर्ग पा लेगा। और हां! मोदी जी का नाम जप लेगा तो यह भूलोक पा लेगा। पर बदले में शाह जी को क्या मिला? मुटौवाज का शोर और माफी से लेकर इस्तीफे तक की मांग! दूसरों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया और अपना इहलोक तक खतरे में डलवा लिया। योगी जी मन ही मन में जरूर हंस रहे होंगे।

पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि शाह जी डिफेंसिव पर क्यों पड़ रहे हैं? छाती ठोक कर कहते क्यों नहीं हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा था? क्या अंबेडकर का नाम लेने से स्वर्ग मिल सकता है? सात जन्म के लिए छोड़ो, एक जन्म के लिए! वल्कि एक जन्म भी नहीं एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी स्वर्ग मिल सकता है? हर्गिज नहीं। कागज में आरक्षण लिखा है, तब भी मामूली लोगों की इस दुनिया में एक मामूली नौकरी तो आसानी से मिलती नहीं है। फिर स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? वहां कम से कम यहां वाला आरक्षण तो नहीं ही चलेगा। वहां तो दूसरा ही आरक्षण चलेगा। आखिर, भगवान जी कोई चुनाव नहीं लड़ना होता है, जो सबको प्रतिनिधित्व का वादा करते फिरेंगे। उनकी गद्दी पक्की है, कोई नाराज होता हो तो हो। और अल्ला वाले अपने अलग स्वर्ग में होंगे, हमारे स्वर्ग में न वो टांग अड़ाने आएंगे और न उनसे बचाने के लिए अंबेडकर वाले सिर पर चढ़ाए जाएंगे। तो सच कहने में क्या डर-स्वर्ग तो भगवान का नाम रटने से ही मिलेगा।

रही बात शाह जी के झलोकी की तो, मोदी जी की दोस्ती बनी रहे, उन पर कोई खरोंच भी नहीं आ सकती है। माफी और इस्तीफे के तो शब्द भी मोदी जी की डिक्शनरी में नहीं हैं। उल्टे सांसदों के साथ हिंसा के इतने मुकदमे लाद दिए जाएंगे, कि माफी की मांग करने वाले खुद माफी मांगते नजर आएंगे!

बाबा साहेब से तल्खियां

कांग्रेस

कमलेश पासवान

भारत के पवित्र संविधान के स्वर्णीम 75 वर्षों की यात्रा बहुत कुछ उतार-चढ़ाव को समेटे हुए है। अगर हम वर्तमान कालखंड को देखें तो भारतीय लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली नरेन्द्र मोदी की सरकार ने संविधान की पवित्रता को बनाए रखते हुए उसे जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमारी सरकार की कार्य पद्धति के कारण संविधान अब केवल न्यायिक दस्तावेज भर नहीं रह गया है अपितु जन आकांक्षाओं की पूर्ति का सबसे सशक्त माध्यम बना है।

इससे इतर व्यापक तौर पर देखें तो जबसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता की कमान संभाली है, लोकतांत्रिक मूल्यों व सिद्धांतों को मजबूती प्रदान की है और बाबा साहेब के विचारों, उनके आदर्शों को हर स्तर पर सम्मान दिया है तथा उसका संरक्षण भी किया है। विगत दिनों संसद में संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष की यात्रा पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा की पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने की। इस चर्चा ने देशवासियों को संविधान के उन अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराया, जिसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी थी। मुझे यह पूरी उम्मीद है कि संविधान पर ऐसी व्यापक, समृद्ध चर्चा पहले कभी नहीं हुई है। यह हमारी सरकार का संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा ही है कि हम देश भर में संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने का बड़ा अभियान चला रहे हैं।

गौरतलब है कि आज बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास ही संविधान, बाबा साहेब, दलित और पिछड़ा विरोधी रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहे जितना बाबा साहेब को लेकर झूठ फैलाने का प्रयास करें, परंतु स्वयं बाबा साहेब ने ही कांग्रेस को लेकर ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होना आत्मघाती होगा।' बाबा साहेब कांग्रेस की कुनीति, कुरीति और कुंठित मानसिकता को बहुत पहले समझ गए थे। उल्लेखनीय होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी की नेहरू सरकार की कैबिनेट से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने दलित और पिछड़ा वर्ग के संबंध में सरकार के रवैये के कारण आजीवन कांग्रेस का विरोध किया, वही कांग्रेस पार्टी आज खुद को ऐसा प्रचारित कर रही है जैसे बाबा साहेब की सबसे बड़ी समर्थक वही है। बल्कि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने हर मौके पर बाबा साहेब को अपमानित करने का पाप किया है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो

बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व को कमतर करने की कोशिश की है। एक परिवार के लिए 'भारत रत्न' समर्पित कर देने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब अंबेडकर को 'भारत रत्न' देने का विचार कभी आया ही नहीं। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न की हकदार नहीं मानती थी?

यही नहीं बाबा साहब संसद तक कैसे न पहुंच सके, इसके लिए अनेकों षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस अचानक उनकी सबसे बड़ी हिमायती बनने का ढोंग कर रही है। दिल्ली में एक परिवार के सभी सदस्यों की समाधि बनी हुई, पर क्या कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए कोई समाधि या स्मारक बनाना जरूरी नहीं समझा? ये कांग्रेस की बाबा साहेब को लेकर नफरत भरी मानसिकता का बड़ा प्रमाण है। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर जी को उचित सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहेब की स्मृतियों से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में निर्माण, दिल्ली में विश्वस्तरीय अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सहित उनसे जुड़े स्थलों को विकसित कर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं पिछड़े वर्गों के उत्थान पर केंद्रित मंडल कमीशन से लेकर काका कालेलकर की रिपोर्ट को अटकाने में भी सबसे अग्रणी कांग्रेस पार्टी रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंडल कमीशन और ओबीसी आरक्षण के खिलाफ 6 नवम्बर, 1990 को लोक सभा में ढाई घंटे का भाषण दिया था और यही लोग आज पिछड़ा वर्ग के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। मगर, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी, तब जाकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

संविधान की प्रति को अपनी जेब में लेकर घूमने वाली कांग्रेस की सरकारों की नीयत कभी 'संविधान दिवस' जैसा कुछ मनाने की थी ही नहीं। देश में 'संविधान दिवस' मनाने की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने की। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश पर आपातकाल थोपकर अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान की आत्मा पर हमला किया हो, जिन्होंने 90 से ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बरर्खास्त कर दिया हो और जो कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कहते हैं कि, 'अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए।' ऐसे लोग 'संविधान रक्षक अभियान' मना रहे हैं, यही सबसे बड़ी विडम्बना है। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान और बाबा साहब को कभी उचित सम्मान देना उचित नहीं समझा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इसमें बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखा गया है। बाबा साहेब ने समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित भारत की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया है। चाहे गरीबों के लिए 'आयुष्मान भारत' जैसी स्वास्थ्य योजनाएं हों, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य हो, 'स्टैंड अप इंडिया' और 'मुद्रा योजना' जैसी योजनाओं के माध्यम से हाशिये पर खड़े समुदायों को सशक्त बनाना-इन सबके केंद्र में बाबा साहेब की समानता और गरिमा के आदर्श हैं।

(लेखक केंद्रीय प्रायोग विकास राज्यमंत्री हैं। विचार निजी हैं)

> प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इसमें बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखा गया है। बाबा साहेब ने समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित भारत की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया है

देश में 224 बड़े बांध सौ साल से ज्यादा पुराने

- भारत में 1065 बड़े बांध हैं, जो 50 से 100 साल पुराने हैं जबकि 224 बांध ऐसे हैं जो एक सदी से ज्यादा पुराने हैं
- जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक, देश में कुल 6,138 निर्मित और निर्माणाधीन बांध हैं
- पुराने बांध से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने और बांध की विफलताओं से उत्पन्न होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 लागू किया गया है
- सिंचाई और बिजली उत्पादन उद्देश्यों के अलावा बाढ़ पर रोक लगाने में बांध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

स्रोत : राज्य सभा में दी गई जानकारी

क्या भारत तनाना रिपब्लिक तनता जा रहा है? जिस किसी को भी संसद में और संसद के बाहर नाटकीय-और अर्ध-उम्मीदी हरकतें देखने को मिलेंगी वह ऐसा ही सोचेगा। कहा नहीं जा सकता कि भारतीय राजनेता कितना गिर सकते हैं।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

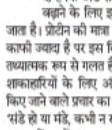

मुद्दा

रजनीश कपूर

क्या अंडे शाकाहार हैं

विज्ञापन जगत ने आम जनता के मन में एक बात बिठा दी है कि अंडे शाकाहारी नहीं हैं। अंडे का उपयोग बढ़ाने के लिए इसे प्रोटीन का बढ़िया स्रोत बताया जाता है। प्रोटीन की मात्रा बहुत सारी शाकाहारी चीजों में भी काफी ज्यादा है पर इस विवाद में नहीं भी पड़ा जाए तो यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि अंडा शाकाहारी है। इसलिए शाकाहारियों के लिए अंडे को लोकप्रिय बनाने के लिए किए जाने वाले प्रचार का उल्टा नारा लगाया जा सकता है - 'संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे'। कोई क्या खाए और क्या नहीं इसमें बहुत कुछ आदमी की अपनी पसंद और जीवनशैली के साथ-साथ कई अन्य बातों पर निर्भर करता है। फिर भी आप जो चीज खाते हैं या किसी कारण से नहीं खाते हैं उसके बारे में आपको आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100 ग्राम अंडों में जहां 13 ग्राम प्रोटीन होगा, वहीं पनीर में 24 ग्राम, मूंगफली में 31 ग्राम, दूध से बने कई पदार्थों में तो इससे भी अधिक एवं सोयाबीन में 53 ग्राम प्रोटीन होता है। यही तथ्य कैलोरी के बारे में है। जहां 100 ग्राम अंडों में 173 कैलोरी, मछली में 93 कैलोरी व मुर्गे के गोश्त में 194 कैलोरी प्राप्त होती है, वही गेहूं व दालों में 300 कैलोरी, सोयाबीन में 350 कैलोरी व मूंगफली में 550 कैलोरी और मक्खन निकले दूध एवं पनीर से लगभग 350 कैलोरी प्राप्त होती है तो हम यह निर्णय ले सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या चीज जरूरी है? यह स्पष्ट करना भी उचित रहेगा कि अधिक कोलेस्ट्रोल शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। 100 ग्राम अंडों में कोलेस्ट्रोल की मात्रा 500 मिलीग्राम है और मुर्गी के गोश्त में 60 है तो वही कोलेस्ट्रोल सभी प्रकार के अन्न, फलों, सब्जियों आदि में शून्य है। अमेरीका के विश्वविख्यात विशेषज्ञ डॉ. माइकेल कलेपर का कहना है कि अंडे का पीला भाग विश्व में कोलेस्ट्रोल एवं जमी चिकनाई का सबसे बड़ा स्रोत है जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्होंने यह भी साबित किया है कि जो व्यक्ति मांस या अंडे खाते हैं उनके शरीर में 'रिसप्टरों' की संख्या में कमी हो जाती है जिससे रक्त के अन्दर कोलेस्ट्रोल की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे हृदय रोग शुरू हो जाता है और गुर्दे के रोग एवं पथरी जैसी बीमारियों को भी बढ़ावा मिलता है। वास्तविकता यह है कि 1962 में यूनीरोफ ने एक पुस्तक प्रकाशित की तथा अंडों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनिषेचित (इनफर्टाइल) अंडों को शाकाहारी अंडे (वेजीटेरियन) जैसा मिथ्या नाम देकर भारत के शाकाहारी समाज में भ्रम फैला दिया। 1971 में

मिशिगन यूनीवर्सिटी (अमेरिका) के वैज्ञानिक डॉ. फिलिप जे. स्केन्ट ने यह सिद्ध किया कि: अनिषेचित अंडे किसी भी प्रकार से शाकाहारी नहीं होते क्योंकि वे न तो पेड़ों पर उगते है और न किसी पौधे पर बल्कि वे सब मुर्गी के पेट में से ही उत्पन्न होते है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर यह देखा गया है कि विद्युत धारा के द्वारा अंडों को आंका जा सकता है। अनिषेचित अंडे में निषेचित अंडे की भांति ही यह विद्युत धारा होती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि निर्जीव वस्तु में कभी भी विद्युत धारा का अंकन नहीं किया जा सकता। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी प्राणी के जीवन का आधार मात्र लैंगिक प्रजनन क्रिया ही नहीं है बल्कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा भी जीवन हो सकता है जैसे अमीबा और अनेक एककोशीय प्राणी बिना निषेचन क्रिया के उत्पन्न होते रहते हैं। इसी प्रकार से 'रेलट ट्यूब बेबी' या उसके द्वारा उत्पन्न प्राणी निर्जीव नहीं गिने जा सकते। सच्चाई यह है कि अंडे दो प्रकार के होते हैं एक वे जिनसे बच्चे निकल सकते हैं तथा दूसरे वे जिनसे बच्चे नहीं निकलते। मुर्गी यदि मुर्गे के संसर्ग में न आए तो भी जवानी में अंडे दे सकती है। इन अंडों की तुलना स्त्री के उत्स्राव से की जा सकती है। जिस प्रकार स्त्री के मासिक धर्म होता है। उसी तरह मुर्गी के भी यह धर्म अंडों के रूप में होता है। यह अंडा मुर्गी की आंतरिक गंदगी का परिणाम है। मुर्गियां जो अंडे देती हैं वे सब अपनी स्वेच्छा से या स्वभावतया नहीं देतीं। बल्कि उन्हें विशिष्ट हार्मोन्स और एग-फर्मयुलेशन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन इंजेक्शनों के कारण ही मुर्गियां लगातार अंडे दे पाती हैं। अंडे के बाहर आते ही उसे इन्क्यूबेटर (सेटर) में डाल दिया जाता है ताकि उसमें से 21 दिन की जगह 18 दिनों में ही चूजा बाहर आ जाए।

मुर्गी का बच्चा जैसे ही अंडे से बाहर निकलता है नर तथा मादा बच्चों को अलग-अलग कर लिया जाता है। मादा बच्चों को शीघ्र जवान करने के लिए एक खास प्रकार की खुराक दी जाती है और इन्हें चौबीसों घंटे तेज प्रकाश में रखकर सेने नहीं दिया जाता ताकि ये दिन रात खा-खा कर जल्दी ही रजःस्राव करने लगें और अंडा देने लायक हो जाएं। अब इन्हें जमीन की जगह तंग पिंजरों में रख दिया जाता है। इन पिंजरों में इतनी अधिक मुर्गियां भर दी जाती हैं कि वे पंख भी नहीं फड़फड़ा सकतीं। तंग जगह के कारण आपस में चोंचें मारती हैं, जख्मी होती हैं, गुस्सा करती हैं व कष्ट भोगती हैं। जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडा जाली में से किनारे पड़कर अलग हो जाता है और उसे अपनी अंडे सेने की प्राकृतिक भावना से वंचित रखा जाता है ताकि वह अगला अंडा जल्दी दे। जिंदगी भर पिंजरे में कैद रहने व चल फिर न सकने के कारण उसकी टांगे बेकार हो जाती हैं। जब उसकी उपयोगिता घट जाती है, तो उसे कत्लखाने भेज दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त अंडे अहिंसक व शाकाहारी कैसे हो सकते हैं?

ध्यानाभ्यास

संत राजिन्दर

ध्यानाभ्यास की पुरातन परंपरा आधुनिक काल के लोगों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। आज लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत अधिक तनाव झेलते हैं, और आज संपूर्ण विश्व को भी कोई न कोई समस्या घेरे ही रहती है। जब लोग किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो उनमें से कई तो इतना अधिक निराश हो जाते हैं कि वे अपने दर्द को भुलाने के लिए शराब या अन्य मादक पदार्थों का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन इससे उल्टा वे अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं या अपनी मृत्यु के निकट होते हैं। वे लोग आत्मिक तकलीफ से गुजरने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इस संसार से जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। जिस परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला जाता है, वे भी कष्ट से गुजरते हैं और यही सोचते रहते हैं कि वो इंसान कहां चला गया है। पूरी दुनिया में सभी लोग कभी न कभी आर्थिक संकट से भी गुजरते हैं। सच तो यह है कि जीवन की समस्याओं को कोई अंत नहीं। हालांकि ध्यानाभ्यास हमारी बाहरी समस्याओं का खात्मा नहीं करता, लेकिन वो हमें एक ऐसे स्थान में अवश्य ले जाता है जहां हम उन समस्याओं के कष्टदायी प्रभावों को महसूस नहीं कर पाते। ध्यानाभ्यास करने से हम प्रेम, परमानंद और खुशियों से भरपूर ऐसे मंडलों में पहुंच जाते हैं। बाद में जब हम ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं, तब हम उस आनंद को दिन भर अपने अंतर में अनुभव कर पाते हैं। ध्यानाभ्यास हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सहायता करता है, जिसमें हम जान जाते हैं कि बाहरी जीवन के संघर्ष केवल अस्थाई होते हैं, और यह कि हमारे अंतर में स्थाई खुशियों और शांति से भरपूर एक ऐसा स्थान है जहां हम जब चाहे जा सकते हैं। गैलप मतदान के अनुसार, विश्व भर में एक करोड़ तीस लाख लोगों ने कहा है कि वे 'नियर-डैथ एक्सपीरियंस' या मृत्यु-सम अनुभव से गुजरे हैं, जिसमें वे ऑपरेशन टेबल पर, या किसी दुर्घटना में, मृत घोषित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। उन लोगों ने बताया कि जिस अवधि में वे मृत घोषित थे, उस समय वे अपने शरीर से बाहर आ गए।

रीडर्स मेल

गरिमा गिराने वाला कृत्य

जो कुछ भी संसद में घटा वह बेहद शर्मनाक है और उसकी जितनी निंदा हो वह काम ही होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपस में नोकझोंक और मुद्दों पर असहमति तो सामान्य बात है, लेकिन नौबत धक्का-मुक्की और दो सांसदों के अस्पताल पहुंचने की आ जाएगी वह किसी ने न सोचा था। और दुःख की बात यह है कि जब प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने भाजपा सांसद प्रताप सारंगी को घायल अवस्था में देखा तो उनसे हालचाल पूछने और अस्पताल ले जाने के पूछने के बजाय मुंह मोड़ कर वापस चले गए। अहंकार का इससे बड़ा उदहारण और क्या होगा? पहले कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को काट छांट कर दिखाया और यह प्रस्तुत किया की जैसे अमित शाह ने संविधान के जनक बाबा साहब अंबेडकर की आलोचना की और उसके बाद धक्का-मुक्की पर उतर आए। और तो और शाम को जब राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की उसमें भी अदाणी का तो जिक्र करते रहे, लेकिन संसद के बाहर हुए घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी और दुख जाहिर नहीं किया। संसद की गरिमा बनाए रखने में हर सांसद की भूमिका है और चूंकि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनकी बड़ी भूमिका बनती है।

बाल गोविंद, ई मेल से

दिखाना होगा संयम

बांग्लादेश के साथ भारत के बिगड़ते रिश्तों का दीर्घकालिक संदर्भ बनता दिख रहा है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग अपने देश की पहचान 1971 के संदर्भ में देखने के बजाय 1947 के संदर्भ में देखने लगे हैं और यह बात देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनुस संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कह चुके हैं। उन्होंने कहा बांग्लादेश बना, क्योंकि लोगों को उदारवाद, बहुलवाद एवं धर्मनिरपेक्षता में गहरा यकीन था। दशकों बाद अब नई पीढ़ी उन उसूलों पर पुनर्विचार कर रही है। लोग 1947 की तरफ लौट रहे हैं, भारत का मजहबी आधार पर विभाजन हुआ। अब चूंकि बात मुस्लिम पहचान पर आ गई है, तो स्वाभाविक नतीजा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के समान अधिकार की आकांक्षा पर चोट की जा रही है। बांग्लादेश से आ रही यह चुनौती बेहद गहरी है, जिसका मुकाबला संयम और दूरदर्शिता के साथ ही किया जाना आवश्यक है।

मनोज श्रीवास्तव, आरा

विश्व ध्यान दिवस का महत्त्व

21 दिसम्बर को पहला 'विश्व ध्यान दिवस' मनाया जा रहा है। भारत द्वारा सह-प्रायोजित एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसम्बर को 'विश्व ध्यान दिवस' घोषित किया है। विश्व ध्यान दिवस न केवल ध्यान की महत्ता को रेखांकित करता है बल्कि मनुष्य के भीतर शांति, प्रेम और करुणा के विकास का भी प्रतीक है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ध्यान के महत्त्व के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों को इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। यह दिन मनुष्य को मानसिक तनाव, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पाने के लिए ध्यान के अभ्यास की ओर प्रेरित करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने संबंधों में सुधार, कार्यक्षमता में वृद्धि और जीवन में संतुलन स्थापित कर सकता है।

श्वेता गोयल, दिल्ली
letter.editorsahara@gmail.com

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजमी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, गौआ-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-सदर, गाजीपुर, पटना से मुद्रित तथा भगवान तल, सहारा इण्डिया बिल्डिंग, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना से प्रकाशित।
: समूह संपादक - डॉ. विजय राय: स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6514
आर.एन.आई. नं. बीआईएसएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

जाति गणना

विवादास्पद विषय

जाति गणना एक विवादास्पद विषय है, हालांकि इससे हाशियाकृत समुदायों के उत्थान की आशा भी की जा सकती है। भारत में जाति गणना का विषय लगातार विवादों का कारण बन गया है जिससे देश का जटिल सामाजिक-कानूनी ढांचा स्पष्ट होता है। इसके समर्थकों का कहना है कि यह विकास और नीति-निर्माण के लिए जरूरी है, पर आलोचकों ने इससे सामाजिक विभाजन और गंभीर होने का खतरा जताया है। दोनों पक्षों के तर्कों से जहां इसके कुछ महत्व उजागर होते हैं, वहीं चुनौतियां भी स्पष्ट होती हैं। जाति गणना का अर्थ जनसंख्या में जातीय संरचना का डेटा व्यवस्थित रूप से एकत्र करना है। भारत में 1931 के बाद ऐसा समग्र प्रयास नहीं हुआ है, हालांकि जाति देश में सामाजिक-आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व बनी हुई है। जाति गणना के पैरोकारों का तर्क है कि यह खासकर ऐतिहासिक रूप से हाशियाकृत समुदायों का समतापूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी-राम विलास के नेता चिराग पासवान ने संकेत किया है कि जातियों की संख्या पर सटीक डेटा समुदाय-आधारित विकास परियोजनाओं के लिए विकास योजनायें बनाने तथा उनके लिए फंड आवंटित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पासवान द्वारा जाति गणना का समर्थन व्यावहारिक है। लेकिन उन्होंने एक सावधानी बरतने की बात भी कही है। हालांकि, सरकार को ऐसा डेटा एकत्र करना चाहिए, पर उसे सार्वजनिक करने से 'जातीय पहचान' मजबूत हो कर सामाजिक विभाजन गहरे हो सकते हैं।

जाति गणना से विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर डेटा मिल जाएगा। यह सूचना प्रभावी सकारात्मक नीतियां और कल्याण कार्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्यायों तथा व्यवस्थित पृथक्करण के कारण हस्तक्षेप जरूरी हो गए हैं। जाति गणना से आरक्षण नीतियों के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी और इससे पता चलेगा कि उनके इच्छित परिणाम निकले हैं या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष ने जोर दिया है कि जाति गणना सामाजिक न्याय का वादा पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। जनसंख्या संरचना की सटीक समझदारी से सरकारें समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा संसाधनों का तदनुसार आबंटन सुनिश्चित कर सकेंगी। लेकिन इसके साथ ही जाति गणना का डेटा सार्वजनिक करने से 'जातीय चेतना' में बढ़ोत्तरी होगी जिससे सामाजिक विघटन तेज हो सकता है। भारत का सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पहले से ही 'पहचान आधारित विभाजनों' का खतरा उठा रहा है, ऐसे में डेटा के दुरुपयोग से विभाजक रेखायें और गहरी होने का जोखिम बढ़ेगा। यह आशंका और भय उचित है कि जाति गणना का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए हथियार की तरह हो सकता है। ऐसे में असमानताओं को संबोधित करने के बजाय यह डेटा जाति-आधारित लामबंदियों, चुनावी रणनीतियों तथा टकरावों को भी बढ़ावा देगा। जाति गणना का कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू करने के पहले इस आयाम पर भी गौर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, जाति गणना एक व्यापक लाजिस्टिक चुनौती है। ऐसे में डेटा संग्रह और उसके वर्गीकरण की सटीकता अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस मामले में कोई गलती विवादों को बढ़ावा देगी तथा इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकती है। जाति गणना आवश्यक है और इसे किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह सटीक हो तथा संभावित चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

बांग्लादेश मुक्ति दिवस की विरासत

बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने वाला विजय दिवस स्वतंत्रता के उत्सव के साथ ही लोकतांत्रिक व समावेशी आकांक्षाओं को सुरक्षित रखने की चुनौतियां भी स्पष्ट करता है।

संतोष पैय्यू
(लेखक,सह प्रोफेसर हैं)

विजय दिवस का बांग्लादेश के लिए अत्यधिक महत्व है। यह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेनाओं पर विजय तथा बांग्लादेश की मुक्ति याद दिलाता है। हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला विजय दिवस एक संप्रभु राष्ट्र के जन्म तथा आत्मनिर्णय के लिए चले लंबे संघर्ष में विजय का प्रतीक है। इसमें भारत ने केन्द्रीय भूमिका निभाई थी और उसने दक्षिण एशिया में नवीनतम राष्ट्र को जन्म देने में जननी वाली भूमिका अदा की थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम न केवल सीमाओं पर चल रहे टकराव को समाप्त होने तक सीमित था, बल्कि इसके क्षेत्र की भू-राजनीति पर पारिभाषिक परिणाम भी सामने आए थे।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जड़ें पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की व्यवस्थित अनदेखी तथा शोषण में निहित थीं। दशकों से व्याप्त आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक दमन व राजनीतिक अधिकारों से वंचना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में एक सशक्त आंदोलन की नींव डाली जो स्वायत्तता की मांग कर रहा था।

इस अन्याय की चरम परिणति 25 मार्च, 1971 को सेना द्वारा बर्बर नरसंहार के रूप में सामने आई। 'आपरेशन सर्चलाइट' ने आतंक का एक नया अध्याय खोला जिसमें लाखों लोगों की आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे जनता का प्रतिरोध और तेज हो गया। अवामी लीग के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान इस प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उनके नेतृत्व ने बंगाली जनता को एकजुट कर दिया और स्वतंत्रता का उनका आह्वान लाखों लोगों के दिलों में गूंजने लगा जो बर्बर दमन से अपनी मुक्ति चाहते थे।

इस टकराव के कारण लाखों लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए जिससे असाधारण स्वरूप का मानवीय संकट पैदा हो गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का हस्तक्षेप एक रणनीतिक व नैतिक निर्णय था। भारतीय सशस्त्र बलों ने मुक्ति वाहिनी के समन्वय से काम करते हुए एक संयुक्त कार्रवाई की जिसने केवल 13 दिनों के भीतर पाकिस्तानी बलों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। 16 दिसंबर, 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण भारतीय इतिहास का एक सर्वाधिक शानदार क्षण है।

लेफ्टीनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में पाकिस्तानी जनरल एएके नियाजी द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर की छवि दोनों देशों की सामूहिक चेतना में महत्वपूर्ण स्थान पर है। इससे न केवल बांग्लादेश की मुक्ति हुई, बल्कि यह द्विराष्ट्र सिद्धान्त के लिए बड़ा धक्का था जिसने 1947 में भारतीय उप-महाद्वीप का विभाजन कर दिया था। बांग्लादेश के जन्म की दुनिया भर में प्रशंसा हुई, पर इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को भी उजागर कर दिया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी कीसिंजर शीतयुद्ध परिस्थितियों के कारण पाकिस्तान के कट्टर समर्थक थे, लेकिन बांग्लादेश की मुक्ति से वे भौचक्के रह गए। दक्षिण एशिया के बारे में निक्सन की कुख्यात टिप्पणी अब भी लोगों को याद है। उन्होंने इसे 'अंतरराष्ट्रीय टोकरी वाला मामला' कहा था। इससे उनके मन में नए राष्ट्र के प्रति पैदा संदेह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है।

> **सालों तक प्रभुत्व बनाए रखने के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार का तख्तापलट देश में एक खाली स्थान का कारण बना है।**

इसके बावजूद बांग्लादेश ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भरता और प्रगति की ओर अपनी यात्रा शुरू की। पिछले पांच दशकों से अधिक समय में बांग्लादेश पूरी तरह से बदल गया है और वह 'दुनिया की गारमेंट फैक्ट्री' कहा जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं तथा ढांचागत कमियों जैसी शुरुआती चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश एक शानदार आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर चला। आज बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश बन गया है और उसकी जीडीपी वृद्धि दर अक्सर पड़ोसियों से आगे निकल जाती है। इस देश ने खासकर जेंडर समानता, शिक्षा और स्वास्थ्यरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक टिकाऊ विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता पाई है।

यह उपलब्धि प्रशंसनीय है। यह अन्य विकासशील देशों के लिए माडल बन गया है जो प्रदर्शित करता है कि मानव विकास पर ध्यान केन्द्रित करने तथा रणनीतिक नियोजन से टिकाऊ प्रगति हो सकती है। विजय दिवस न केवल अतीत की विजयों का समारोह है, बल्कि यह भावी चुनौतियों तथा अवसरों की याद भी दिलाता है। दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य 1971 से बहुत विकसित हुआ है। हालांकि, भारत के साथ संबंध मजबूत बने हुए हैं जिसका कारण ऐतिहासिक संबंध तथा परस्पर हित हैं। बांग्लादेश ने चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव' में शामिल होने का फैसला भी किया है। इससे वह अधिकतम आर्थिक लाभ के लिए विदेश नीति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

विजय दिवस उन बलिदानों को याद करने का समय है जिन्होंने बांग्लादेश को मुक्त कराने में अपना जीवन अर्पण कर दिया। इस युद्ध में असंख्य स्वतंत्रता सेनानी एवं नागरिकों ने अपना बलिदान दिया। उन्होंनें अपनी वीरता और दृढ़ता से नये राष्ट्र की नींव रखी। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम ने गहरी स्मृतियां भी छोड़ीं जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा किए बर्बर अत्याचार शामिल हैं जो लोगों को अभी भी झकझोर देते हैं।

युद्ध अपराध ट्राइब्यूनलों के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा मुक्ति संग्राम की स्मृतियां याद रखने का संघर्ष भी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तथा विजय दिवस की महत्वपूर्ण विरासत है। बांग्लादेश इस समय एक और विजय दिवस मना रहा है। ऐसे में उसे एक राष्ट्र के रूप में उन उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए जिसने उसे दुनिया भर में उल्लेखनीय प्रगति की राह पर पहुंचाया है। शेख मुजीबुर रहमान तथा मुक्ति वाहिनी के सपने अनेक प्रकार से पूरे हुए हैं जिनमें जीवन्त लोकतंत्र, फलती-फूलती अर्थव्यवस्था तथा सक्रिय जनसंख्या शामिल हैं। लेकिन बांग्लादेश में हालिया अस्थिरता ने देश की प्रगति पर काली छाया छोड़ी है।

सालों तक प्रभुत्व बनाए रखने के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार का तख्तापलट देश में एक खाली स्थान का कारण बना है। इसके कारण बांग्लादेश में लगातार अनिश्चितता, अशांति और हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत गहरा हुआ है जिसके कारण लोकतंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों व खासकर हिंदुओं तथा आदिवासी समूहों की स्थिति पर भयानक संकट मंडरा रहा है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव तथा अल्पसंख्यकों व खासकर हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश में सामाजिक ढांचा तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्त बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा समावेशन पर जोर देना बहुत जरूरी है। विजय दिवस की वार्षिकी हमें उन लोगों की अदम्य इच्छाशक्ति याद दिलाती है जिन्होंने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष किया तथा अनेकानेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विजय पाई। विजय दिवस स्वतंत्रता के उत्सव के साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना बलिदान दिया तथा भविष्य में अपने सपने पूरे करने की कसम खाई। बांग्लादेश की कहानी एक युद्धग्रस्त नवोदित राष्ट्र से फलती-फूलती अर्थव्यवस्था बनने की कहानी है। इस प्रकार वह दुनिया के लिए दक्षिण एशिया में उम्मीदों और आकांक्षाओं का केन्द्र बना हुआ है।

मजबूत होते भारत-श्रीलंका संबंध

> **जीवन और मृत्यु नवीनीकरण के एक शाश्वत चक्र में गुंथे हुए हैं, जो आत्मा को विकास के अवसर प्रदान करते हैं।**

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भारत ने इस सप्ताह अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, जिससे इस द्वीप राष्ट्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति, महामहिम श्री अनुरा कुमार दिसानायका ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद नई दिल्ली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा की। इस वर्ष की शुरुआत में, राष्ट्रपति दिसानायका ने भी ऐसे समय में दिल्ली का दौरा किया था, जब श्रीलंका का राजनीतिक भविष्य, जिसमें उसके चुनावों का समय भी शामिल था, अभी भी अनिश्चित था। नए राष्ट्रपति वामपंथी पार्टी के सहारे सत्ता में आए, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने अतीत में कुछ भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया है। हालांकि, नई दिल्ली ने अपरिपक्व युवा मार्क्सवादी नेता पर दांव लगाना चुना, ताकि भविष्य में विवेक की भावना की उम्मीद की जा सके। दिसानायका अतीत में भारत और चीन के साथ श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों में एक अच्छा संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, और किसी भी तरह की गोलीबारी में फंसने की कोशिश नहीं की है।

इस बीच, जबकि हाल के दिनों में चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव में कमी आई है, फिर भी वह सतर्क रहना पसंद करता है। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने भी इस सप्ताह बीजिंग में अपने आपसी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। ऐसा लगता है कि जनवरी में ट्रम्प प्रशासन के ओवल ऑफिस में वापस आने के बाद, चीन उन देशों के साथ सैन्य तनाव कम करना चाहता है, जिन्हें वह अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है।

चीन को पता है कि ट्रम्प अमेरिका को उसके कई निर्यातों पर टैरिफ लगा सकते हैं और शायद अमेरिका से उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को और सख्त कर सकते हैं। यह अच्छी तरह से जानता है कि भारत तब तक आर्थिक बातों में शामिल नहीं होगा, जब तक कि व्यापक सैन्य मुद्दों को सुलझा नहीं लिया जाता। इसी पृष्ठभूमि में, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह याद किया जा सकता है कि चीन ने अतीत में श्रीलंकाई जलक्षेत्र में जासूसी जहाज (जिसे वह समुद्री अनुसंधान वाहन कहता है) भेजे थे, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई खतरे पैदा किए हैं। चीन श्रीलंका के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को भी नियंत्रित करता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी सैन्य संघर्ष के दौरान रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए चीन पर अपने देश की निर्भरता से अवगत हैं, साथ ही, भारत के साथ गहरी द्विपक्षीय साझेदारी को बिगाड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। भारत में नीति पर नजर रखने वालों के लिए यह जानकर खुशी हुई कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने निर्वाचित होने के बाद दिल्ली को अपना पड़ाव चुना और अपने राष्ट्रीय क्षेत्र का इस्तेमाल भारत विरोधी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं करने देने के संबंध में कुछ जोरदार बयान दिए। राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया, भारत और श्रीलंका के साझा सुरक्षा हितों को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित नियमित संवाद और एक-दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देने के महत्व को स्वीकार किया।

भारत श्रीलंका का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी है, राष्ट्रपति दिसानायका ने श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति को दोहराया कि वह अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किसी भी तरह से हानिकारक तरीके से नहीं करने देगा। भारत की सुरक्षा चिंताओं का संज्ञान लेते हुए दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक रूपरेखा समझौते को समाप्त करने की संभावना आपदा न्यूनीकरण, राहत और पुनर्वास पर श्रीलंका की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, जिसमें प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है; और श्रीलंकाई रक्षा बलों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को बढ़ाना और जहां भी आवश्यक हो, अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। इस संबंध का आधार भारत द्वारा श्रीलंका को उदार आर्थिक सहायता देना है, बिना उसे अपारदर्शी, स्वार्थी अल्पसंरचना ऋण के, जिसके कारण द्वीप राष्ट्र के लिए रणनीतिक बंदरगाहों का नुकसान हुआ है।

आप की बात

संसद में ड्रामा

संसद में संविधान पर हुई बहस में जब गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का नाम लेते हुए कांग्रेस पर तंज किया कि वह केवल दिखाने के लिए अंबेडकर का नाम लेती है, पर कांग्रेस को मौका मिल गया। शब्दों के सहारे कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार को घेरने की कोशिश ही धक्का मुक्ति और दुर्व्यवहार तक पहुंच गई। अब बाबा साहेब की विरासत की लड़ाई कहां खत्म होगी, कहना मुश्किल है। भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने है। कितना अच्छा होता है कि दोनों दल विरासत के लिए लड़ने के बजाय बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाते? क्या आज किसी पार्टी के पास अभी तक वंचित दलितों के उत्थान की कोई नई योजना है? जाति-गत जनगणना के मांग को बल मिल सकता है। आरक्षण का अगला चरण शुरू हो सकता है। बीजेपी दलितों के पक्ष में किसी योजना के साथ है सामने आ सकती है। श्री राम मंदिर बनने के बाद कमंडल की राजनीति के बजाय मंडल की राजनीति का ज्यादा जोर रह सकता है। सवाल एक और है इन दोनों बड़े दलों के अलावा ऐसी पार्टियों भी है जो बाबा साहेब का नाम लेकर दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ती रही है। अब इन पार्टियों का रुख क्या होगा? दोनों बड़े दल नहीं चाहेंगे कि बाबा साहेब की विरासत बसपा जैसे दलों के पास लौटे।

– **डॉ हेमंत कुमार**, गोराडीह

भारत पर मेहरबान

अमेरिका ने लम्बी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल को विकसित करने के पाक के कार्यक्रम को अत्यधिक जनहानि होने की संभावनाओं के मद्देनजर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर भारत को अपनी मिसाइल तकनीक के निर्यात सम्बन्धी नियमों संशोधन के संकेत दिए हैं ताकि दोनों के बीच रक्षा सम्बन्धी उद्योगों को बढ़ाने के नए अवसर मिल सकें। पाक पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है कि वो विश्वशांति के लिए खतरे पैदा कर सकता है जबकि भारत पर से तकनीक के निर्यात सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने की बात इसलिए की है कि अमेरिका भी विश्व शांति में विश्वास करता है. बहुत ही सोचनीय बात यह है कि रूस-अमेरिका दोनों एक-दूसरे के विरोधी होने बावजूद भारत के दोनों से संतुलित सम्बन्ध हैं. इसका प्रमुख कारण भारत पर दोनों का विश्वास बढ़ा है. वह इसलिए कि भारत ने हमेशा शान्ति की बात ही दुनिया के पटल पर रखी है. जबकि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण सभी देशों का विश्वास खोता जा रहा है. पाक पर प्रतिबन्ध और हम पर मेहरबान होना एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। पीएम मोदी ने भी अमेरिकी कदम की सराहना की है जबकि पाकिस्तान छाती पीट रहा है।

-**शकुंतला** महेश नेनावा, इंदौर

संसद को अखाड़ा न बनाएं

विगत कई दिनों से विपक्ष संसदीय कार्यवाही में ज़ोर शराबा, नारेबाजी से करोड़ो रूपए खर्च संसदीय कार्यवाही पर गतिरोध बने हैं। और संसद की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष की बौखलाहट का स्वरुप संसद के नए परिसर में देखने को मिला। पहली बार सांसदो के हाथापाई और धक्का मुक्की का माहौल निर्मित हुआ। सांसदो को सिर में चोट आना , आई सी यू में भर्ती होना , और लहू लुहान होना , ईत्यादि। धक्का मुक्की में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर सांसदो द्वारा इशारा है। यही नहीं राहुल गांधी पर एफ आई आर भी की गई। समझ से परे लगता है कि विपक्षी दल के इन नेताओं को क्या हो गया की संसद की गरिमा और मान मर्यादा का बिल्कुल भान नहीं। बच्चों की तरह लड़ाई झगड़े और धक्का मुक्की करके एक दूसरे को चोट पहुंचाना कोन सी महानता है। संसद को अखाड़ा बना कर रख दिया। विदेशों में अगर कार्यवाही और खबरे ऐसी जाती होगी तो क्या तस्वीर भारत की जाती होगी। यह विपक्ष को बिल्कुल भान नहीं। पति मूर्ख इन सफेद पोश नेताओं को विपक्षी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा की यही प्रवृति कांग्रेस को रसातल में ले जा रही है। क्या जनता जनार्दन इनकी ऐसी स्थिति को अच्छा कहेगी? इस कृत्य की जाँच करवाना चाहिए। और दोषी करार दिया जाएं तो कानूनी कार्रवाई सजा भी दी जानी चाहिए।

– **योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

बांग्लादेशी मंत्री की हिमाकत

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम विजय दिवस पर कुछ अतिरेक में नजर आए। भारत पर कब्जे की धमकी के बाद सिरफिरे मंत्री ने फेसबुक पर सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी भारत में रहने वाले लोगों के बीच संस्कृति के आधार पर असंतोष पैदा करने की कोशिश की। फिर विवादित नक्शा जारी किया जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। आलम ने अपनी पोस्ट में पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में लोगों की संस्कृति धर्म से इतर एक जैसी बताई। बेलगाम मंत्री यहां तक लिख गए कि पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के बंगाल विरोधी रवैये के कारण हुआ। महफूज आलम ने दावा किया, भारत ने एक नियंत्रण और यहूदी बस्ती कार्यक्रम अपनाया है। भारत से सच्ची आजादी सुनिश्चित करने के लिए, हमें 1975 और 2024 को दोहराना होगा। ध्यान रहे 1975 और 2024 का संबंध बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या और उनकी बेटी को 2024 में अलोकतांत्रिक तरीके से पीएम पद से हटाने से जोड़ा गया है।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

कल्पमेधा

जो व्यक्ति सत्य के साथ कर्तव्यपरायणता में समर्पण भाव से लीन है, उसके मार्ग में बाधक होना कोई सरल कार्य नहीं है।

- रवींद्रनाथ ठाकुर

गिरावट की मुद्रा

डालर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर कर पचासी से अधिक हो गई। यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपनी नीतियों में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ है। कोरोना के बाद दुनिया के तमाम देश मंदी की चपेट में आ गए थे। उससे उबरने के लिए सभी ने अपने-अपने तरीके से उपाय किए। अमेरिकी फेडरल ने अपनी ब्याज दरों में कटौती कर उसे साढ़े चार फीसद पर ला दिया है। इस तरह डालर की स्थिति मजबूत हुई है। फिर, जब से राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है, निवेशकों को लगने लगा है कि वहां निवेश करना सबसे फायदेमंद है। इसलिए बहुत सारे निवेशकों ने भारत से पैसे निकाल कर अमेरिका का रुख कर लिया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी छीजन दर्ज शुरू हो गई। पिछले कुछ समय तक डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट लगभग रुकी हुई थी, तब विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार से डालर की निकासी करके रुपए की कीमत को रोक रखा है। मगर अब यह तरीका भी शायद काम नहीं आ रहा।

डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट का असर व्यापार, पर्यटन, शिक्षा आदि पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का अधिकतर ईंधन तेल दूसरे देशों से खरीदता है। ऐसे में जब भी कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो सरकार का खर्च बढ़ जाता है। इसके अलावा, दवाइयों के लिए कच्चा माल, खाद्य तेल, इलेक्ट्रानिक साजो-सामान आदि के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। विदेश पढ़ने गए विद्यार्थियों और पर्यटकों की जेब पर बोझ बढ़ जाता है। इसलिए रुपए की कीमत का गिरना चिंताजनक होता है। रुपए की कीमत गिरने की कुछ वजहें साफ हैं। व्यापार घाटा बढ़ता है, तो डालर के मुकाबले रुपए की कीमत घट जाती है। हालांकि वर्षों से निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, घरेलू बाजार और स्वदेशी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, मगर हकीकत यह है कि निर्यात में लगातार कमी देखी जा रही है। व्यापार घाटा पाटने के लिए कई विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने और देसी वस्तुओं को प्रश्रय देने की कोशिश की गई, इसका कुछ असर भी हुआ। मगर फिर भी व्यापार घाटा कम नहीं हो पा रहा। खासकर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है।

महंगाई पर काबू पाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने लगातार रेपो दर को ऊंचा बनाए रखा है, मगर स्थिति यह है कि बाजार में पूंजी का अपेक्षित प्रवाह नहीं बन पा रहा। इसकी बड़ी वजह लोगों की आय में बढ़ोतरी न हो पाना है। इन स्थितियों का असर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पड़ता है। जैसे ही बाहरी निवेशकों को लगने लगता है कि किसी देश में उपभोक्ता व्यय घट रहा है, तो वे वहां निवेश करने से बचते हैं। पिछले कुछ समय से हमारी विकास दर और उसमें विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे में डालर की आवक कम हुई है। इस स्थिति में रुपए की कीमत घटनी शुरू हो जाती है। भारत में यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। सरकार अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डालर तक ले जाने को संकल्पित है, मगर रुपए की गिरावट का रुख देखते हुए इसका भरोसा नहीं बन पाता।

लापरवाही लगातार

किसी भी हादसे का सबक यही होना चाहिए कि वैसी लापरवाहियां न बरती जाएं। हर तरह के सुरक्षात्मक इंतजाम किए जाएं, ताकि दोबारा वैसी त्रासदी न हो। मगर विडंबना है कि एक जैसी दुर्घटनाएं बार-बार हो जाती हैं और बहुस्तरीय लापरवाही कायम रहती है। करीब पांच महीने पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में भारी संख्या में जमा लोगों के बीच भगदड़ मच गई थी। उस घटना की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसमें एक सौ तेईस लोगों की जान चली गई और डेढ़ सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ऐसा नहीं कि वह कोई अकेली घटना थी, जिसमें व्यवस्था में लापरवाही की वजह से लोगों की मौत हुई, बल्कि जब-तब उस तरह के आयोजन होते रहते हैं और उनमें कई तरह की लापरवाहियां हादसे को न्योता देती रहती हैं। जबकि आयोजकों और प्रशासन को यह अंदाजा रहता है कि वहां भगदड़ की संख्या में लोग किसी जगह जमा हो रहे हैं, तो वहां हादसे की आशंका होती है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथावाचक का प्रवचन सुनने एक लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। खबरों के मुताबिक, आयोजन स्थल में प्रवेश द्वार पर फैली अव्यवस्था की वजह से कई महिलाएं गिर गईं। सुर्खियों में आए एक वीडियो में भी कुछ महिलाएं भीड़ में गिरती दिखीं, लेकिन पुलिस का बयान आया कि वहां भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी। गनीमत थी कि कुछ लोगों के तत्काल सक्रिय होने की वजह से अफरातफरी की स्थिति कोई भगदड़ या बड़े हादसे में तब्दील होने से बच गई, वरना जितनी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, उसमें नतीजों का बस अंदाजा लगाया जा सकता है। सच यह है कि पहले हुए ऐसे हादसों के बावजूद, आयोजकों की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते ऐसी स्थिति बनी रहती है। ऐसे में कभी भगदड़ के कारण लोगों की मौत हो जाती है, तो उसके लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहरा कर असली कसूरवारों पर शायद ही कभी सख्त कार्रवाई होती है। नतीजतन, आस्था के नाम पर लाखों लोगों के जुटान के बावजूद सुरक्षा इंतजामों का सवाल आमतौर पर हाशिये पर रहता है।

आभासी संजाल में जकड़ता मासूम मन

अनुसंधान एजंसी 'रेडसियर' के मुताबिक, एक भारतीय हर दिन करीब 7.3 घंटे सोशल मीडिया पर समय गुजारता है। जबकि एक अमेरिकी औसतन 7.1 घंटे और चीनी नागरिक 5.3 घंटे सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं।

सोनम लववंशी

बीते दिनों मध्यप्रदेश के देवास जिले में पंद्रह वर्ष के बच्चे ने सोशल मीडिया पर पटाखे वाली बंदूक बनाने का वीडियो देखा। उसमें बताए गए तरीके से उसने बंदूक बनाई। मगर अचानक उसी बंदूक से गोली चल जाने से उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आठ साल के दो बच्चों ने एक वीडियो देख कर मासूम बच्ची से गलत हरकत की। ये उदाहरण मात्र नहीं, बल्कि हमारे समाज का दुखद सच है। सोशल मीडिया के बेतहाशा इस्तेमाल के कारण बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं। फिर भी न तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध लगाने की नीति बनाई जा रही है और न ही इस पर सामग्री को लेकर कोई विरोध होता दिखाई दे रहा है। अभी हाल में आस्ट्रेलिया की संसद में लाया गया एक विधेयक चर्चा का विषय है। वहां सोलह साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए पहल की जा रही है। यह सराहनीय कदम है। देखा जाए तो सोशल मीडिया बच्चों के बाल मन पर गहरी छाप छोड़ रहा है। यह न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर अपना कुप्रभाव डाल रहा है।

अनुसंधान एजंसी 'रेडसियर' के मुताबिक एक भारतीय हर दिन करीब 7.3 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारता है। अमेरिकी औसतन 7.1 घंटे और चीनी नागरिक 5.3 घंटे सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। भारतीय युवा सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अमेरिका और चीन से बहुत आगे है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और ब्रिटेन में एक युवा जहां सोशल मीडिया के सात मंचों पर मौजूद है, वहीं एक भारतीय युवा करीब ग्यारह मंचों पर मौजूद रहता है। सितंबर 2023 में प्रकाशित एक रपट के मुताबिक 46 फीसद भारतीय बच्चे सोशल मीडिया मंच, ओटीटी और 'आनलाइन गेम्स' का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023' की धारा 9 में अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डेटा इस्तेमाल की शर्तों की बात कही गई है। उसमें अभिभावकों की सहमति, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण में बाल कल्याण निगरानी और लक्षित विज्ञापन पर पाबंदी का जिक्र है। इन सबके बावजूद मासूम बच्चे धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। अगर बाल मन अपराध की दलदल में फंस जाएगा, तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रह पाएगा?

यह सच है कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा असर बच्चों की नींद पर पड़ता है। इससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। इतना ही नहीं, मोबाइल स्क्रीन बच्चों के खाने-पीने के तौर-तरीकों पर भी असर डाल रही है। उनकी घर से बाहर की गतिविधियां कम हो रही हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। सच है कि विज्ञान वरदान है, लेकिन इसकी अति किसी अभिशाप से कम नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि स्मार्ट फोन ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। दुनिया की हर जानकारी पलक झपकते मिल जाती है, लेकिन इस कड़वे सच को भी नकारा नहीं जा सकता कि मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से हम अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। घर-परिवार में संवाद की कड़ियां कमजोर हो रही हैं। खून के रिश्तों में भी भावनात्मक खाई बढ़ रही है। आभासी रिश्ते जोड़ने के चक्कर में वास्तविक रिश्ते दिनों-दिन कमजोर हो रहे हैं, जिसका कुप्रभाव समाज पर साफ देखा जा सकता है।

> बीते माह भारत के 368 शहरों में 70 हजार बच्चों के अभिभावकों पर हुए सर्वे की एक रपट के मुताबिक बच्चों के 'स्क्रीन टाइम' का 61 फीसद समय सोशल मीडिया पर गुजरता है। जबकि 52 फीसद समय आनलाइन गेम में चला जाता है। इसके चलते बच्चों में आक्रामकता का स्तर 58 फीसद तक बढ़ गया है। छोटी-छोटी बातों पर बच्चों का गुस्सा करना और मारपीट पर उतारू होना आम बात हो गई है। जबकि सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के कारण 49 फीसद बच्चे आलसीपन का शिकार हो गए हैं। यहां तक कि बच्चों में मोटापा और मधुमेह भी बढ़ रहा है।

आजकल छोटी उम्र में ही बच्चों में मोबाइल की लत लग रही है। आए दिन अपराध में उनकी संलिप्तता दिख रही है। बच्चे सोशल मीडिया मंच पर न केवल अश्लील वीडियो देख रहे हैं, बल्कि खुद भी 'रील' बना कर डाल रहे हैं। यहां तक कि 'लाइक-कमेंट' का चस्का बच्चों के बाल मन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। अभिभावक तक सस्ती लोकप्रियता के फेर में बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की खुली छूट दे रहे हैं। अभी हाल में अभिनव अरोड़ा के मामले को भला कौन भूल सकता है कि कैसे उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। इस घटना के बाद उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। वैसे यह कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर छोटी उम्र की बच्चियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर घटिया टिप्पणी आम बात हो गई है।

सस्ती लोकप्रियता और कम उम्र में मशहूर होने की ख्वाहिश के कारण बच्चों का सोशल मीडिया के प्रति झुकाव सही नहीं है। बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया की चाहत बच्चों को गहरे मानसिक अवसाद की तरफ धकेल रही है, जो कहीं न कहीं समाज के लिए घातक है। ऐसे में बच्चों को नैतिक संबल देने के साथ उन्हें यह बताने की जरूरत है कि सोशल मीडिया किसी रोग से कम नहीं। इसलिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग ही इसका सही समाधान है।

'कामन सेंस मीडिया' की एक रपट के मुताबिक दस वर्ष की उम्र के करीब 41 फीसद बच्चों के हाथ में स्मार्ट फोन है। जबकि 14 वर्ष तक आते-आते 91 फीसद बच्चे किसी न किसी रास्ते से स्मार्ट फोन की जद में आ जाते हैं। विडंबना है कि भारत मोबाइल फोन के इस्तेमाल में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस बात की फिक्र किसी को नहीं है कि उनके मासूम बच्चे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं। वैसे देखा जाए, तो गलती बच्चों की नहीं है। हमने ही बच्चों को इतना एकाकी बना दिया है कि वे आसानी से किसी से घुल-मिल नहीं पाते हैं। संयुक्त परिवार के अभाव के कारण बच्चों का ज्यादातर समय मोबाइल फोन चलाने में बीतता है। यूनेस्को के मुताबिक मोबाइल फोन का अंधाधुंध इस्तेमाल से बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन में तो कमी आती ही है, उनका मनोबल भी कमजोर होता है।

बीते माह भारत के 368 शहरों में 70 हजार बच्चों के अभिभावकों पर हुए सर्वे की एक रपट के मुताबिक बच्चों के 'स्क्रीन टाइम' का 61 फीसद समय सोशल मीडिया पर गुजरता है। जबकि 52 फीसद समय आनलाइन गेम में चला जाता है। इसके चलते बच्चों में आक्रामकता का स्तर 58 फीसद तक बढ़ गया है। छोटी-छोटी बातों पर बच्चों का गुस्सा करना और मारपीट पर उतारू होना आम बात हो गई है। जबकि सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के कारण 49 फीसद बच्चे आलसीपन का शिकार हो गए हैं। यहां तक कि बच्चों में मोटापा और मधुमेह भी बढ़ रहा है। बच्चे असाध्य रोगों का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तरह हमारे देश में भी कोई ठोस कदम बच्चों को सोशल मीडिया के भंवर जाल से बचाने के लिए उठाया जाता है, तो यह देश के भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए उचित होगा और इससे मासूम बालमन अपराध और अवसाद के अंधकार में फंसने से बच पाएगा।

अहंकार की परतें

चंदन कुमार चौधरी

लोगों में एक आम धारणा है कि प्यासा, कुएं के पास जाता है। कुआं कभी प्यासे तक नहीं जाता। यानी अगर कोई जरूरतमंद है तो मदद उसे ही मांगनी पड़ेगी। मदद देने वाला व्यक्ति उसे मदद देने नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मदद करने वाला व्यक्ति भी खुद प्रस्ताव देता है कि मैं सहायता कर देता हूं, लेकिन ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है, उसे ही सामने वाले से सहायता मांगनी चाहिए।

कई बार समाज में यह भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को सहायता की जरूरत होती है, वह मदद नहीं मांगता है, बल्कि वह उम्मीद करता है कि कोई व्यक्ति खुद आकर उसकी सहायता करे। कुछ अंतर्मुखी और संकोची लोगों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह की सोच की वजह खुद को श्रेष्ठ समझना या घमंड होती है। उसे लगता है कि सहायता मांगने से उसकी तौहीन हो जाएगी। उसके बड़प्पन पर दाग लग जाएगी। ऐसे में वह मदद कैसे मांग सकता है? वह समझता है कि यह सामने वाले का कर्तव्य है कि वह खुद आकर यह प्रस्ताव पेश करे कि आपको जरूरत है और मैं सहायता करता हूं। जब ऐसा नहीं हो पाता है, तो अपने को श्रेष्ठ समझने वाले इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। उसे भले ही नुकसान उठाना पड़ जाए, परेशानी झेलनी पड़ जाए, लेकिन वह फिर भी सहायता मांगने नहीं जाता। मांगने को वह अपना स्वभाव नहीं मानता। इसमें उसको अपनी प्रतिष्ठा दांव लगी दिखती है। क्या इस तरह अभिमान से ग्रस्त लोग ऐसा करके अपना भला करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि घमंड और अकड़ सिर्फ 'मृत शरीर' में हो सकती है। जिंदा इंसान में कभी घमंड नहीं हो सकता। अगर उसमें घमंड है तो समझना चाहिए कि वह इंसान नहीं है। हालांकि यह तथ्य है कि मृत शरीर में जान नहीं होती, इसलिए जीवित व्यक्ति के भीतर घमंड की तुलना मृत शरीर की प्रकृति से नहीं की जा सकती।

ऐसा लगता है कि श्रेष्ठता के भाव के कारण लोगों में दंभ का अंकुर अब धीरे-धीरे विशाल पेड़ बन रहा है। यह समाज की एक जटिल समस्या बनती गई है और ज्यादातर लोग इसके असर में आ रहे हैं। इसका कई स्तर पर नुकसान होता है, मगर लोग इस भाव से अलग नहीं होना चाहते और इससे चिपके रहना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान समय में समाज में कई लोग अहंकार के रथ पर सवार हैं। कोई इस रथ से उतरना ही नहीं चाहता। लोगों को लगता है कि वह सामने वाले से ज्यादा अमीर और प्रतिभाशाली है। साथ ही, उसकी उपलब्धि सामने वाले से कहीं अधिक है। यह संभव हो सकता है कि मगर अभिमान के कारण स्वाभाविक रूप से समाज में ईर्ष्या का प्रादुर्भाव शुरू होता है और लोग एक-दूसरे की तरक्की देख कर जलने लगते हैं, दूसरे को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। शायद यही वजह है कि समाज में आए दिन कई तरह की समस्याएं पनप रही हैं और यह एक-दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं।

हालांकि इस तरह के दंभ से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि फिर भी यह इतना पल्लवित-पुष्पित क्यों हो रहा है? आखिर समाज में यह अभिमान इतना पांव क्यों पसार रहा है? वसुधैव कुटुंबकम् वाले भारत वर्ष में लोगों के मन में इतनी संकीर्णता कहां से आ रही है? तरक्की अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी साथ लाती हैं। तो क्या यह उसका परिणाम है? यह समझना मुश्किल है कि सामाजिक समरसता कहां समाप्त होती जा रही है? यह एक मनोविज्ञान है कि लोगों में अक्सर घमंड श्रेष्ठता के भाव से शुरू होता है। यही श्रेष्ठता की ग्रंथि लोगों को एक-दूसरे से दूर करने लगती है। फिर धीरे-धीरे लोगों के मन में ईर्ष्या पनपने लगती है, लोग दूसरे लोगों को दुख-तकलीफ, समस्या में देख कर खुश होने लगते हैं। पता नहीं, समाज में ऐसा कौन-सा जहर अपनी जगह बना रहा है, जिसके कारण लोगों को दूसरे को दुख-तकलीफ और समस्या में देख कर आनंद की अनुभूति होती है। यह कुंठा नहीं तो और क्या है?

दुनिया मेरे आगे

> तरक्की अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी लाती है। तो क्या यह उसका परिणाम है? यह समझना मुश्किल है कि सामाजिक समरसता कहां समाप्त होती जा रही है? यह एक मनोविज्ञान है कि लोगों में अक्सर अभिमान श्रेष्ठता के भाव से शुरू होता है। यही श्रेष्ठता की ग्रंथि लोगों को एक-दूसरे से दूर करने लगती है।

अक्सर लोग सफाई पेश करने के तौर पर अभिमान को स्वाभिमान की भावना से जोड़ देते हैं जो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होती। यह एक तरह का घालमेल है, जिसमें स्वाभिमान के नाम पर दंभ से लैस अभिमान को छिपाने की एक विफल कोशिश की जाती है। गर्व और घमंड शब्द आमतौर पर एक जैसा ही दिखाई जरूर देता है, हालांकि यो शब्द करीब एक जैसे होकर भी भाव में काफी अंतर रखते हैं। गर्व को जहां हम लोग सकारात्मक तरीके से लेते हैं, वही घमंड को नकारात्मक तरीके से। ऐसे में हमें घमंड को किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर जगह नहीं देना चाहिए। यह याद रखने की जरूरत है कि घमंड से इंसान का कभी भी भला नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम होने की वजह से कभी अभिमान के भाव से भर जाता है तो एक अच्छे नागरिक होने के कारण सहज व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि उसे इस संजाल से बचाए। दरअसल, घमंड एक तरीके का रोग है। इससे जितना दूर रहा जाए मनुष्य के लिए उतना ही अच्छा। इससे मनुष्य और मानवीय संवेदनाएं जीवित रहेंगी।

आपत्ति बनाम आदर्श

भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। 'बाबा साहेब का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान' यह नारा विपक्षी दलों की जुबान पर है। निस्संदेह गृहमंत्री का आंबेडकर के अपमान का इरादा नहीं रहा होगा, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि देश के करोड़ों दलितों को संसद में अनावश्यक संदर्भ पर आपत्ति है और इसे अपमान के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष ने यह मुद्दा जोरदार ढंग से संसद के अंदर और बाहर उठा कर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को सफाई देने पर मजबूर किया है। मगर विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने भी क्या किया? आंबेडकर को अपने शासनकाल में भारत रत्न भी नहीं दिया। जबकि दुनिया को पता है कि बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत और संविधान के निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी। इसी तरह जब लखनऊ और नोएडा में आंबेडकर स्मारक बनाया गया, तो आज जो लोग विपक्ष में हैं, उनके नेताओं ने सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया था। सवाल है कि बाबा साहेब के नाम के बजाय उनके आदर्शों और उद्देश्य को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

निर्विवाद खिलाड़ी

भारत के महान आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के लिए अनिल कुंबले के बाद अश्विन ही सबसे सफल गेंदबाज रहे। 106 टेस्ट मैच खेल कर 537 विकेट लेने वाले अश्विन बहुत अच्छे बल्लेबाज भी है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ छह शतक लगाए हैं। हर मायने में वे मैच जिताने वाले क्रिकेटर रहे। उनको सर्वाधिक 11 बार 'मैन आफ द सीरीज' का सम्मान मिला। वर्ष 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्राफी जीतने वाली भारतीय टीम का सदस्य रहे अश्विन की आलराउंडर कहा जा सकता है। अट्ठाईस वर्षीय रविचंद्रन अश्विन का लंबा क्रिकेट करिअर हमेशा निर्विवाद रहा। कैरम बाल के जादूगर अश्विन ने विदेशों में भी सफलतापूर्वक गेंदबाजी कर कई टेस्ट मैचों में भारत को जीत दिलाई। अब हम सिर्फ आइपीएल में ही अश्विन को खेलते हुए देख पाएंगे।

- अनिल कुमार राय टिकू, धनबाद

खतरनाक मांझा

नव वर्ष के शुरुआती महीने में हम गणतंत्र दिवस समारोह और मकर संक्रांति तथा बसंत पंचमी जैसे प्रमुख त्योहार मनाएंगे। इस अवसर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि राज्यों में खूब पतंगबाजी होती है। पतंगबाजी के शौकीन लोग पतंग उड़ाने के लिए नायलान, प्लास्टिक या अन्य किसी सिंथेटिक सामग्री से बनीं डोर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो चीनी मांझे पर प्रतिबंध है, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो मनुष्यों, पक्षियों, पर्यावरण और विद्युत लाइनों को नुकसान पहुंचाते हैं। दुपहिया वाहनों के लिए तो दुर्घटना का हमेशा अंदेशा बना रहता है। ऐसे मौके पर अक्सर हादसे की खबरें आती हैं। हालांकि सरकार लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल कदम उठाती है। फिर भी लोग ध्यान नहीं देते। अब सभी का कर्तव्य है हम प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल करने से बचें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें, तभी इन त्योहारों का आनंद लिया जा सकता है।

- वेद प्रकाश, गुरुग्राम

मर्यादा के विरुद्ध

कोई भी सत्र हो लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल पा रही है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। क्या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही परिदृश्य है? संसद की कार्यवाही में बाधा डालना क्या सही है। इस तरह की नकारात्मक राजनीति क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं नेता? विपक्षी दलों के नेताओं का व्यवहार भी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। जिन महान नेताओं के प्रतिफल से लोकतंत्र गौरवान्वित है, उनके मान-सम्मान को खंडित करने की राजनीति कहीं घातक सिद्ध न हो। पक्ष-विपक्ष का संयम आखिर क्यों खत्म हो रहा है? हमारे सभी नेताओं ने देश के लिए एकजुटता के साथ काम किया, पर वर्तमान राजनीति में दलों के बीच इतनी खाई क्यों पैदा हो गई। इस पर चिंतन जरूरी है। इस तरह की थक्का-मुक्की का कोई मतलब नहीं है। इस बात की चिंता क्यों नहीं हो रही है कि जनता में क्या संदेश जा रहा है।

- हरिहर सिंह चौहान, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

विक्रांत निर्मला सिंह
प्रोफेसर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

आजकल

पूंजीगत खर्च बढ़ाने से गतिशील होगी आर्थिकी

महंगाई को काबू में रखते हुए आर्थिक वृद्धि को कायम रखना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रह गई, जो पिछली सात तिमाहियों में सबसे कम है। वहीं, आरबीआइ ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया, जिसका मुख्य कारण महंगाई का बढ़ता हुआ स्तर है। लिहाजा पूंजीगत खर्च बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए

भविष्य के रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश से अर्थव्यवस्था को मिल सकती है तीव्र गति। फाइल

भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया अनुमान के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में खुदरा महंगाई पांच प्रतिशत से ऊपर बनी रह सकती है। जीडीपी में गिरावट के बाद यह उम्मीद थी कि ब्याज दरों में कटौती होगी, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि केंद्रीय बैंक ने आर्थिक प्रोत्साहन के बजाय कड़ी मौद्रिक नीति बनाए रखने का फैसला क्यों किया? पिछले 22 महीनों में 11वीं बार रेपो दर को स्थिर रखना न केवल क्रेडिट क्रिएशन (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा नई क्रेडिट राशि का निर्माण या सृजन करना) को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह कई आर्थिक सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या यह निर्णय महंगाई को नियंत्रित रखने के डर से लिया गया है? या इसके पीछे दीर्घकालिक स्थिरता का कोई उद्देश्य है?

यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान में महंगाई की स्थिति घरेलू कारणों से कम और बाहरी कारकों से अधिक प्रभावित है। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय से अस्थिरता बनाए रखी है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, आरबीआइ के पास ब्याज दरों में कटौती करने का एक उपयुक्त अवसर था। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में कमी की है। दूसरी तरफ यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में महंगाई का प्रमुख कारण क्रेडिट सप्लाई में अत्यधिक वृद्धि नहीं है। भारत में क्रेडिट ग्रोथ इस वित्तीय वर्ष में 14-15 प्रतिशत की समान्य दर से बढ़ने की संभावना है।

असल में इसके पीछे अर्थव्यवस्था का गहरा समीकरण है, जो ब्याज दरों और आर्थिक वृद्धि के बीच के सीधे संबंध को दर्शाता है। इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किसे भी देश की अर्थव्यवस्था दो प्रमुख नीतियों- मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति पर आधारित होती है। इन नीतियों के उद्देश्य और कार्यप्रणाली भले ही अलग हों, लेकिन दोनों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। मौद्रिक नीति का मुख्य काम महंगाई को नियंत्रित करना और मुद्रा आपूर्ति को संतुलित रखना है।

लेकिन आर्थिक विकास में ब्याज दरों की भूमिका को लेकर सरकार, संस्थाएं और आर्थिक चिंतक अक्सर केंद्रीय बैंक की ओर देखते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती का सीधा संबंध मनी सप्लाई यानी अर्थव्यवस्था में चलन में मौजूद धन की मात्रा से होता है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम करता है, तो ऋण सृजन (क्रेडिट क्रिएशन) में वृद्धि होती है, जिससे बाजार में अधिक धन प्रवाहित होता है। इसका सकारात्मक प्रभाव खर्च और निवेश पर पड़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है और जीडीपी में सुधार होता है। हालांकि यह वृद्धि अक्सर नामभाव (नोमिनल) जीडीपी में दिखाई देती है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि बढ़ होती है जो महंगाई के प्रभाव से मुक्त होती है।

जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट : भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अब एक और गंभीर चुनौती जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट की है। स्वयं आरबीआइ ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। एसबीआइ की हालिया रिपोर्ट इस दर को और भी कम लगभग 6.3 प्रतिशत तक रहने की आशंका जताती है। एशियाई विकास बैंक ने भी अपने पूर्वानुमान को सात प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारण निजी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती है। खासतौर पर खनन क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक हो चुकी है। हालांकि निजी निवेश में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन यह पहली तिमाही के 7.4 प्रतिशत की तुलना में काफी धीमी है। इसके अलावा, सरकारी निवेश व्यय में 15.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो घरेलू मांग में कमी का एक बड़ा कारण बन रहा है।

वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के निवेश व्यय में बढ़ोतरी निस्संदेह एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। सरकारी निवेश का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि इसका गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफैक्ट) व्यापक और दीर्घकालिक होता है। जब सरकार सड़क, रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा या शहरी विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं में निवेश करती है, तो इसका प्रभाव केवल उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता। यह निवेश संबंधित उद्योगों और सेवाओं को भी प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के तौर पर, हाईवे निर्माण परियोजनाएं सीधे मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को रोजगार प्रदान करती हैं। इसके अलावा, सीमेंट और स्टील जैसे निर्माण सामग्रियों की मांग बढ़ने से इन उद्योगों में भी रोजगार और उत्पादन में तेजी आती है। इसका एक अन्य लाभ यह है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लोगों को आय में वृद्धि होती है, जिससे उनकी खरीद क्षमता बढ़ती है।

लेकिन यहां सवाल यह है कि आर्थिकी को गति देने के लिए सरकारी निवेश को किस दिशा में और कैसे बढ़ाया जाए। क्या घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं पर विचार किया जाए या फिर आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर निवेश किया जाए? नकद हस्तांतरण योजनाएं तात्कालिक रूप से प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक पूंजी निर्माण में सहायक नहीं होतीं। इसके विपरीत, आधारभूत ढांचा परियोजनाएं रोजगार सृजन करती हैं और भविष्य की आर्थिक संरचना को भी मजबूत बनाती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार के पास दोहरी रणनीति अपनाने का विकल्प है। पहला, ग्रामीण मांग को बढ़ाने के लिए किसानों को सम्मान राशि में वृद्धि की जाए, ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े। दूसरा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को एक निश्चित धनराशि हस्तांतरित की जाए, जिससे ग्रामीण मांग में वृद्धि हो और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए।

इसके अलावा, शहरी मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मुख्य रूप से मध्य और निम्न मध्य वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन वर्गों के खर्च का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर जाता है। अगर इनमें से किसी एक क्षेत्र में राहत दी जाए, तो उनकी बचत बढ़ सकती है, जिससे वे अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार एक प्रभावी उपाय हो सकता है। सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों को इसमें शामिल किया है। इसी तरह, एक निश्चित आय स्तर तक के परिवारों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे इस वर्ग का एक बड़ा खर्च बच सकेगा, जो उन्हें अन्य मदों पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान कुल जीडीपी का 4.9 प्रतिशत है, जबकि 2021 में यह 9.2 प्रतिशत था। यानी सरकार के पास अब कई विकल्प खुले हुए हैं। इस संदर्भ में सरकार यदि चाहे तो हर जिले में एक केंद्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव कारगर साबित हो सकता है, जो न केवल पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। ऐसे कदमों के दो प्रमुख लाभ होंगे। पहला, इन परियोजनाओं से पूंजीगत खर्च के माध्यम से रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए शिक्षा-स्वास्थ्य में मजबूत सार्वजनिक ढांचे की जरूरत है। ये संस्थान दीर्घकालिक दृष्टि से राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में काम करेंगे।

(विक्रांत निर्मला सिंह)

रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण

पूंजीगत खर्च पर विचार करते समय यह सवाल उठता है कि क्या सरकार को केवल मौजूदा योजनाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए जैसे भारतमाला, रेलवे और ग्रामीण सड़कों या फिर कुछ नए और नवोन्मेषी कदम उठाने चाहिए। इस संदर्भ में, सरकार को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सरकार ने हाल के वर्षों में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी से काम किया है। अब समय आ गया है कि सरकार भविष्य के रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दे। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों को उपलब्धता जरूरी है। इनकी कमी के कारण इन वाहनों की बिक्री प्रभावित हो रही है। इस चुनौती को हल करना जरूरी है। कम से कम प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर पांच से 10 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटरों के विकास में निवेश करना भी जरूरी है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है।

इन सभी क्षेत्रों में निवेश से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। पूंजीगत खर्च बढ़ाने में जो प्रमुख बाधा सामने आती है, वह राजकोषीय घाटे से जुड़ी होती है। हालांकि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन ने इस चुनौती को काफी हद तक नियंत्रित किया है। आज सरकार की कमजोर वर्गों को सीधी सहायता और दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश का संतुलन बनाना होगा। जहां कमजोर तबकों के लिए सीधी आर्थिक मदद तो वहीं भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए निवेश भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब ला सकते हैं। आगामी बजट में इस पर विचार किया जाना चाहिए। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब आज के निवेश और नीतियां आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करेंगी।

खरी-खरी

आधुनिक राजनीति शास्त्र का प्रश्नपत्र

कृष्ण जैन

विषय : आधुनिक राजनीति शास्त्र

1. (क) किसे चुनाव के परिणामों में चार राजनीतिक दल मिलकर बहुमत के आंकड़े को छू पाते हैं। वे मिलकर सरकार बनाने राजी होते हों तो सरकार में उपमुख्यमंत्रियों की संख्या क्या होगी?
(ख) यदि बहुमत हेतु पर्याप्त संख्या केवल तीन दलों को मिलाकर हासिल हो जाती हो, फिर भी सरकार में चार दल शामिल हो रहे हों तो उस स्थिति में क्या उपरोक्त संख्या परिवर्तित होगी? संभावित परिस्थितियों सहित व्याख्या कीजिए।
2. यदि किसी राज्य में गठबंधन सरकार का गठन किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़े दल के नेता को सीएम नहीं बनाया जाता। सीएम बनाए गए नेता की जाति, सबसे बड़े दल के प्रमुख नेता की जाति तथा राज्य की जनसंख्या के जातिगत ढांचे के आधार पर इस निर्णय के कारणों पर प्रकाश डालें।
3. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें किसी राज्य में मुख्यमंत्री रहा नेता आगामी वर्षों में उसी राज्य में उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता हो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. दल-बदल का बड़ा कारण है?
(अ) पद का लोभ **(ब)** पूर्व में किए गए घोटालों की जांच का भय **(स)** पुराने दल में अब क्या बचा है जैसी भावना **(द)** उपरोक्त सभी।
2. मुख्यमंत्री को जेल गमन के कारण पद छोड़ना पड़े तो किसे कुर्सी पर बिठाना श्रेष्ठ होगा?
(अ) उसके पति या पत्नी को **(ब)** उसकी ही जाति के किसी नेता को **(स)** दल के दूसरे नंबर के वरिष्ठ को **(द)** नए नेता को जो जेल से आए आदेशों को मानता रहे।
3. वे नेताओं की दावेदारी होने पर सीएम किसे बनाना उचित होता है?
(अ) जो वरिष्ठ हो **(ब)** जो युवा हो **(स)** जो आलाकमान की चमचागिरी में अधिक कुशल हो **(द)** चमचागिरी विद्या में पारंगत किसी तीसरे को।
4. आलाकमान के परिवार से कितने व्यक्ति लाभ के पदों पर नियुक्त हो सकते हैं?
(अ) एक **(ब)** दो **(स)** तीन **(द)** जितनी परिवार के सदस्यों की संख्या हो।

पोस्ट

कभी-कभी लगता है कि देश में ड्रेसोक्रेसी वस एक पोशाक है...आत्मा नहीं।
सर्पाशिया सागवान@DrSarvapriya

सफल देश अपने वर्तमान की चर्चा करते हैं, जबकि संघर्षशील देश अपने अतीत की।
हार्दिक राजगोर@Hardism

महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भीमराव आंबेडकर हो, सरदार पटेल हो या कोई भी, ये नेता हैं नेता ही रहेंगे। इनका देश के विकास, देश के निर्माण में अपना-अपना योगदान है, लेकिन भगवान कोई भी नहीं है। सब आलोचना के दायरे में हैं।
शुभम शुक्ल@ShubhamShuklaMP

संसद की प्रतिदिन की कार्यवाही का खर्च करीब छह करोड़ रुपये है। इसमें सांसदों के आने जाने, रहने, खाने पीने का खर्च नहीं जुड़ा है। वह भी हमारे पैसे से होता है। शीतकालीन सत्र में संसद में छग से पांच दिन भी कार्यवाही नहीं चली।
डा. अनुज कुमार@dranuj_k

संसद सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष की परंपरागत टी पार्टी का विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार करना ठीक नहीं है। विरोध के बावजूद शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए।
पल्लवी घोष@_pallavighosh

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या संसद परिसर में धक्का-मुक्की राजनीतिक कटुता का नतीजा है?

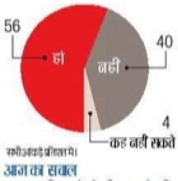

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज तक सवाल
क्या पक्ष-विपक्ष के वैचारिक मतभेद निजी दुश्मनी में बदल गए हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

संसद मे ले जाइए ढाल और तलवार,
क्योंकि चलते हैं नहीं अब तो वहां विचार।
अब तो वहां विचार चल रही गुंडागर्दी,
धक्का देकर घुस रहे देखो बेदर्दी!
'वे' खुद ही पिटवाय रहे हैं अपनी ही भद,
वना अखाड़ा 'लोक-तंत्र' का मंदिर संसद!!
- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

जमीन की शर्त पर उतरे जमीन पर

आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

अपने देश के भौगोलिक नक्शे को देखें तो बिहार उसमें दिल के स्थान पर नजर आएगा। इसलिए देश की धड़कन को चलाए रखने के लिए बिहार का धड़कना जरूरी है। किसी प्रदेश की धड़कन तभी धड़क सकती है, जब उसे उद्योगों की ऊर्जा मिले। जिसके लिए रोड़ा थी- जमीन। वस्तुतः प्रदेश में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक और जमीन का रकबा कम है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बड़ी आबादी की निर्भरता जमीन पर ही है। आम लोग भी जमीन देने में परहेज करते हैं। लेकिन अब माहौल बदलता नजर आ रहा है। इस समय बिहार में देश की तमाम बड़ी कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों का जमावड़ा है। राजधानी पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट की गुरुवार को शुरूआत हुई और शुक्रवार को इसके समाप्त होने तक 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आ गए।

देश के तीन प्रतिशत से कम भूभाग वाले इस राज्य के लोग दूसरे प्रदेशों में अपना हुनर दिखा रहे हैं। अपने प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण वे अन्य राज्यों में जाते हैं और उनके बनाए हुए सामान बिहार के बाजार में बिकते हैं। अब बिहार बदल रहा है। सड़कें चमाचम हो गई हैं। बिजली पर्याप्त है। सबसे बड़ी दिक्कत जमीन की थी, जिसकी बाधा भी अब दूर होती दिख रही है। यहां आए तमाम उद्योगपतियों ने मांग की, कि अगर जमीन मिले तो वे निवेश को राजी हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उद्योगों के लिए सरकार दस हजार एकड़ भूमि देने को तैयार है। उन्होंने नए हवाई अड्डों, फिल्म सिटी निर्माण आदि की जानकारी दी। जो भी उद्योगपति आए,

बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में अपनी बात रखते अदाणी समूह के निदेशक प्रणव अदाणी। जागरण

उन्हें बदलते बिहार की जानकारी दी गई। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने यहां तक कह दिया कि बिहार देश का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। यहां बिजली, पानी, जमीन के साथ ही तमाम इंफ्रेस्टिक का भी आश्वासन दिया गया। इस बदलते बिहार के बारे में जानकर सबकी रुचि बढ़ी और जो एक लाख करोड़ रुपये निवेश की संभावना गुरुवार रात तक दिख रही थी, वह शुक्रवार दोपहर होते-होते एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

बिहार के लिए यह एक बूस्टर डोज ही कहा जा सकता है। यह जरूरी भी है कि बिहार अब आगे बढ़े। पड़ोसी राज्य इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम सुविधाएं मिलने के कारण उद्योग उस तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में वहां लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और पड़ोसी प्रदेश बंगाल भी इसमें पीछे नहीं है। वहां भी पिछले साल लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये निवेश करने की रुचि तमाम कंपनियों ने दिखाई थी।

बिहार के श्रमिक ही अन्य राज्यों के उद्योगों में लगे हैं। यहां कंपनियों को सस्ते में श्रमिक मिल सकते हैं। यहां की महिलाएं भी अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक ये एक ही पाली में काम करती थीं। शुक्रवार को बताया गया कि अब यहां उनके दो पालियों में काम करने की योजना बनाई जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि दिन के अलावा संध्याकालीन पाली में भी अब महिलाएं काम कर सकती हैं। सौर ऊर्जा और आइटी सेक्टर की तमाम कंपनियों ने इसमें खूब रुचि दिखाई है। इस बार का यह कनेक्ट वाकई शानदार रहा। जहां पिछली बार मात्र 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, वहीं इस बार यह आंकड़ा उससे पौने चार गुना अधिक है। नीतीश सरकार अब इस दिशा पर ध्यान दे रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो दो दिन का यह जमावड़ा वाकई बिहार को बदलने की दिशा में सक्रिय होगा और दैवस्य यदि केंद्रीय अनुदान पर चल रहे राज्य की अपनी भी कुछ कमाई होने लगेगी, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम

नेतृत्व के प्रति भरोसे की जीत

महाराष्ट्र चुनाव का जनादेश सकारात्मकता की विजय है। पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास, महायुति का समन्वित प्रयास और असंख्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का यह परिणाम है

शिव प्रकाश
राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, भाजपा

हालिया संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को अपार बहुमत के साथ जीत हुई। महायुति गठबंधन को 49.8 प्रतिशत मत एवं 234 सीटें प्राप्त हुईं। गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने 148 सीटें लड़कर 132 सीटें प्राप्त कीं। वहीं, इस वर्ष लोकसभा चुनावों के परिणाम के आधार पर महाविकास आघाड़ी विधानसभा के परिणाम को भी अपने पक्ष में मान रही थी। लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें एवं विधानसभा की 151 सीटों पर बढ़त मिली थी। महायुति के समर्थन में आया यह जनादेश महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। साथ ही, देश की जनता को भी अनेक प्रकार की सीख देने वाला बनेगा।

वस्तुतः महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जिसने समाज में चलने वाली अनेक विभमतायुक्त कुरीतियों को तोड़कर समरसतायुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज में अलग-अलग प्रकार से भक्ति की धारा बहाने वाले संतों की भूमि महाराष्ट्र है। मुगलों की सत्ता को धूल चटाने वाले हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र से ही संपूर्ण देश को स्वराज एवं स्वधर्म के संरक्षण की प्रेरणा दी।

समरस समाज निर्माण के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, महिला शिक्षा को समर्पित सावित्रीबाई फुले व छत्रपति शाहू जी महाराज की कर्मभूमि भी यही प्रदेश है। दलितोद्धार के महानायक भारतरत्न डा. बाबा साहेब आंबेडकर की प्रारंभिक कर्मभूमि भी महाराष्ट्र ही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी एवं अहिंसावादी दोनों ही माध्यमों से अपना योगदान देने वाले महापुरुषों की भूमि है महाराष्ट्र। महानतम क्रांतिकारी वीर सावरकर एवं लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र ही नहीं, अपितु संपूर्ण देश के युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है। इन समस्त महापुरुषों की प्रेरणा अपने में समाहित किए, देशभक्ति जागरण एवं हिंदुत्व के संस्कारों का पुंज बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्मस्थान नागपुर भी इसी प्रदेश में है, जो सनातनवादिता की आस्था का केंद्र बनकर संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है।

महाराष्ट्र के कुछ सत्तालोलुप नेता इन सभी महापुरुषों को नकारने का कार्य सदैव से कर रहे हैं। अपने को जातिगत राजनीति का केंद्र बिंदु मानने वाले लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े महापुरुषों के अस्तित्व को ही नकारने का काम करते रहे। इतिहास की पुस्तकों में शिवाजी महाराज को लुटेरा कहने जैसे सिद्धांत पुस्तकों में प्रकाशित कर गहने का प्रयास करते रहे हैं। समर्थ स्वामी रामदास महाराज, दादाजी कोंडदेव की शिवाजी महाराज के जीवन में कोई भूमिका नहीं है, यह सिद्धांत भी स्थापित करने का प्रयास होता ही रहा है। वीर सावरकर की देशभक्ति पर प्रश्न खड़े करना जैसे एक परंपरा ही बन गई है। महापुरुषों को जाति के चश्मे से देखना और इसी आधार पर जातिगत भेद खड़ा कर वोट प्राप्त करना ही राजनीतिक कुशलता का उदाहरण बन गया है। महाराष्ट्र की जनता ने इसी विद्वेषपूर्ण मानसिकता को नकार कर सभी के प्रति समान आदर रखने वालों को समर्थन दिया है।

देश में विकास एवं विरासत को समानभाव से स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ अतिवादी तत्व आइएनडीआइए के समर्थन में खड़े हुए थे। हाथ में संविधान के नाम पर रिक्त पुस्तक लेकर संविधान बचाओ का तथ्यहीन विमर्श खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस सहित आइएनडीआइए ने किया। भाजपा के आने से संविधान एवं आरक्षण समाप्त होगा, ऐसा भय का वातावरण लगातार बनाने का प्रयास विपक्ष करता रहा। लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में उसे आंशिक सफलता भी मिलती दिखाई दी। जो स्वयं चुनी हुई सरकारों को भंग कर संविधान का गला घोंट चुके हों, जिनको बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में लोकतंत्र दिखाई देता हो, जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर को चुनाव न जीतने दिया हो, जिनकी एकाधिकारवादी मानसिकता से बाबा साहेब को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा हो, जिन्होंने बाबा साहेब को उचित सम्मान न दिया हो, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 54 में से 42 सीटों को महायुति को सौंपकर इस झूठे तथ्यहीन विमर्श को महाराष्ट्र की जनता का सटीक उत्तर है।

महा विकास आघाड़ी के जिन नेताओं के भाषणों में महाराष्ट्र के विकास का कोई चित्र नहीं था, जो नकारात्मकता के आधार पर विष-वमन करके तथ्यहीन भ्रम फैलाकर महाराष्ट्र की विजय के स्वप्न देख रहे थे, वो हारने के बाद सदैव की भांति ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। यह जनादेश उन सभी नकारात्मक शक्तियों पर सकारात्मकता की विजय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन के साथ महाराष्ट्र के विकास को प्राथमिकता देकर कसौटी पर कसे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, महायुति का समन्वित प्रयास, सज्जन शक्तियों के सहयोग, भाजपा एवं महायुति के असंख्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये विजय प्राप्त हुई है। साथ ही, महाराष्ट्र की जनता के भरोसे का भी यह एक प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फाइल

****

दैनिक जागरण
दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने वाला ही बुद्धिमान है

चरम पर शत्रुता की राजनीति

अवधेश कुमार

वर्तमान राजनीति का संकट परस्पर संवाद और एक-दूसरे के सम्मान के अभाव का है

बीते दिनों संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जो कुछ हुआ, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए डरावना है। संसद संसदीय लोकतंत्र की शीर्ष इकाई है और उस परिसर में सांसदों के बीच समान्य हिंसा हो सकती है और पक्ष-विपक्ष के सांसद एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर धाराओं में रपट भी दर्ज करा सकते हैं, इस सीमा तक राजनीति के पतन की कल्पना नहीं की जाती। राहुल गांधी पर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने, आपराधिक धमकी जैसी धाराओं में भाजपा सांसदों द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया जा चुका है। विपक्ष ने भी सत्तापक्ष के सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख हैं, पर कुछ बातें प्रत्यक्ष दिख रही हैं। भाजपा के दो सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को जो चोटें आईं, वे दिख भी रही हैं। नगालैंड की महिला राज्यसभा सदस्य कह रही हैं कि राहुल गांधी जिस तरह मेरे पास आकर चीखने लगे, वह मेरे लिए असहज था। दोनों पक्षों का अपना मत है, पर कल्पना कीजिए कि कोई महिला किसी आम व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाती तो उसके साथ कानून कैसा व्यवहार करता?

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान राजनीति सामान्य दलीय प्रतिस्पर्धा से निकलकर परस्पर कटुता से होते हुए शत्रु भाव में बदल गई है। मामला इतना था कि विपक्ष बीते कई दिनों से संसद परिसर में मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहा था। 19 दिसंबर को भाजपा सांसदों ने विपक्षी सांसदों के पहले प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सांसद नारा लगाते वहीं पहुंच गए। जितनी बात सामने आ रही है, उसके अनुसार राहुल गांधी उनके बीच से ही सदन में जाने लगे और उसमें ही वह सब घटित हो गया, जिसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। देश ने वह राजनीति भी देखी है, जब सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध शब्दों की बौछार करते थे। बाबजूद उनके बीच परस्पर सम्मान का भाव रहता था। संसद में बाद-विबाद के बाद संसद एक-दूसरे से बात करते हुए बाहर निकलते थे और एक साथ भोजन भी करते थे। कभी सत्तापक्ष और विपक्ष में तनाव उत्पन्न होता था तो कुछ ऐसे नेता दोनों ओर थे, जो बीच-बचाव कर देते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कई बार दोनों पक्षों की सार्वजनिक आलोचना करते हुए सांसदों को अपने व्यवहार को सुधारने की सीख देते और मामला शांत हो जाता था। आज एक भी नेता ऐसा नहीं है जो बीच-बचाव करा सके।

अवधेश राजपूत

प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जैसे ही गिरे, वैसे ही राहुल गांधी को उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। उनके घायल होने की सूचना के तुरंत बाद यदि वह चिंता जता देते, फोन कर लेते तो भी स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। मल्लिकार्जुन खरगे के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए था। इसी तरह नगालैंड की महिला सांसद से क्षमा याचना की जानी चाहिए थी। किसकी गलती है या नहीं, यह विषय बाद में आता है। कोई हमारे सामने गिर गया तो उसे उठाने, उसका हाल-चाल लेने जैसी गरिमा अब्यय दिखनी चाहिए थी। यदि राहुल ऐसा करते, तब भाजपा सांसदों के सामने भी इस सीमा तक जाने का आधार नहीं बनता। नरसिंह राव सरकार के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष डा. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ था और पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की से उन्हें चोट आ गई थी। उनके एम्स में भर्ती होने के कुछ समय बाद ही अनेक केंद्रीय मंत्री उन्हें देखने पहुंचे थे। यह संसदों का एक स्थापित व्यवहार है।

निःसंदेह यह भी सही है कि सदन में विपक्ष की अपनी बात तरीके से रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। राज्यसभा में जैसी स्थिति पैदा हुई, वह नहीं होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं और सभापति के बीच मामला एक-दूसरे के विरुद्ध हमले तक पहुंच गया। जब सभापति धनखड़ ने मल्लिकार्जुन विपक्ष की नाराजगी है तो उसे भी सुनकर दूर करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। असंसदीय शब्दों को निकाला जा सकता है। वर्तमान राजनीति का संकट परस्पर संवाद और एक-दूसरे के सम्मान के अभाव का है। यदि झूठ और फरेब को राजनीति का मुख्य हथियार बनाया जाएगा तो इसकी परिणति विषैली राजनीति ही होगी।

क्या आज कोई मंत्री डा. आंबेडकर के अपमान का साहस दिखा सकता है? आज कोई पार्टी व नेता ऐसा नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से कुछ सेकेंड की एक बाइट को संदर्भ से अलग कर उसे मुद्दा बनाना सस्ती राजनीति है। भाजपा से आप असहमत हो सकते हैं, पर यह स्वीकारना होगा कि यदि डा. आंबेडकर को किसी सरकार ने सर्वाधिक सम्मान दिया तो वह मोदी सरकार है। जिस भाषण पर अमित शाह से त्यागपत्र की मांग की जा रही है, उसी में उनका कहना था कि कांग्रेस का इतिहास उनका अपमान करने का है। फिर वह ऐसे तथ्य सामने लाते हैं, जो यह बताते हैं कि आंबेडकरजी की सरमुच उपेक्षा की गई। लगता है लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे झूठे नैरेटिव की आंशिक सफलता से कांग्रेस और विपक्ष को लगा कि जनता को आगे भी भ्रमित किया जा सकता है। यह भी तथ्य है कि विपक्ष द्वारा झूठ फैलाने के प्रत्युत्तर में भाजपा ने भी वे मुद्दे उठाए, जो उस रूप में नहीं थे। यदि एक पक्ष फरेब करता है तो दूसरे पक्ष से भी इसी तरह का प्रत्युत्तर मिलेगा। कटु राजनीति की आधारभूमि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के साथ ही हो गई थी। देश में नेताओं, बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्टों का एक ऐसा वर्ग है जो यह पचा नहीं पाया कि मोदी सत्ता शीर्ष पर पहुंच गए। आज संघ और भाजपा से वैचारिक मतभेद नफरत की सीमा तक पहुंच गया है। राहुल गांधी द्वारा चौकीदार चोर है जैसा नारा देने से मामला और बिगड़ा। वर्तमान राजनीति में विवेकशील बातचीत की गुंजाइश खत्म है। देश के विवेकशील एवं प्रभावी लोगों को चाहिए कि वे राजनीति को सामान्य पटरी पर लाने के लिए संगठित होकर जो कर सकते हैं, करें, क्योंकि जो हो रहा है, उसके आगे की कल्पना डराने वाली है?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

काम न करने वाली संसद

इसके पहले भी संसद के सत्र बिना किसी खास कामकाज के समाप्त हुए हैं, लेकिन शीतकालीन सत्र का मामूली कामकाज के साथ समाप्त होना इसलिए कहीं अधिक निराशाजनक और चिंताजनक है कि इस दौरान संसद के भीतर-बाहर जमकर हंगामा तो हुआ ही, सत्तापक्ष-विपक्ष के स्थिरे इतने अधिक कटु हो गए कि उनके बीच शत्रु भाव दिखने लगा। इसी के नतीजे में पिछले दिनों संसद परिसर में पक्ष-विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हुई और मामला एक-दूसरे के खिलाफ रपट दर्ज कराने तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच की कटुता बढ़ जाने की पुष्टि तब भी हुई, जब विपक्ष ने राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल कर दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र के लिए इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि सत्तापक्ष एवं विपक्ष में इतना वैमनस्य व्याप्त हो जाए कि वे एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि शीतकालीन सत्र में संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा में उस पर बहस हुई, क्योंकि इस बहस से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बहस के जरिये दोनों पक्षों ने यही साबित करने की कोशिश कि संविधान को एक-दूसरे से खतरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्ष की ओर से अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए जानबूझकर भय का यह भूत खड़ा किया गया है कि मोदी सरकार संविधान और आरक्षण खत्म करने का इरादा रखती है। चूंकि विपक्ष छिछले स्तर पर उतर आया, इसलिए सत्तापक्ष को भी उसी उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए सक्रिय होना पड़ा।

शीतकालीन सत्र में संसद का ज्यादातर समय हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ गया। जो समय बचा, उसे ऐसे मुद्दों को उठाने में जाया किया गया, जिनका आम जनता से कोई खास लेना-देना नहीं था। यदि आम जनता को संसद की कार्यवाही में अपने लिए कुछ न दिखा हो तो हैरानी नहीं। यह समझ आता है कि विपक्ष की दिलचस्पी इसमें ही थी कि संसद में कोई कामकाज होने के स्थान पर हंगामा होता रहे, लेकिन कम से कम सत्तापक्ष को तो संसद की कार्यवाही का उपयोग अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए हर संभव तरीके से करने चाहिए थे। यह अच्छा नहीं हुआ कि सत्तापक्ष ने विपक्ष के हंगामे का जवाब हंगामा करके देना बेहतर समझा। एक ऐसे समय जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, तब उसे यह देखना चाहिए कि वह सही दिशा में बढ़ पा रही है या नहीं? यदि संसद ढंग से नहीं चलेगी तो इससे सरकार का एजेंडा बाधित होगा और उसके नतीजे में न तो जरूरी सुधार हो सकेंगे, न आवश्यक फैसले लिए जा सकेंगे और न ही जनता की अपेक्षाएं पूरी हो सकेंगी।

चारधाम की धारण क्षमता

चारधाम में जैसे-जैसे अवस्थापना सुविधाएं बढ़ रही हैं, तीर्थ यात्रियों की आमद भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है इससे अव्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी ही। इसी को ध्यान में रख उत्तराखंड सरकार अब बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की धारण क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगले साल की यात्रा के लिए मंथन शुरू हो गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने की प्रक्रियाएं आगामी 30 जनवरी तक पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लेने को कहा है। ताकि यात्रा प्रबंधन को सशक्त बनाया जा सके। समय रहते ऐसा किया जाना जरूरी भी था। दरअसल, संसाधन और सुविधाएं बढ़ने के साथ चारों धाम पर तीर्थ यात्रियों का दबाव साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। इसका असर यात्रा पड़ावों पर भी तरह-तरह की अव्यवस्थाओं के रूप में देखने को मिलता है। इसी साल यात्रा मार्गों पर दस-दस किमी लंबा जाम देखने को मिला था। हालांकि, सरकार की ओर से यात्रा व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए तमाम कदम उठाए गए, यहां तक कि सख्ती भी दिखाई गई। लेकिन, सीमित व्यवस्थाओं में एकदम बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए तो योजनाबद्ध ढंग से कार्य किए जाने की जरूरत है। जिस तरह चारों धाम के लिए सुविधाएं बढ़ रही हैं, उससे आने वाले वर्षों में तीर्थ यात्रियों का दबाव और बढ़ेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि चारों धाम ही नहीं, यात्रा पड़ावों पर भी पार्किंग, होटल, धर्मशाला, रैन बसेरा, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं। साथ ही यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए चारों धाम के आसपास स्थित पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

दूर होता समान शिक्षा का लक्ष्य

प्रेमपाल शर्मा

दो तरह के पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के उस विचार की उपेक्षा ही करेंगे, जिसमें समान शिक्षा पर जोर दिया गया है

शिक्षा सुधार की प्रक्रिया में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी वैसे ही दो तरह के पाठ्यक्रम बनने पर विचार हो रहा है, जैसे गणित विषय में पहले से ही है। अभी सीबीएसई 10वीं कक्षा में गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड दो स्तर पर आफर किय जाता है। इसके आधार पर कुछ विद्यार्थी बेसिक गणित पढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड गणित। बेसिक गणित की तुलना में स्टैंडर्ड गणित कठिन होता है। स्टैंडर्ड गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी ही आगे चलकर इंजीनियरिंग आदि की परीक्षा देने में समर्थ होते हैं। यहां तक कि 11वीं और 12वीं में भी गणित पढ़ने की आजादी इन्हीं छात्रों को दी जाती है। गणित विषय के संबंध में इस बात पर कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि इसकी कुछ कठिन परिकल्पनाएं एक स्तर के बाद काम नहीं आतीं। याद करें तो किसी वक्त नौवीं और दसवीं में लड़कियों के लिए गणित की जगह होम साइंस का विकल्प रहता था। हालांकि अब वक्त बदल गया है। समाज की समझ में भी यह बात आ गई है कि लड़कियां भी गणित और विज्ञान में उतनी ही प्रतिभा रखती हैं, जितना लड़के। यही कारण है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार इंजीनियरिंग कालेजों में 30 प्रतिशत लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं। मौजूदा सरकार ने तो एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए आइआइटी में 20 प्रतिशत सीट लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी है, लेकिन दो अलग तरह के पाठ्यक्रम की यही बात विज्ञान और सामाजिक विषयों के लिए सही नहीं होगी।

विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा ही बच्चों की समझ को मुकम्मल बनाती है। इसलिए इन विषयों को दुनिया भर में दसवीं तक अनिवार्य रूप से सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाया जाता है। शिक्षा की बुनियाद यही विषय बनते हैं। विज्ञान जहां बच्चों को तर्कशील प्रयोगधर्मी बनाता है, वहीं सामाजिक विज्ञान उनमें समाज, देश-दुनिया की राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास की समझ पैदा करता है। लिहाजा इन विषयों की पढ़ाई हर बच्चे के लिए समान रूप से अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा ही उन्हें स्वावलंबी बनाएगी और यही लोकतंत्र के हित में भी है। दो तरह के पाठ्यक्रम बनाने के पीछे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने का विचार हावी लगता है, लेकिन

सभी बच्चों को मिले एक जैसी शिक्षा। फाइल

यह सच्चाई से बहुत दूर है। इसे कोटा या दूसरी जगहों पर छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि उन बच्चों में मानसिक तनाव समाज एवं मां-बाप के दबाव और नंबरों की अंधी दौड़ की देन है। उन पर इन विषयों का दबाव नहीं है। देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ केवल कक्षाएं पास करना या परीक्षाओं में कुछ नंबर ज्यादा लाना ही नहीं होता, बल्कि बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाना भी होता है। जैसे कि ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली करती है। वह कहती है कि ''15 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थी में पूरी दुनिया में घूमने और संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए।'' यह विज्ञान और दूसरे विषयों को और बेहतर ढंग से पढ़ने से ही संभव हो सकता है, पाठ्यक्रम की काट-छांट से नहीं।

नीति निर्धारकों को गणित के अनुभव से सबक लेना चाहिए। दिल्ली के महंगे निजी स्कूलों में सभी बच्चे जहां स्टैंडर्ड गणित पढ़ते हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे बेसिक गणित। जहां स्टैंडर्ड गणित पढ़ने वाले बच्चों से इंजीनियर या डाक्टर बनने की उम्मीद की जाती है, वहीं सरकारी स्कूलों में छात्रों के करियर के प्रति एक उदासीन रवैया देखा जाता है। यदि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी यह वर्गीकरण कर दिया गया तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और गिर जाएगी। हमें सरकारी स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर बनाने की जरूरत है, न कि और कमजोर करने की। प्रश्न यह है कि क्या उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए इन बच्चों को मदद मिलेगी? हो सकता है कि ऐसे दोहरे पाठ्यक्रम की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और पीछे रह जाएं। यह कदम नई शिक्षा नीति के उस विचार को भी उपेक्षा करता है, जिसमें समान शिक्षा की बात कही गई है और जिसके तहत मेडिकल और आइआइटी जैसी संस्थाओं या पिछले दिनों केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए समान प्रवेश परीक्षाएं शुरू की गई हैं। हमारे देश के निजी स्कूलों से निकले इंजीनियरों की क्षमता और स्किल पर दुनिया भर में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि उनमें से 70 प्रतिशत डिग्री होने के बावजूद सक्षम नहीं हैं। ऐसी चुनौती के बीच तो हमें अपने पाठ्यक्रमों को और बेहतर करने की जरूरत है।

हालांकि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रमों को मजबूत बनाने, प्राइमरी एवं उच्च स्तर की पढ़ाई अपनी भाषाओं में कराने पर जोर दिया गया है, लेकिन इस दिशा में अभी कोई विशेष प्रगति नहीं दिखी है। इसके अलावा 11वीं एवं 12वीं और दूसरे स्तरों पर अपनी मर्जी से विषय लेने की जो बात चार साल पहले हुई थी, उस दिशा में भी ठोस कदम नहीं बढ़ाए जा सके हैं। शिक्षा की पुरानी शैली यथावत जारी है, बल्कि उसमें और गिरावट आई लगती है, जिसका प्रमाण देश में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों और बाहर जाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि है। यह न भूलें कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। पिछली सदी के छठे दशक में अंतरिक्ष विज्ञान में जब रूस आगे बढ़ता नजर आया तो अमेरिका ने अपनी विज्ञान नीति में आमूलचूल बदलाव किया, जिसका प्रभाव आज नजर आ रहा है। विज्ञान में आज अमेरिका दुनिया का अगुआ बना है। वक्त आ गया है कि दुनिया भर की शिक्षण पद्धतियों को संरक्षते हुए हम भी अपनी विज्ञान और सामाजिक शिक्षा को ऐसा बनाएं कि दुनिया भर के लोग भारत में पढ़ने के लिए लालायित हों।

(भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ध्यान

ध्यान एक कौशल है, जो आपके भीतर छिपी हुई असीम ऊर्जा के स्रोत को पहचानने में मदद करता है। ध्यान आपके दिन में और अधिक समय जोड़ता है, क्योंकि यह समय प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाता है और जब भी आप थका हुआ महसूस करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा से भर देता है। यह आपको स्वस्थ रखता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ध्यान आपको अतीत को भुलाने, वर्तमान में रहने और आगे बढ़ने की क्षमता देता है।

हमारा मस्तिष्क एक परमाणु संरचना के समान है। इसका केंद्र प्रोटान की तरह सकारात्मक है और नकारात्मकता इलेक्ट्रान की तरह केवल परिधि पर है, वह किसी भी व्यक्ति के मूल में नहीं है। कोई भी बच्चा बुरा पैदा नहीं होता, इसलिए यदि किसी ने बुरी आदतें विकसित कर ली हैं, तो यह उसके परिवेश, उचित शिक्षा की कमी या अन्य कारणों से है। मानव स्वभाव की जड़ों में अच्छाई और परोपकारिता है, जो हर व्यक्ति के भीतर हमेशा रहती है। हर अपराधी के भीतर एक पीड़ित होता है, जो सहायता के लिए पुकार रहा होता है। यदि आप पीड़ित को ठीक कर देंगे तो उस व्यक्ति के भीतर का अपराधी समाप्त हो जाएगा। ध्यान और प्राणायाम इसमें बहुत सहायक हैं।

ध्यान से पहले और बाद में प्राणायाम किया जाना चाहिए। जब आप ध्यान से पहले प्राणायाम करते हैं, तो यह आपको ध्यान की गहराई तक जाने में सहायता करता है। यदि आप ध्यान के बाद प्राणायाम करते हैं तो यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। ध्यान एक कप को खाली करने जैसा है। जब आप एक कप भरते हैं तो आप इसे कई अलग-अलग चीजों से भर सकते हैं, लेकिन जब आप खाली करते हैं तो सभी में खालीपन एक समान होता है। ध्यान उस खालीपन, उस आंतरिक शून्यता तक पहुंचना है जो जीवन में पूर्णता को जन्म देती है।

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

नशे के जाल में न फंसें युवा

डा. मोनिका शर्मा

युवाओं का नशे के जाल में फंसना देश के भविष्य का हर मोर्चे पर दिशाहीन होने जैसा है

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल भी 'कूल' नहीं है। चिंतनीय है कि महानगरों में ही नहीं, दूर-दराज गांवों में भी नशे का जाल फैल गया है। लत का रूप ले लेने वाली नशे की आदत जीवन के हर पहलू पर दुष्प्रभाव डालती है। ऊर्जावान आयुवर्ग में ही बीमारियों का शिकार बना देती है। युवाओं को सदा के लिए दिशाहीन कर देती है। नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और यहां तक कि मानवीय सोच पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस जाल में फंसे युवा नशीले पदार्थ खरीदने के लिए आपराधिक गतिविधियों तक का हिस्सा बन जाते हैं। हिंसात्मक व्यवहार, सड़क दुर्घटनाएं और स्वयं अपना जीवन छीन लेने जैसी समस्याओं से तो नशे की लत गहराई से जुड़ी है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के युवाओं से अपील की है कि न केवल दोस्तों के दबाव में आकर ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति से दूर रहें, बल्कि उन लोगों को अनुसरण करने से भी बचें जो इसकी लत के शिकार हैं।

शीर्ष पत्रिका 'ड्रग एंड अल्कोहल रिव्यू' द्वारा लैंगिक अपराध और शराब के संबंध पर किए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक लैंगिक अपराध के लगभग आधे मामले नशे की हालत में ही होते हैं। ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिनमें नशे के लती युवा चोरी, झूठ और जालसाजी के साथ ही परिवारजनों की जान तक लेने से नहीं चूके। व्यावहारिक आक्रोश से लेकर शारीरिक व्याधियों तक, ड्रग्स नकारात्मकता और शारीरिक परेशानियों की जड़ हैं। बावजूद इसके हमारे देश में नशे के जाल में फंसते युवाओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आए दिन हो रही घटनाएं-दुर्घटनाएं बताती हैं कि इसी अनुपात में युवाओं में मानसिक उन्माद भी बढ़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक दुष्कर्म, हत्या, डकैती, लूटमार जैसी छोटी-बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों में नशे का सेवन करने वालों के मामले लगभग 74 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि युवाओं का नशे के जाल में फंसना देश के भविष्य का हर मोर्चे पर दिशाहीन होने जैसा है।

न्यायालय ने इस ताजा निर्णय में कहा है कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए अभिभावकों, समाज और एजेंसियों को गंभीर प्रयास करने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस समस्या से बचाव के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय करने आवश्यक हैं। निःसंदेह देश के किशोर और युवा आज नशे के बाजार के निशाने पर हैं। कम उम्र के ग्राहकों को न सिर्फ लती बनाना, बल्कि दोस्तों और हमउम्र लोगों तक ड्रग्स के बाजार को फैलाना भी आसान होता है। ऐसे में युवाओं का जीवन सहेजने के लिए सजगता आवश्यक है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्रदूषण की बढ़ती चुनौती

'आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोकें' शीर्षक से लिखे आलेख के तहत डा. भरत झुनझुनवाला ने वायु प्रदूषण को देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए हानिकारक बताते हुए इसकी रोकथाम के लिए सरकारों और आमजन से गंभीरता दिखाने की मांग की है। प्रदूषण प्राणियों की सेहत के साथ देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी बेहद हानिकारक है, क्योंकि इससे फसलों को जो नुकसान होता है, बीमारियों का जो कारण प्रदूषण बनता है उनके लिए सरकारों को भारी खर्च करना पड़ता है। बढ़ते प्रदूषण से बढ़ती जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है प्रदूषण। यही कारण है कि दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन देश के अधिकांश राज्य बारिश को तरस रहे हैं। बारिश न होने के कारण हिमाचल और अन्य राज्यों में कृषि पर भी संकट के बादल छा गए हैं। अब सूखे से जो नुकसान होगा उसके लिए भी सरकारों को भारी खर्च करना पड़ सकता है। कहीं वायु प्रदूषण का खतरा कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक न बन जाए? हालांकि सरकारें इससे निपटने के लिए कुछ पाबंदियां लगा रही हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। वायु प्रदूषण सल दर सल चुनौती बनता जा रहा है। यह भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। यदि इस बढ़ते प्रदूषण का समय रहते निवारण नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं, जब यह बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। देश में केंद्र और राज्यों में पर्यावरण विभाग हैं, इनमें मंत्री और अफसरों और अन्य कर्मचारियों को भारी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी देश में प्रदूषण को रोकने के लिए गंभीरता से काम क्यों नहीं किय जा रहा है? क्यों यह चुनाव में वैसा मुद्दा नहीं बनता है जैसे आरक्षण, जाति, धर्म आदि बनते हैं? इससे साफ जाहिर है कि हमारे देश में सरकारें वायु प्रदूषण के लिए गंभीर नहीं हैं, बस इसके लिए यह बातें ही करती हैं, काम नहीं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

लोकगीतों का बदलता स्वरूप

पहले लोकसंगीत में पंजाबी रस का पूरा प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन मौजूदा समय में पंजाबी गायन बिल्कुल बदल चुका है। 1970 और 1980 का समय पंजाबी लोकगीतों के लिए काफी बेहतरीन काल रहा। इस समय के संगीत पारिकारिक रिश्तों, संस्कृतिक धरोहर, गुरु की महिमा, फकीरों से जुड़े रहते थे, लेकिन 1990 में पंजाबी लोकगीतों में नए बदलाव आए। उनमें भांगड़ा, ढोल, पोप जैसी कई चीजें जुड़ गईं और पंजाबी लोकगीतों और गायन का दायरा बढ़ता चला गया। देश-दुनिया में लाखों प्रशंसक बड़े पैमाने पर पंजाबी गायन से जुड़ गए और धीरे-धीरे पंजाबी गायकों ने अपने आय को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन मौजूदा समय में पंजाबी लोकगीतों से पंजाबी संस्कृति और संस्कार का दायरा लगातार कम हो रहा है। उसमें हिंसा, अश्लीलें का प्रयोग, शराब, हथियार का प्रभाव बढ़ रहा है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे गानों का युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

खतरे में संसद की गरिमा

गुरुवार को जो कुछ भी संसद में घटा, वह बेहद शर्मनाक है और उसकी जितनी निंदा हो, वह कम ही होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष को आपस में नोकझोंक और मुद्दों पर असहमति तो सामान्य बात है लेकिन नौबत धक्का-मुक्की और दो सांसदों के अस्पताल पहुंचने की आ जाएगी, यह किसी ने भी सपने में न सोचा होगा। दुख की बात यह है कि जब प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने भाजपा संसद प्रताप सारंगी को घायल अवस्था में देख तो उनसे हालचाल पूछने और अस्पताल ले जाने के बारे में पूछने के बजाय वहां से मुंह मोड़कर वापस चले गए। पहले कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को काट-छांट कर दिखाया और यह प्रस्तुत किया कि जैसे अमित शाह ने डा. आंबेडकर की आलोचना की हो और उसके बाद विरोध कर रहे भाजपा के सांसदों से धक्का-मुक्की पर उतर आए। संसद की गरिमा बनाए रखने में हर सांसद की भूमिका होती है। प्रतिपक्ष के नेता की इसमें बड़ी भूमिका बनती है।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। अपना हमारा पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के पठन एवं संकलन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 21 दिसंबर 2024

मर्यादा के विरुद्ध

शीतकालीन सत्र में टकराव चरम पर पहुंचा

पिछले महीने की 15 तारीख से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने-होते ऐसे विवाद, मुद्दे और टकराव के बिंदु छोड़ गया, जिसकी छाप आगे भी संसदीय कार्यवाही पर दिखते रहने के आसार हैं। सच है कि इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में गंभीर बहस के कुछ अच्छे पल भी आए, लेकिन ज्यादातर समय सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव ही हावी रहा।

सांसदों में धक्का-मुक्की

संविधान पर बहस | संविधान पर दोनों सदनों में चली लंबी बहस तीखी जरूर रही, लेकिन यह ज्यादातर शांतिपूर्ण रही और इसमें आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही कई गंभीर मुद्दे भी उठे। जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के संविधान में निहित भारतीय परंपरा के शाश्वत तत्वों और आजादी की लड़ाई से मिली सीखों को रेखांकित किया, वहीं सत्ता पक्ष ने इमर्जेंसी काल की याद दिलाते हुए बताया कि संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन को देश ने कभी स्वीकार नहीं किया। इस बहस में दोनों पक्षों ने संवैधानिक पवित्रता के प्रति निष्ठा की वकालत की।

सभापति पर अविश्वास | संसद के इस सत्र के नाम एक यह रेकॉर्ड भी आया कि इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि यह प्रस्ताव उपसभापति ने तकनीकी और प्रक्रियागत वजहों से खारिज कर दिया, लेकिन इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की बढ़ती हुई दूरी जरूर रेखांकित हुई।

एक देश, एक चुनाव | यह प्रकरण भी इस बात के एक उदाहरण के ही रूप में दर्ज हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नजरिए में जो अंतर है, उसे पाटने की कोई खास कोशिश किसी तरफ से नहीं हो रही। विपक्ष के विरोधी रुख से अच्छी तरह वाकिफ होते हुए भी सरकार यह बिल लेकर आई, हालांकि इसे पास कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत फिलहाल उसके पास नहीं है। जाहिर है, इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजकर भी सरकार ने देशवासियों को यह संदेश देना जरूरी समझा कि इस मुद्दे पर वह कोई समझौता नहीं करने वाली।

टकराव का चरम | इस पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में अदाणी और जॉर्ज सोरोस के सहारे सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमले करने और संसद का कामकाज उन बमों को लेकर जैसे एक-दूसरे से होड़ करते रहे। फिर भी, आखिर के दो दिन संसद भवन में जिस तरह के दृश्य दिखे, उनकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर की गई गृहमंत्री की एक टिप्पणी पर विपक्ष ने तो संसद के अंदर और बाहर तूफान खड़ा करने में कोई कसर नहीं ही छोड़ी, सत्तापक्ष ने भी इसका जवाब देने में नए कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे धक्का-मुक्की, ICU में भर्ती और FIR के रूप में सामने आए, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

दो दूनी चार

घर के क़रीब दफ़्तर

रमेश शिवारी

कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना कोई यूं ही रोज लंबा सफर नहीं करता। दफ्तर के लिए रोज लंबा सफर करने वालों को देख यही खयाल आता है। कोई नोएडा में रहता है, रोज गुड़गांव काम करने जाता है। कोई गुड़गांव में रहता है, रोज काम करने नोएडा जाता है। लोकल ट्रेनों से मेरठ और सहारनपुर से दिल्ली आने वाले भी कम नहीं हैं।

पब्लिक सेक्टर के ढेरों उद्यम कामगारों की कॉलोनी बसाते हैं। कॉलोनी के लोगों को सामाजिक संबंध बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। घर से दफ्तर की दूरी पैदल तय की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी दफ्तर के नजदीक आवास बड़ा आकर्षण होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह के कुछेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसे एक संस्कृति का रूप दिए जाने की जरूरत है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। इस विकास के साथ कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये कामगार अक्सर ग्रामीण या दूर-दराज के क्षेत्रों से आते हैं। अपनी जीविका के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में अनियोजित ढंग से बस जाते हैं। इससे स्लम बनते हैं। इस तरह का आवास न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता पर भी बुरा प्रभाव डालता है।

सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कामगारों को फैक्ट्रियों के नजदीक बसाने की वकालत की गई है। कहा गया है कि इसके लिए सरकार को भी फंडिंग करनी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली और पानी की दरों में छूट देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में रेंटल हाउसिंग की बात कही थी। इसमें औद्योगिक कामगारों के लिए रहने के इंतजाम पर गौर किया गया था। प्रधानमंत्री ने भी हाल में एक बैठक में जिक्र किया था कि आम पर जितने जरूरी हैं, उतने ही जरूरी औद्योगिक क्षेत्रों के आवास भी हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए फैक्ट्री के नजदीक घरों का रोल अहम है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। इस तरह के आवास से कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। औद्योगिक इलाकों में भूमि आवंटन के जो नियम हैं, उसमें आम तौर पर श्रमिक आवास के लिए लचीला रुख नहीं है। कार्यस्थल के नजदीक घर होने से प्रॉडक्शन बढ़ेगा। वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। नौकरियां तेजी से बदलने की की परेशानी कम होगी। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगा।

ऐपल जैसी कंपनियों के इको सिस्टम ने भारत में कदम रखने के बाद इसे प्राथमिकता पर रखा है। चीन और विएतनाम में इंडस्ट्रियल हाउसिंग का फॉर्मुला सफल रहा है। उसे भारत में भी लागू करने की कोशिश हो रही है। फॉक्सकॉन जैसी ऐपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए तमिलनाडु सरकार ने खुद कदम आगे बढ़ाए। करीब 18 हजार यूनिटें बनाने की पहल की गई है। बताते हैं कि पहली बार भारत में किसी राज्य सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए इस स्केल का हॉस्टल बनाने का काम किया है। सरकार ही इसे मेंटेन और ऑपरेट भी करेगी। कैंपस में ही शॉपिंग एरिया है, डायनिंग एरिया है, स्पोर्ट्स जैसी आउटडोर एक्टिविटी का इंतजाम है।

ऑफ़ दि ट्रैक

मरता नहीं कचरा

दिलीप लाल

कूड़े-कचरे में आग लगाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक नई रिसर्च बताती है कि खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। ब्रिटेन में कचरा जलाने वाले संयंत्रों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जांच की गई थी। नतीजे बताते हैं कि चिमनियों का काला धुआं हमारे फेफड़े ही नहीं खराब कर रहा, बल्कि मां के दूध तक को जहरीला बना दे रहा है। रिसर्च के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में रहने वाली मांओं के दूध में घातक केमिकल्स Polychlorinated biphenyls (PCBs) और डाइऑक्सिन पाए गए हैं। दरअसल जब इन दोनों केमिकल्स का सही से निस्तारण नहीं किया जाता, खुले में फेंक दिया जाता है, तो ये हवा, पानी और जमीन को प्रदूषित करते हैं। लेकिन, जब हम कचरे को जलाते हैं, तो प्रदूषण फैलने की आशंका और भी बढ़ जाती है। ये दोनों केमिकल्स कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनसे पुरुषों में स्पर्म काउंट पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही, डायबिटीज और पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक, दोनों केमिकल धुएं में घुलने के बाद वातावरण में ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। और इससे भी बढ़कर चिंता करने वाली बात यह है कि जिस जगह इन्हें जलाया जाता है, उसकी तुलना में दूर रहने वाली जगहों पर असर ज्यादा होता है। ये दोनों रासायनिक तत्व हमारे खाने-पीने की चीजों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं।

टैलंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए हर तरीका अपनाती हैं कंपनियां

IIT प्लेसमेंट में भी पक्षपात?

प्रवीन मोहता

भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजिनियरिंग संस्थानों में शुमार IIT में हर साल दिसंबर में स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट शुरू होता है। पिछले कुछ वर्षों से प्लेसमेंट सीजन हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। वजह होती है भारी-भरकम सैलरी पैकेज, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। IIT बॉम्बे ने प्लेसमेंट को साफ-सुथरा और पक्षपात रहित बनाने के लिए एक पैनल बनाया है। तो क्या IIT प्लेसमेंट में भी पक्षपात संभव है? IIT कानपुर के लोग खुले तौर पर मानते हैं कि चाहे-अनचाहे कुछ छात्रों को प्लेसमेंट में थोड़ा-बहुत फायदा मिल ही जाता है। इसकी वजह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं।

AI image

नौकरी की जद्दोजहद

- कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा
- सिलेक्शन पर नेटवर्किंग का असर
- कई सोर्स से पता करती हैं कंपनियां

नेटवर्क इफेक्ट | IIT कानपुर में प्लेसमेंट से जुड़े रहे एक अधिकारी इस पूरे विषय को विस्तार से समझाते हैं। वह कहते हैं कि प्लेसमेंट में कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-बहुत पक्षपात तो होता है, लेकिन इसकी वजह पढ़ाई में बढ़िया प्रदर्शन के साथ अन्य गतिविधियों में उनकी सक्रियता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में आगे होते हैं, वे खेल, डिबेट और विविध में भी आगे रहते हैं। इससे उन्हें थोड़ी सहायता और पहचान मिलती है। जो क्लास में टॉपर है, उसके लिए साथी स्टूडेंट्स के मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है। टॉपर्स के अलग ग्रुप भी बने होते हैं। इसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। नेटवर्किंग का थोड़ा असर लाजिमी है।

सीनियर्स का रोल | आम तौर पर प्लेसमेंट के लिए किसी भी IIT में जाने वाली बड़ी कंपनियां पिछले 1-2 साल में उस कैंपस से ही रिक्रूट हुए स्टूडेंट्स को साथ लेकर जाती हैं। जो कैंपस से 1-2 साल पहले पेशेवर दुनिया में गए हैं, उनके अपने जूनियर्स से अच्छे रिश्ते होते हैं। ऐसे में पहले से फीडबैक लेना कोई बड़ी बात नहीं। प्लेसमेंट से जुड़े अधिकारी एक उदाहरण देते हैं, 'कुछ साल पहले दो दिनों तक एक अच्छे लड़के को किसी इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। इसी बीच एक कंपनी ने मुझसे किसी अच्छे स्टूडेंट की मांग की। मुझे उस छात्र के बारे में पता था, तो उसका नाम आगे कर दिया। संयोग ही था कि कंपनी ने उसे जॉब ऑफर दे दिया।'

सोर्स से जानकारी | हमें कंपनियों के नजरिये से भी चीजों को समझना होगा। कंपनियां कम से कम लागत में बढ़िया से बढ़िया टैलंट को हायर करना चाहती हैं। कैंपस विजिट के पहले ही कंपनी के प्रफेशनल्स अपने परिचितों और दूसरे सोर्स के जरिये चीजों को समझ लेते हैं। यहां से मिले क्लू आगे काम करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पहुंचने वाली कंपनियां पूरी तरह HR पॉलिसी पर निर्भर होती हैं। ऐसे में उनके पास किसी कमजोर छात्र-छात्रा को जॉब देने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कंपनियां हरसंभव तरीके इस्तेमाल करती हैं। उनके प्रतिनिधियों का स्टूडेंट्स के साथ खाना-पीना और घूमना भी एक सामान्य बात है।

कंपनियों में होड़ | कई बार कंपनियां भी किसी खास स्टूडेंट को किसी भी स्थिति में अपने यहां रखना चाहती हैं। इसकी वजह इंटर्नशिप में बढ़िया प्रदर्शन होता है। IIT कानपुर से एक छात्रा जापान में सोनी कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप के लिए गई थी। जब प्लेसमेंट की बारी आई, तो सोनी के प्रतिनिधि उस इंटर्न को ही लेने पर अड़ गए। इंटर्न से बात की गई, लेकिन जॉब से इतर कुछ समस्याओं के चलते वह राजी नहीं हुई। टैलंटेड स्टूडेंट्स को लेने के लिए कंपनियां आपस में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा करती हैं। कई कंपनियां टॉपर से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स का चुनाव करती हैं, जो उनकी टीम में फिट हो जाएं।

सेट फॉर्मेट नहीं | फील्ड वर्क वाली कंपनियों की मांग बिल्कुल अलग होती है। उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स रिक्रूट करने होते हैं, जो IIT संस्थानों की आपसी खेलकूद प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हों। तेज दिमाग के साथ मजबूत शारीरिक क्षमता वाले युवा ही फील्ड में कंपनी के लिए पूरा दम लगा सकते हैं। इस तरह, IIT कैंपस में कई एंगल से सोचकर जॉब ऑफर दिए जाते हैं। आप इसे मानव स्वभाव से भी जोड़ सकते हैं। यह UPSC या सरकारी नौकरी नहीं है, जहां कागजों पर नंबर देखकर एक सेट फॉर्मेट में ही सब कुछ तय कर दिया जाए।

क्रेडिट पॉइंट्स | तकनीक की दुनिया में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स भी विशेष किस्म के पक्षपात की बात स्वीकारते हैं। एक रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि हां, कुछ पक्षपात हो ही जाता है। पढ़ाई के अलावा इतनी सारी गतिविधियां रखने का उद्देश्य ही यही होता है कि स्टूडेंट्स की दबी प्रतिभा को बाहर लाकर विकसित किया जाए। ऐसी गतिविधियां उनके क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ाती हैं।

रेज्यूमे का असर | बीटेक के एक छात्र का कहना था कि रेज्यूमे में पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीजों का जिक्र करना होता है। रेज्यूमे देखकर ही कंपनियां काफी कुछ तय कर लेती हैं। प्लेसमेंट के दौरान इंटरव्यू और प्रबंधन की कमान भी आईआईटियंस के हाथों में ही होती है। IIT कैंपस प्लेसमेंट में जॉब हासिल करने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि खेल, रचनात्मक गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों में भी आगे होते हैं। उनके बाकी स्टूडेंट्स से रिश्ते भी बेहतर होते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में ये सारी चीजें काउंट होती हैं।

www.nbt.in

भगत सिंह की वह तस्वीर

चांदनी चौक के बीचोंबीच ऐन फव्वारा चौक पर छोटे- से ढाबे पर गया, तो जायकों से ज्यादा मेरा ध्यान सामने दीवार पर फ्रेम में सजी खास फोटो ने खींचा। यह शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर थी। भगत सिंह के हाथ-पैर में लोहे की मोटी-मोटी बेड़ियां बंधी थीं, वह जेल में दिखाए गए थे। हाथ में किताब थामी थी- शायद लेनिन की जीवनी, जो वह अंतिम दिनों में पढ़ते थे। पहली बार इस ढाबे में मैं मई 2011 में गया था, फोटो पहले भी चूं ही लगी थी। इन साढ़े 13 सालों में ढाबा रेनोवेट हो गया है, लेकिन नहीं बदली तो शहीद भगत सिंह की वह तस्वीर। बस फ्रेम जरूर बदल गया है।

ढाबा 1966 से है। काउंटर से जुड़े शेल्फ के सहारे खड़े होकर खाते-खाते भगत सिंह को निहारते हुए जेहन में सवाल उमड़ा, 'नेता लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए देश के नायकों की तस्वीरें अपने दफ्तरों-घरों में लगाते ही हैं, लेकिन एक छोटे से ढाबे में ऐसा क्यों है?' ढाबे में किसी भगवान या गुरु की भी तस्वीर नहीं लगी है। पूछने पर ढाबे के तीसरी पीढ़ी के मालिक सरदार रमन ज्योत सिंह आए और सरदार भगत सिंह जी के बीच कनेक्शन नहीं बता पाए। मैंने पूछा, 'शायद आपके पिता जानते हों?' जवाब मिला, 'अभी घर पर ही होंगे, मैं फोन पर बात कराता हूं।'

खुद अपनी आंख से

अमिताभ स.

सरदार अवतार सिंह फोन पर दुआ-सलाम के बाद बताने लगे, '1984 में जाने तक मेरे पिता सरदार दर्शन सिंह के दिल में भगत सिंह के प्रति बड़ा मान-सम्मान था। वह बताते थे कि यह 23 मार्च, 1931 को फांसी पर चढ़ने से पहले लाहौर सेंट्रल जेल में कैमरे से खिंची अमर शहीद की दुर्लभ तस्वीरें मेरे से एक है।' मैंने बीच में टोका, 'लेकिन यह उन्हें मिली कैसे ?' वह बताने लगे, 'मेरे पिता रोज उर्दू के 2-4 अखबार पढ़ते थे। उनमें से एक मिलाप उर्दू था। फांसी से कुछ दिन पहले मिलाप के संपादक ने भगत सिंह से जेल में जाकर इंटरव्यू लिया था, जो अखबार में छपा था। इंटरव्यू के साथ यही फोटो भी छपी थी। तब छपाई इतनी साफ नहीं होती थी। देश के वीर सपूत की साफ तस्वीर देखने के लिए मेरे पिता मिलाप के दफ्तर ही जा पहुंचे। संपादक महोदय उनके भगत सिंह प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि असली खिंची ग्लॉसी पेपर की फोटो ले दिखाई ही, भेंटस्वरूप दे भी दी।'

'.. सीने से लगा कर पिता जी फोटो घर लाए, फ्रेम कराई और अपने कमरे की दीवार पर हमेशा के लिए सजा ली। 1966 में जब ढाबा चालू किया, तो यहां लगा ली, ताकि आजादी के परवाने को ज्यादा लोग सलाम कर सकें। अब मेरे और मेरे बेटे में भी शहीद भगत सिंह की देशभक्ति के प्रति वही जज्बा है।' उन्होंने बताया, 'अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर के केंद्रीय सिख संग्रहालय में भी यही फोटो लगी है।' बगल के चाय वाले हरी शंकर का कान चाय बनाते-बनाते हमारी बातों पर लगा था। जाते-जाते मुझसे बोले, 'मैं तो भगत सिंह जी की फोटो 1995 से देख रहा हूं।'

चलते-चलते...

शिशु की पहली प्यारी आवाज और शब्द बनाने के शुरुआती प्रयास सीधे उसकी हृदय गति से जुड़े होते हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में कहा गया है कि हार्ट रेट शिशुओं के बोलने के समय को प्रभावित करता है। इससे शिशुओं में भाषा की समझ बढ़ती है। कोमल आवाज में बच्चों का बड़बड़ाना इसी का संकेत है।

US फेल, तालिबान पास!

साल 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ी। तब से, कम से कम एक मामले में तालिबान ने बेहतर काम किया है और वह है ड्रग्स पर लगाम। समझते है पूरी कहानी :

AI image

बाकवा में हुकूमत

अमेरिकी हमले के बाद तालिबान ने दूरदराज के इलाकों में पनाह ली। ऐसा ही जिला है बाकवा, जहां तालिबान ने अफीम की खेती को बढ़ावा दिया ताकि अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार खरीद सके। इसके लिए उसने स्थानीय लोगों को आर्थिक मदद भी दी।

ड्रग्स की खेती

अफीम की खेती से लेकर उसकी तस्करी तक, हर काम तालिबान की निगरानी में होता था। हर काफ्म पर उसके लड़ाके टैक्स वसूलते थे। तालिबान के अपने चेकपॉइंट थे, जहां से होकर अफीम और दूसरे नशीले पदार्थ बाहर भेजे जाते थे।

5 पॉइंट

बेशुमार कमाई

विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, तालिबान को हर महीने लगभग 400 करोड़ रुपये की कमाई ड्रग्स से होती थी। अफीम के धंधे को खत्म करने के लिए अमेरिका ने campaign चलाए, लेकिन करप्शन और लोकल सपोर्ट की कमी के चलते उसे कभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकी। अभियान का खर्च नष्ट की गई खेती या लैब से ज्यादा होता था।

छिपे ठिकाने ध्वस्त

तालिबान ने कहा था कि जंग खत्म होने के बाद वह अफीम की खेती को बंद करा देगा, क्योंकि यह इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है और उसने यही किया। उसने ड्रग्स के रूट और अब्दुल वाद्दुद बाजार जैसे ओपन ड्रग मार्केट बंद करा दिए। उसे सारे छिपे ठिकाने पता थे, तो कार्रवाई करने में परेशानी नहीं आई।

सख्ती का सहारा

तालिबान ने धार्मिक प्रोपगैंडा से अफीम की खेती शुरू कराई थी और बंद करने में भी इसी का सहारा लिया। आदेश न मानने वालों पर सख्ती करती। अमेरिका हवाई हमले का सहारा लेता था, जिसमें कई बार नागरिकों की भी मौत हुई। तालिबान ने जमीनी निगरानी बढ़ाई।

प्रस्तुत : शैलेंद्र पांडेय

फिर तो ज़ाकिर साहब ने कमाल कर दिया

प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार ने इसी हफ्ते ग्वालियर किले में भारत के सबसे बड़े शास्त्रीय संगीत ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया, जिसमें तानसेन के तीन गणों को 546 शास्त्रीय संगीतकारों ने धुन में पिरोया। इसे गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। वह उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के भी काफी नजदीकी थे। पं. रोनू मजूमदार से शास्त्रीय संगीत के मौजूदा हाल पर बात की राहुल पाण्डेय ने। पेश है बातचीत के अहम अंश :

सप्ताह का इंटरव्यू

पंडित रोनू मजूमदार

इंटरनेट पर जाकिर हुसैन को दी गई यह अनूठी श्रद्धांजलि काफी सराही जा है

■ जाकिर हुसैन साहब के जाने के बाद एक बड़ा स्पेस खाली हुआ है...

यह स्पेस भरना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो कुछ नहीं, मगर बहुत ही मुश्किल लग रहा है। वह सिर्फ तबला प्लेयर नहीं थे। वह एक ग्लोबल मास्टर थे। उन्होंने बहुत कुछ किया। वह ताज किया, शक्ति बैंड बनाया, फिल्में भी कीं। यह इंडिविजुअल टैलंट की बात है। व्यक्ति की अपनी क्वॉलिटी ही उसे वर्ल्ड लेवल पर ले जा सकती है, जैसे भारत रत्न पंडित रविशंकर जी थे। उनकी फिल्मों में भी मैंने बजाया। मर्चेंट आइवरी प्रॉडक्शंस की मुहाफिज फिल्म के संगीत पर जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो पाया कि वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के बारे में भी उन्हें कितना ज्ञान था। मैं परिवार से जुड़ा रहा। मेरा सुपरहिट एलबम जाकिर भाई मेरे साथ लाए- नाम था हार्ट टु हार्ट। उसके पहले उन्होंने मेरे साथ कभी संगत नहीं की थी। रेकॉर्डिंग हो रही थी। वह बोले, रोनू बाबू शुरू करिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। दिल में सोचा कि थोड़ा अभ्यास तो कर लेते, कभी बजाया नहीं साथ में। मैंने शुरू किया और उन्होंने ऐसे बजाया जैसे जन्मों से मेरे साथ बजा रहे हैं। इतनी बड़ी क्वॉलिटी, मतलब लार्जर दैन लाइफ।

■ आपने वेस्टर्न क्लासिकल के साथ फ्यूजन पर काफी काम किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत वेस्टर्न क्लासिकल से क्या सीख सकता है और क्या इसने नहीं सीखा?

यह बहुत बड़ा सवाल है और कंट्रोवर्शियल भी। मगर मैं सच बोलूंगा, क्योंकि मैंने वेस्टर्न म्यूजिक सीखा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत कभी एक प्लेटफॉर्म पर आ ही नहीं पाया। इसकी कमी रही। ये वेस्टर्न म्यूजिक से सीख नहीं पाए। इसी हफ्ते तानसेन समारोह में मेरे सामने चैलेंज था कि सबकी गमक अलग है, सबकी नॉब अलग है। हालांकि वही खूबसूरती भी है। घरानों के फर्क को मिटाकर अगर हम सिंफनी बनाना चाहें, जिसकी शुरुआत मैंने की और गिनिस बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ, ऐसा नहीं होता यहां। मैं चाहूंगा कि जितने भारतीय संगीतज्ञ हैं, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह साथ आएं। पर वे अपने ऑरा में, अपने रागों में ही आत्ममुग्ध रहते हैं। नया राग रचते हैं मगर वेस्टर्न म्यूजिक की बारीकियां नहीं सीखते। हमारे यहां हारमनी नहीं है- ऐसा खेल सब अपने अहंकार को दिखाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तानपूरे में तो दूसरे स्वरों की गूंज आ रही है- यही है हारमनी। नहीं, वह गूंज है। वह प्रैक्टिकल सुर थोड़े ही है? उससे रेजोनेंस आती है, सुर नहीं आते। जबकि एक सुर में दूसरे सुर की आवाज तो आ ही सकती है। वेस्टर्न म्यूजिक में पांच नोट एक साथ पिपनो में बजाकर हारमनी क्रिएट करते हैं। यह सीखना चाहिए था, जो नहीं सीखा, यह बात मैं खुलकर कह रहा हूं।

■ भारतीय शास्त्रीय संगीत का भविष्य आप कैसा देखते हैं?

यह कभी पॉप म्यूजिक बनेगा नहीं। यह स्टेडियम का संगीत है ही नहीं। यह तो महफिलों का संगीत रहा है। मैं क्लैक्ट गुटं की बात से सहमत हूं कि इससे जो शांति मिलती है उस बात का प्रचार थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए।

■ क्या श्रोताओं के साथ भी दिक्कत है?

ऐसी श्रोताओं के बारे में बदनामी फैलाई गई। राजाओं के टाइम से ऐसी धारणा बन गई कि शास्त्रीय संगीत दीवान-ए-खास में होता था और लोक संगीत दीवान-ए-आम की चीज है। मुगलों के आने से पहले के राजाओं में ऐसा नहीं होता था। वहां एक ही दीवान होता था।

> सिर्फ तबला प्लेयर नहीं थे जाकिर भाई। वह एक ग्लोबल मास्टर थे। उन्होंने वाह ताज किया, शक्ति बैंड बनाया, फिल्में भी कीं। यह इंडिविजुअल टैलंट की बात है। मर्चेंट आइवरी प्रॉडक्शंस की मुहाफिज फिल्म के संगीत पर जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो पाया कि वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के बारे में भी उन्हें कितना ज्ञान था

■ आपने शंख बांसुरी बनाई है। यह क्या है और इसकी जरूरत कैसे पड़ी?

फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपने गुरु पं. रविशंकर के साथ मैं मॉस्को गया था। वहां वह जब मेरे गुरुभाई विश्वमोहन भट्ट को और तरुण भट्टाचार्य को सिखा रहे थे, एक खास सुर पर बांसुरी जा ही नहीं पा रही थी। मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया। गुरुजी ने मुझे दूसरे दिन सुबह छह बजे अपने कमरे में आने को कहा। मैं गया तो उन्होंने कहा कि नई बांसुरी बनाओ, कुछ नया करो। म्यूजिक तुमसे कुछ नया चाहता है। मैं भारत आया तो बहुत सारे बड़े-बड़े बांसों को जोड़कर, बिगाड़ कर बनाता, और ऐसे शंख बांसुरी बनी।

■ बांस की बांसुरी की जगह आजकल PVC पाइप और स्टील की बांसुरी खूब चल रही है। सुर या मिठास में इनमें कुछ खास अंतर होता है?

बांस में रेशे होते हैं, इससे गूंज पूरे बांस से निकलती है। कभी भी स्टील या PVC पाइप में वो गूंज नहीं आती है। वह सुरीला भले हो जाए, मगर एक डेड साउंड लगता है।

■ आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं बांसुरी की। क्या बिना गुरु के बांसुरी सीखी जा सकती है? सीखने के लिए कैसी बांसुरी होनी चाहिए?

शुरू में सीखने के लिए कोई सादगंड नहीं बनाया जा सकता। सबकी हथेली का जो पंजा होता है उसकी साइज अलग होती है। उंगलियों की लंबाई पर डिसिजन होता है। ऑनलाइन क्लासेस से बहुत दुख है। लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि दो महीने में बांसुरी सीखिए। ऐसा कैसे खेल सकते हैं? एक महीने में तो सरगम भी नहीं आती। यह ठीक नहीं है। शुरुआत में बांसुरी बजाना आसान है। छह महीने में कोई भी फूं-फां करके सीधे सादा फिल्मी सॉन्ग बजा सकता है। बुरा बजाएगा, मगर बजा लेगा। लेकिन आगे चलकर ऊंचे स्तर में मुश्किल होती है। इसलिए यह बड़ा नुकसान हो रहा है।

रीडर्स मेल

चीन से सतर्कता

20 दिसंबर का संपादकीय 'सहयोग संग सावधानी' पढ़ा। हमें पड़ोसी मुल्क चीन पर भरोसा करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीन के साथ इंस्टर्न लद्दाख में LAC पर देपसांग और डेमचॉक में गतिरोध खत्म करने पर पिछले दिनों भले ही समझौता हो गया हो, सीमा पर हमारे जवानों को सतर्क रहना होगा। पूरी दुनिया जानती है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। चीन पूरे एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और ऐसा करने में वह किसी भी हद तक जा सकता है। चीन यह भी अच्छी तरह जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चीन ने भारत की बढ़ती ताकत के सामने समझौता करने के विकल्प पर मजबूरी में ही विचार किया है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि डोकलाम में चीन भारत की सीमा में घुसने की नाकाम कोशिश कर चुका है। बफर जोन में ग्रेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत होनी अभी बाकी है। भारत को सोच-समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

कुंभ की तैयारी

20 दिसंबर का लेख 'देश की ग्लोबल ब्रैंडिंग का मौका है कुंभ' मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे ऐतिहासिक महाकुंभ के महत्व को दर्शाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसा आयोजन है, जो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं को जोड़ता है और देशवासियों को धार्मिक सहनशीलता और भाईचारे का संदेश देता है। लेख पढ़ने पर पता चला कि आयोजन इस बार हाईटेक होगा और इसमें सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह अच्छी बात है। निश्चित ही यह आयोजन भारत की वैश्विक पहचान और छवि को मजबूती देगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कुंभ में इकट्ठा होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का ध्यान रखना होगा और ट्रांसपोर्टेशन के पुख्ता इंतजाम करने होंगे।

प्रियंका रावत, इमेल से

आज का अंक : पेज 1 से 24 तक। सर्वाधिकार सुरक्षित। रिप्रोडक्शन अनुमति के बिना छापना या आंशिक पुनर्मुद्रण पूर्ण प्रतिबंधित। राजधानी दिल्ली, मीरापुरी राज्य मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन। 2 अक्टूबर 1950 को पंजीकृत। नवभारत टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड, नवभारत टाइम्स, सर्वोदय मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रक

हिन्दुस्तान
1936

निवेश बढ़ाना होगा

भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट पर चिंता स्वाभाविक है। शुक्रवार को बॉम्बे शेयर बाजार के शेयर सूचकांक में 800 अंकों की गिरावट देखी गई है। अगर सप्ताह की बात करें, तो यह सप्ताह गिरावट के नाम रहा है। निवेशकों को पूरे सप्ताह नुकसान का सामना करना पड़ा है। सेंसेक्स में 3,700 अंकों की गिरावट को कम नहीं समझना चाहिए। निफ्टी अपने निचले स्तर पर ही चल रहा है और अकेले शुक्रवार को उसमें 250 अंकों की गिरावट हुई है। टीसीएस, रिलायंस, इंफोसिस, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक जैसी महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयरों में गिरावट की वजह से ही बाजार ज्यादा प्रभावित हुआ है। जब बड़ी कंपनियों के शेयर भाव घटने लगते हैं, तब दूसरी अनेक कंपनियों के शेयर पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। चिंता यह होने लगी है कि साल का आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है और अगर भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का क्रम जारी रहा, तो अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छी बात नहीं है। वैसे भी यह कई लोगों के लिए छुट्टियों का समय है, वे क्रिसमस मनाने और साल को विदा करने की तैयारी में लगे निवेशक बाजार में जोखिम लेना नहीं चाहेंगे।

गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में कम कटौती की संभावना है। कटौती अगर कम होती है, तो अमेरिकी निवेशकों के पास भारतीय बाजारों में निवेश के लिए धन कम पड़ने लगेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी भारत से बाहर जा रही पूंजी की मात्रा बढ़ी है। अमेरिकी निवेशकों के बारे में यह कहा जाता है कि अगर उन्हें अपने देश में ही फायदा दिखे, तो वे विदेश का रुख नहीं करते हैं। जब उन्हें देश में नुकसान की आशंका होती है, तभी वे पैसा बचाने और बनाने के लिए भारत जैसे देशों की ओर देखते हैं। ध्यान देने की बात है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों के पिछले चार सत्र में ही 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। अब सवाल यह है कि भारत से पूंजी प्रवाह का क्रम कैसे रुक सकता है? एक ही उपाय है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, लेकिन फिलहाल घरेलू अर्थव्यवस्था ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को अगर डॉलर के मूल्य से मापा जाए, तो हमारा रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है। यह भी संकेत मिल रहा है कि लगातार तीसरी तिमाही में भारतीय विकास दर अनुमान के मुताबिक नहीं रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को सोचना पड़ेगा कि उत्पाद में सुधार की ज्यादा जरूरत है या सेवा में? दोनों ही क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन दुनिया के ज्यादातर देशों से अच्छा रहा है। आगे भी हमारी स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए ज्यादा उपाय आजमाने की जरूरत महसूस होने लगी है। हमें किसी अन्य देश से तुलना करने के बजाय अपने प्रदर्शन में स्वयं सुधार करना चाहिए। अगर बड़े उद्योग और बड़े उद्योग क्षेत्र तेजी से विकास नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था अगर घरेलू मोर्चे पर मजबूत रही, तो विदेशी निवेश स्वाभाविक ही आएगा। प्राथमिक रूप से हमें स्वदेशी निवेश को सुनिश्चित करना होगा। अगर अर्थव्यवस्था में मांग घट रही है, तो उसे बढ़ाने के उपाय किए जाएं और ऐसे उपाय पहले भी सफलतापूर्वक आजमाए गए हैं।

भारत का आर्थिक प्रदर्शन ज्यादातर देशों से अच्छा रहा है। आगे भी हमारी स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए ज्यादा उपाय आजमाने की जरूरत अब महसूस होने लगी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 21 दिसंबर, 1949

उचित निर्णय

भारतीय पार्लमेंट ने हिन्दू कोड बिल पर आम बहस समाप्त कर ली। पार्लमेंट में और उसके बाहर इस बिल की धाराओं के संबंध में उग्र मतभेद देखने में आया। बिल के विरुद्ध विरोधी प्रदर्शन भी हुए और कुछ लोगों ने तो सामान्य शिष्टाचार की मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर डाला। ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार विरोधी दलों ने अपने मन की निकालने के लिए इस बिल को औजार बनाया है। दूसरों से अपनी बात सुनवाने के लिए हुल्लड़बाजी का प्रयोग किया जाये, इसको हम किसी भी अवस्था में उचित नहीं समझते। यह लोकतंत्री नहीं, फासिस्ट तरीका है। लोकतंत्र में दूसरों को शान्तिपूर्वक अपनी बात समझानी होती है और उतनी ही शान्ति के साथ दूसरों की बात सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। पार्लमेंट में हिन्दू कोड बिल के विरोधियों को अपना मत प्रकट करने का पूरा मौका दिया गया और उस पर पूरे नौ दिन तक बहस जारी रही। कांग्रेस पार्टी ने अपने सदस्यों को यह स्वतंत्रता दे दी थी कि वे अपनी इच्छानुसार बिल के पक्ष या विपक्ष में बोल सकते हैं। इसलिए किसी को यह शिकायत करने का मौका नहीं हो सकता कि सरकार अपने बहुमत के बल पर येन-केन प्रकारेण बिल को कानून का रूप दे देना चाहती है।

प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अन्तिम दिन हिन्दू कोड बिल पर सरकार की स्थिति को बड़े ही सौम्य रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार कुल मिलाकर इस बिल में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, उससे सहमत है। सरकार को यह सुझाव मान्य नहीं कि इस बिल पर विचार ही नहीं किया जाये। किन्तु वह ऐसा मार्ग अपनाने को तैयार है जिससे उसके पक्ष में अधिक से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेहरूजी ने जो सुझाव पेश किया और जिसे पार्लमेंट ने स्वीकार लिया, वह पार्लमेंटरी परम्परा के इतिहास में अनोखा है। उसके अनुसार भारत सरकार के कानून मंत्री डा. अम्बेडकर उस कमेटी के सदस्यों के साथ जिसने इस बिल पर विचार किया, पार्लमेंट के अन्य सदस्यों के साथ और पार्लमेंट के बाहर आम जनता के कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ बिल के संबंध में परामर्श करेंगे। परामर्श के लिए उन लोगों को भी आमंत्रित किया जायेगा, जो बिल से सहमत नहीं हैं।

समावेशी भाव के साथ मिल-जुलकर संविधान की रचना हुई थी और संविधान आज भी वैसे ही व्यवहार की उम्मीद करता है। संविधान सभा में 27 दिसंबर, 1948 को जब आपत्ति हुई कि आपने तो ईश्वर को छोड़ दिया, तब बाबा साहेब ने जैसा समाधान किया, वह आज भी राह दिखाता है।

संविधान में भी भगवान को याद करना चाहिए

यहां स्कैन करें

एच वी कामथ | संविधान सभा सदस्य

- हम ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद मांगना भूल गए थे, ऐसा क्यों हुआ?
- क्या ये समझते हैं, कानून बनाकर ईश्वर के अस्तित्व को मिटा सकते हैं?
- हमें जो आध्यात्मिक बपौती प्राप्त है, उसे कतई छोड़ना नहीं चाहिए।

श्रीमान, जैसे मैंने विधान को ध्यानपूर्वक पढ़ा, तो मेरे मन में एक दुःखद बेचैनीपूर्ण भावना रही कि विधान में एक कमी है, एक शून्यता है।...

हम ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद मांगना भूल गए थे, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे यह विचित्र-सी बात लगती है कि एक भारतीय परिषद् के समक्ष, भारतीय विधान पर बोलते हुए, मुझे आगे बढ़कर आपके सामने इस संशोधन के लिए अनुरोध करना पड़ता है। मुझे यह अनुरोध करना पड़ता है कि ईश्वर को हमारे विधान में स्थान मिलना चाहिए। श्रीमान, मेरी तो यह धारणा थी कि प्रस्तावना का ही आरंभ ईश्वर की स्तुति से होना चाहिए था। अस्तु, वह बाद में आ रही है और हम देखते हैं कि उसका क्या होता है। कदाचित यह ईश्वर की इच्छा थी कि विधान उनके नाम से वंचित होना चाहिए और बाद में विधान पर वाद-विवाद के समय भगवान के नाम की स्तुति की जानी चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं, श्रीमान, क्या मेरे मित्र ऐसा समझते हैं- वे मित्र, जो इस प्रार्थना का कोई महत्व अथवा मूल्य नहीं समझते कि भगवान को हटा देने से, अपने मस्तिष्कों और विचारों से अथवा विधान से भगवान शब्द को हटा देने से, वे विधान से ईश्वर को ही हटा रहे हैं? ईश्वर न करे, उनमें ऐसा कोई विचार हो। क्या वे समझते हैं कि वे कानून बनाकर ईश्वर के अस्तित्व को मिटा सकते हैं?

श्रीमान, हम भगवान को जितना दूर हटाते हैं, हम जितना उससे भागते हैं, उतना ही वह हमारा पीछा करता है।... भारत में, श्रीमान, जहां कि हमारी प्राचीन संस्कृति है, आध्यात्मिक विवेक है और हम सबको पूर्वजों से प्राप्त एक बपौती है...। यह कहना अनावश्यक है कि किस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे सब कार्य भगवान को अर्पण करने की गंभीरतम आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत रहते हैं। हिंदू परिपाटी तथा परंपरा के अनुसार, हमारे संस्कार के आरंभ में *हरि ओम् तत्सत्* कहा जाता है। हमारे मुस्लिम मित्रों के *कुरान शरीफ* में प्रत्येक पद के आरंभ में यह स्तुति होती है- *बिसमिल्लाह अल रहमान अल रहीम।* हमारे सिख मित्रों के *गुरुग्रंथ साहिब* का आरंभ *एकोंकार सत्नाम कर्ता* आदि शब्दों से होता है। हमारे ईसाई मित्रों को उनके मसीहा ने आज्ञा दी है कि जो भी तुम्हारे पास है, उसे छोड़ दो और मेरा अनुसरण करो। यह आशय *गीता* में भी है : *सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज।* अर्थात् सबका परित्याग कर दो, यहां तक कि सर्वधर्मों का भी और केवल मेरी अर्थात भगवान की शरण लो। अतः मुझे इस संशोधन पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, खाने-पीने से लेकर सर्वोच्च पूजन तक हमारे सारे कार्य भगवान के प्रति अर्पण, बलिदान होते हैं; अर्थात, *यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय! तत्कुरुष्व मदर्पणम्।।*

...श्रीमान, यहां हम बहुत गंभीर कार्य कर रहे हैं और यदि खाना-पीना भी भगवान के प्रति अर्पण का कार्य होता है, तो यह विधान भी, जो पवित्र कार्य है, ईश्वर के अर्पण अवश्य होना चाहिए। ...हमारे समस्त कार्य ईश्वर के प्रति अर्पित होने चाहिए। ...मैं अनुभव करता हूं कि विधान में, प्रस्तावना में भगवान की कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के अतिरिक्त यदि हम गंभीरतापूर्वक शपथ लेने का कार्य ईश्वर के नाम में नहीं करते हैं, तो यह केवल एक शून्य संस्कार बन जाएगा।... हकुमते-हिंद के प्रधान सेनाध्यक्ष तथा प्रतीत प्रधान बने थे, तब उन्होंने इस प्रकार शपथ ली थी : ईश्वर के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं।

...अतः श्रीमान, अंत में मैं परिषद से अनुरोध करता हूं कि हमने एक अनंत तथा आध्यात्मिक बपौती प्राप्त की है, एक ऐसी बपौती प्राप्त की है, जो न शारीरिक है, न भौतिक है और न लौकिक ही है...। हमें इस अमूल्य बपौती को खोना नहीं चाहिए...।

(संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

आमने-सामने

अब शपथ में हम ईश्वर को आधार मानेंगे

यहां स्कैन करें

बी आर आंबेडकर | संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष

- मसौदा समिति ने इस विषय पर पूर्णतः विचार ही नहीं किया था।
- अनेक प्रकार मत हैं, पर ईश्वर शब्द रखने का कार्य तो सीधा-सा है।
- ऐसे भी लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनकी आत्मा ही आधार है।

यह अच्छा होगा कि मैं इस बारे में कुछ शब्द कह दूं कि मसौदा समिति ने ही मौलिक मसौदे में 'ईश्वर के नाम पर' ये शब्द क्यों नहीं रखे थे? श्रीमान, मेरे विचार में मसौदा समिति ने इस विषय पर पूर्णतः विचार ही नहीं किया था, अतः मैं समुचित कारण नहीं बता सकता कि उन्होंने इन शब्दों को पहले क्यों नहीं रखा।...

जहां तक मेरा संबंध है, तो मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय था, जिस पर कुछ विचार करना अपेक्षित था। यदि परिषद अनुमति दे, तो मैं इस विषय पर अपने निजी विचार प्रकट करना चाहता हूं।...जहां तक मेरा अध्ययन है, ईश्वर शब्द का विभिन्न धर्मों में विभिन्न महत्व है। ईसाई और मुसलमान ईश्वर को एक कल्पना के समान ही नहीं मानते, बल्कि ऐसी शक्ति मानते हैं, जो संसार पर राज्य करती है और इस कारण आस्तिकों के नैतिक और आध्यात्मिक कार्यों पर शासन करती है। जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है, मेरे विचार से और मैं पूर्णतः गलती पर हो सकता हूं, मैं इस विषय का ज्ञानी होने का दावा नहीं करता। मेरा ख्याल था कि ईश्वर शब्द और बड़ा शब्द प्रयोग करें, तो परमेश्वर एक आशय का, एक कल्पना का निचोड़ ही है। जैसा मैंने कहा है। गणित की भाषानुसार आप संख्याओं को साथ रखकर कोई समान संख्या ढूंढ़ सकते हैं, जिसे आप 'स' कह सकते हैं, जो केवल निचोड़ होगा। इसके पीछे कोई ठोस वस्तु नहीं है। हिंदू दर्शन में यदि कोई ठोस कल्पना है, तो वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शक्ति है। हिंदू इन्हें ही संसार का शासन करने वाली शक्तियां मानते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मसौदा समिति के लिए इस आधार पर चलकर बहुत से शब्द रखना कठिन हो जाता, अर्थात परमेश्वर, उसके नीचे रेखा खींचकर शिव, फिर विष्णु, फिर ब्रह्मा, फिर शक्ति आदि-आदि रखने पड़ते। इस झगड़े के कारण ही हमने इस मामले को अनिश्चित छोड़ दिया, जैसा आप मसौदा समिति के कार्य में देखते हैं।

...किंतु मुझे पूर्ण प्रसन्नता है कि यह संशोधन पेश किया गया है। अब कुछ सदस्यों ने इस संशोधन पर आपत्ति की है। उन्हें भय है कि ईश्वर शब्द के रखने से असांप्रदायिक घोषित किए हुए राज्य के इस गुण में अंतर पड़ जाएगा। मेरे विवेकानुसार तो ईश्वर शब्द के रख देने से यह प्रश्न तो उठता नहीं। ईश्वर शब्द रखने का कार्य तो सीधा-सा है। विधान प्रधान के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है। ये कर्तव्य दो प्रकार के हैं- कुछ तो ऐसे कर्तव्य हैं, जिनके लिए कानूनी आधार है और कानूनी दंड की व्यवस्था की गई है, और कुछ ऐसे हैं, जिनके लिए कानूनी नियम नहीं हैं और कोई दंड भी तय नहीं है। परिणामतः, प्रत्येक विधान में यह प्रश्न सदा उठता है। ऐसे कर्तव्यों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए, जो किसी अधिकारी के लिए निश्चित किए गए हैं, किंतु जिनके लिए कानून द्वारा कोई आधार या दंड निश्चित करना संभव नहीं है, उनके लिए क्या आधार हो? ...हमें कोई न कोई आधार अवश्य रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ईश्वर ही आधार है। वे समझते हैं कि यदि वे ईश्वर के नाम पर शपथ लेंगे, तो वे ऐसे कर्तव्यों का आवश्यक आधार होगा, जो पूर्णतः नैतिक है और जिनके लिए कोई आधार नहीं रखा गया है, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मांड की संचालक शक्ति है और उनके व्यक्तिगत जीवन की भी संचालक शक्ति है।

ऐसे भी लोग हैं, जो विश्वास करते हैं कि उनकी आत्मा ही पर्याप्त आधार है। उन्हें किसी बाह्य शक्ति ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, जो प्रारंभ के समान उनके कार्यों का ख्याल रखे। वे समझते हैं कि उनकी आत्मा से निकली हुई गंभीर निश्चयोक्ति ही पर्याप्त आधार है। ...मेरे विचार में हमें चाहिए कि उसे ईश्वर के नाम पर शपथ लेने की स्वतंत्रता दें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो ईश्वर को विश्वसनीय मंत्री नहीं समझता हो, तो हमें उसे निश्चयोक्ति करने और उस निश्चयोक्ति के आधार पर अपने कर्तव्य करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।

(संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

नए साल में एआई से कितना बदलेगा हमारा जीवन

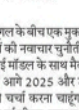

यहां स्कैन करें

जसप्रीत बिंद्रा | तकनीक विशेषज्ञ

हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए एआई मॉडल चैटजीपीटी या जेमिनी से बात करेंगे। अब हमारे उपकरण बदल जाएंगे, जिसमें बड़ी स्क्रीन की जगह आवाज प्रमुख हो जाएगी।

पिछले दिनों ओपनएआई और गूगल के बीच एक मुकाबला हुआ, जिसमें गूगल ने 12 दिनों की नवाचार चुनौती रखी और फिर अपने जेमिनी 2 एआई मॉडल के साथ मैदान में डट गई। मैं इन प्रतिस्पर्द्धाओं से आगे 2025 और उसके बाद के चार एआई रुझानों की चर्चा करना चाहूंगा, जो बताते हैं कि कैसे मनुष्य और एआई जीवन, काम व रिश्तों के संदर्भ में एक-दूसरे के करीब आएंगे?

पहला रुझान, अब कोडिंग नई अंग्रेजी है। जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी, तब हमें बताया गया कि अंग्रेजी सीखना सफलता का पासपोर्ट है। हमने ऐसा ही किया और अपने करियर व व्यवसाय में सफल रहे। बदले में हमने अपने बच्चों को यही बताया कि कोडिंग सीखना सफलता का पासपोर्ट है। इस प्रकार कोडिंग नई अंग्रेजी बन गई। इसी कारण 10 साल के बच्चे को भी पाइथन और जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए कोड कैंपों में घसीटा जाने लगा। जेनरेटिव एआई के आगमन के साथ तस्वीर बदल गई। अब हर बार जब हम चैटजीपीटी या इस जैसी किसी भी चीज से कोई संवाद करते हैं, तो वास्तव में हम 'कोडिंग' कर रहे होते हैं, यानी अपने कुछ काम के लिए उसे निर्देश दे रहे होते हैं, चाहे वह वीडियो बनाना या लेखन ही क्यों न हो। हम इससे मशीनी भाषा के बजाय अपनी कुदरती मानवीय भाषा में बात करने लगे हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसमें कोडिंग को लोकतांत्रिक बनाने व आठ अरब लोगों को कोड करने की क्षमता है। शायद इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला कहते हैं कि मशीन की भाषा सीखने के बजाय, अब मशीनें को हमारी भाषा सीखनी होगी। एनवीडिया के जेंसन हुआंग भी इससे सहमत हैं और कहते हैं कि एआई की असली क्षमता यह है कि हममें से किसी को भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार, अब अंग्रेजी या कोई भी अन्य प्राकृतिक भाषा नई कोडिंग भाषा बन जाती है।

दूसरा रुझान, एआई नई यूआई है, यानी एआई नई यूजर इंटरफेस बन जाएगी। बिल गेट्स ने नवंबर 2023 में भविष्यवाणी की थी- आपको अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग एप इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। आप अपनी डिवाइस को रोजमर्रा की भाषा में बता देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। दरअसल, यूआई वह माध्यम है, जिससे इंसान और मशीनें एक-दूसरे से संवाद करते हैं। सरल यूआई की वजह से मशीन के साथ ज्यादा तेज, सहज और उत्पादक रिश्ता बनाना संभव हुआ है। एआई के आने से यूआई हमारी आवाज से संचालित होगी, ठीक वैसे ही, जैसे हम किसी दूसरे इंसान से संवाद करते हैं। हम अपने रोजाना के कामों के लिए चैटजीपीटी या जेमिनी से बात करेंगे। हमारे उपकरण बदल जाएंगे, जिसमें बड़ी स्क्रीन की जगह आवाज प्रमुख हो जाएगी।

तीसरा रुझान, एआई और ईसान नए निर्माता हैं। जेनरेटिव एआई ऐसी तकनीक है, जो कला, कविता, लेखन जैसे रचनात्मक काम कर सकती है। इससे इंसानों की नौकरी पर संकट बढ़ गया, क्योंकि रचनात्मकता को एक विशिष्ट मानवीय कौशल माना जाता था। हालांकि, मेरा मानना है कि जेनरेटिव एआई इंसानों में रचनात्मकता बढ़ाने का ही काम करेगी। जैसे, पिछले हफ्ते जारी किए गए ओपेनएआई के सोरा को ही लें। जब सैम ऑल्टमैन ने एक साल पहले एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसका जिक्र करते हुए लोगों से किस तरह के क्रिएटिव वीडियो बनाने का सुझाव मांगा, तो भारतीय उद्यमी कुणाल शाह ने 'समुद्र में साइकिल रेस की कल्पना की, जिसमें साइकिल चलाते हुए अलग-अलग जानवर दिखाई' देने की संकल्पना थी। सोरा ने उसका शानदार वीडियो बनाया। जाहिर है, यह सोरा नहीं, बल्कि कुणाल की रचनात्मकता थी। साफ है, मनुष्य व एआई मिलकर रचनात्मकता के नए युग का सृजन करेंगे।

चौथा रुझान, एआई नया ग्राहक बनाती है। औद्योगिक क्रांति अपने साथ लेन-देन करने वाले औद्योगिक ग्राहक लेकर आई, जो शायद ही कभी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जबकि इंटरनेट ने डिजिटल-संचालित ग्राहक तैयार किए। एआई के इस युग में एक नए तरह का ग्राहक उभरेगा, जो नितांत निजता के युग में जिएगा और एआई उसकी जरूरतों व ब्रांड-संबंध का अनुमान एक सहयोगी के तौर पर बिना किसी भावना में बहे हुए लगाएगा। इसका मतलब यह है कि कारोबार और मार्केटिंग में बड़ा बदलाव आएगा। जाहिर है, यह सब हमारी जीवनशैली पर काफी असरदार होने वाला है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

यूरोप की नकल क्यों

यह देखना आसान है कि विकास की प्रक्रिया सार्वभौम है और मानवीय विकास को दार्शनिक विचारों की श्रेणी अथवा आचार के नियमों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। किसी युग, किसी व्यक्ति, किसी दल को सत्य का एकाधिकार नहीं है। ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के साथ भी यही है। यूनानियों में सौंदर्य-बोध था; उनका जीवन सुंदर था। आधुनिक यूरोप ने उनसे जो एक बात ग्रहण नहीं की, वह है सुंदरता। आप यह नहीं कह सकते कि आधुनिक यूरोप सुंदर है, वस्तुतः वह कुरूप है।

प्राचीन यूनान के विषय में जो कहा जा सकता है, वही प्राचीन भारत के बारे में भी कहा जा सकता है। उसमें भी सौंदर्य था, जिसका अधिकांश वह खो चुका है। जापान के लोग ही ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में सौंदर्य को बरकरार रखा। पर यूरोपीय प्रभाव में पड़कर वे भी अब उसे तेजी से खो रहे हैं।

यूरोप में मानव मस्तिष्क का जो हास हुआ, वह आश्चर्यजनक है।... हमने 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में सोचा था कि मानव मस्तिष्क ने बुद्धि का एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लिया है और इसके पहले कि कोई नया विचार स्वीकृति प्राप्त कर सके, उसको संतुष्ट करना होगा। पर ऐसा लगता है कि तनाव का सामना करने के लिए सामान्य बुद्धि पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हम पाते हैं कि नाजी विचार स्वीकार किए जा रहे हैं, पचास वर्ष पहले उनकी स्वीकृति का पूर्वानुमान लगाना असंभव होता। फिर जिस आसानी से बुद्धिजीवी मनोविश्लेषण और फ्रायड के विचारों को स्वीकार करते जा रहे हैं, वह आश्चर्यजनक है। इतिहास के सारे दौर में थोड़े लोग ही मानवता को बचाने के लिए मशाल हाथ में लेते हैं।

श्री अरविंद

आंबेडकर प्रेम का केवल दिखावा किया

मां भारती के महान सपूत और भारत के संविधान-निर्माता डॉ बी आर आंबेडकर देश की राजनीति में अचानक केंद्र में आ गए हैं। देश के गृह मंत्री का डॉ आंबेडकर के अपमान का इरादा नहीं था, वह वह साफ कर चुके हैं, पर कड़वी हकीकत यह है कि देश के करोड़ों दलितों को संसद में अनावश्यक उल्लेख पर आपत्ति है और इसीलिए विपक्ष ने यह मुद्दा जोरदार ढंग से संसद के अंदर और बाहर उठाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सफाई देने पर मजबूर किया है। मगर हमें यहां कुछ अन्य हकीकत को भी जान लेना चाहिए। जैसे, विपक्ष में खासकर कांग्रेस ने डॉ आंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया था, न ही उनका चित्र संसद में लगाया था। देश के दलितों की मांग थी कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण डॉ आंबेडकर के नाम पर किया जाए, लेकिन यह सब भी कांग्रेस ने नहीं किया।

इसी तरह, समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ और नोएडा में आंबेडकर स्मारक तो बनाया, पर उसके नेताओं ने आंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था और केवल पत्थर की मूर्ति कहकर मजाक उड़ाया था। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने तो कभी बाबा साहेब को भू-माफिया कहा था, जिस पर काफी बवाल मचा था। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में केवल बाबा साहेब की तस्वीर लगाने का काम किया है, उनके विचारों को सही अर्थों में मूर्त रूप देने का काम नहीं किया। दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग में इस बात से बेहद नाराजगी है कि डॉ आंबेडकर का नाम लेकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण बोर्ड का गठन भी मात्र दो वर्ष के लिए किया गया था। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली राज्य डॉ आंबेडकर रत्न अवॉर्ड का मुद्दा भी सरकार ने दबाकर रखा है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हमने जब भीम प्रतिभा योजना लागू की थी, लेकिन यह भी लंबे समय से बंद पड़ी है। आप सरकार के तीन मंत्रियों ने तो अपने पद से इस्तीफा देते समय केजरीवाल सरकार को दलित विरोधी करार दिया था।

ऐसे में, समझा जा सकता है कि कौन वास्तव में बाबा साहेब का अपमान कर रहा है? सभी पार्टियों के राजनेताओं को समझना चाहिए कि सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। उनको अगर आंबेडकर को अपनाना है, तो उन्हें वंचित वर्गों के हित में कई काम करने होंगे, अन्यथा उनका आंबेडकर प्रेम दिखावा ही माना जाएगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

आबंडेकर का अपमान

कम से कम उन्हें कानून मंत्री तो बनाया

यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि भारत रत्न का बंटवारा कांग्रेस ने केवल अपने प्रधानमंत्रियों के बीच किया। महू (मध्य प्रदेश) में आंबेडकर का स्मारक नहीं बनावाया। यह भी कि भाजपा के अनुसार आंबेडकर को सबसे अधिक महत्व और सम्मान उसने ही दिया। मान लीजिए, 15 अगस्त, 1947 को संयोगवश संविधान सभा बुलाने का अवसर भाजपा को मिलता (जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं, अकल्पनीय था), तो कौन मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें इसका अवसर देती और कानून मंत्री जैसा भारत के भाग्य-निर्माता का पद उन्हें सौंप देती, जबकि वह उसकी पार्टी के सदस्य भी नहीं थे? वह उदारता और बड़प्पन तो कांग्रेस ने ही दिखाया। यह तथ्य भी है और इतिहास भी।

एक बड़ा भारी भ्रम राजनेताओं ने यह भी फैला रखा है कि संविधान निर्माण का काम अकेले बाबा साहेब ने किया। हां, उन्होंने केंद्रीय और आधारभूत भूमिका जरूर निभाई। दूसरे, बाबा साहेब ने दलितों के मुख्य मुद्दों को संविधान में सस्मान स्वीकार करवाया। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, दोनों ने आंबेडकर के कानून मंत्री होने को शुभ माना। इस रूप में बाबा साहेब समूचे देश और समूचे भारतीय समाज के नेता के रूप में अंगीकार किए गए। वह केवल दलितों के नेता नहीं थे। नहीं कह सकता कि यह बाबा साहेब की स्वीकृति और सम्मान था या अपमान? कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बाबा साहेब के चुनावी प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा किया और बाबा साहेब को हरा दिया। तथ्य यह कि तब की जनसंघ ने भी उनके विरुद्ध अपना उम्मीदवार चुनाव में खड़ा किया। तो क्या यह माना जाए कि जनसंघ इस तरह बाबा साहेब को सम्मानित कर रहा था? सब जानते हैं लोहिया जी, जिदवश कई बार पंडित नेहरू के विरुद्ध फूलपुर से चुनाव लड़ा करते थे। दोनों गांधी में अपनी आस्था रखते थे, मगर वैचारिक दृष्टि की भिन्नता के चलते वह ऐसा चुनाव लड़ा करते थे। आंबेडकर ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, पंडित नेहरू के न चाहते हुए भी। तब उनके विरुद्ध कांग्रेस अपना उम्मीदवार न खड़ा करती, तो क्या करती?

सवाल यह कि जब पंडित नेहरू के खिलाफ भी दूसरी पार्टियां उम्मीदवार खड़े करती थीं। इसी तरह आंबेडकर के खिलाफ दूसरी पार्टियां अगर खड़ा किया करती थीं, तब इसमें सम्मान-अपमान की क्या बात? फिर, जनता को चुनना था और जनता के बहुमत ने उन्हें नकार दिया। तब अपराधी अगर हुई तो जनता हुई, कांग्रेस कैसे हुई?

विजय बहादुर सिंह, रचनाकार

हम मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना वित्तीय पुनर्निर्माण और सामाजिक सुरक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। -योशिहिदे सुगा

कैंसर और उम्मीद

आज दुनिया की सबसे घातक और चुनौतीपूर्ण बीमारियों में से एक कैंसर की वैक्सीन तैयार करने का रूस का दावा वाकई ऐतिहासिक है, जो न केवल चिकित्सा विज्ञान, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। गौरतलब है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई तो वर्षों से चल रही है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन की खोज में भी लगे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति बता ही चुके थे कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद नजदीक है और अब इस खोज ने वाकई कैंसर के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दे दी है। कैंसर के खिलाफ सफलता कितनी जरूरी थी, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है, जिनके अनुसार, दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट में करीब 17 लोगों की मौतें होती हैं। भारत में भी 2022 में कैंसर के चौदह लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। तथ्य यह भी बताते हैं कि विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते ज्यादा खराब है, जहां हर दस कैंसर मरीजों में से सात की मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में यह संख्या तीन या चार ही है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के अनुसार, अगले पांच वर्षों में देश में 12 फीसदी की दर से कैंसर के मरीज बढ़ेंगे। इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका इलाज अत्यंत महंगा और जटिल है, जिसके चलते यह आम आदमी की पहुंच से कई बार बाहर हो जाता है। रूसी वैक्सीन भी चूंकि अलग-अलग मरीजों की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएंगी, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा ही है, लेकिन इससे अब तक लाइलाज माने जाने वाले कैंसर को हराने का एक मार्ग तो खुला ही है। हालांकि अभी वैक्सीन के मनुष्य पर प्रयोग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। मरीजों पर इसका किस तरह इस्तेमाल होगा, क्या यह सभी तरह के कैंसर में प्रभावी होगी, कितनी

खराकें लेनी होंगी इत्यादि सवालों के जवाब जब सामने आएंगे, तभी इसकी परख संभव हो सकेगी। लेकिन ऐसे वक्त में जब नई-नई बीमारियां संकट पैदा कर रही हैं, रूस का दावा मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। अगर यह वैक्सीन सफल होती है, तो इससे निस्संदेह भविष्य में अन्य घातक बीमारियों के इलाज की राहें भी खुलेंगी।

फूंक-फूंक कर कदम रख रहा केंद्रीय बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार रेपो दर में बदलाव न किया जाना धीमी होती आर्थिक वृद्धि और महंगाई के दबाव के बीच संतुलन बनाने का संकेत है। यह रिजर्व बैंक के विकास को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दोहरे उद्देश्य को भी रेखांकित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार ग्यारहवीं बार रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा जाना, धीमी होती आर्थिक वृद्धि और लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के बीच सतर्कता का संकेत है। रेपो दर को 6.5 फीसदी बनाए रखने का फैसला रिजर्व बैंक के विकास को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दोहरे उद्देश्य को रेखांकित करता है। अक्तूबर में मुद्रास्फीति की दर 6.2 फीसदी थी, जो छह फीसदी की ऊपरी सहनीय सीमा से अधिक थी।

रिजर्व बैंक व्यापक रूप से उधार लेने की लागत को कम करने में हिचकिचा रहा है। दरों को स्थिर रखने के निर्णय के बावजूद रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की कटौती की है। इसे 4.5 फीसदी से घटाकर चार फीसदी करने के निर्णय से बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता आएगी और बैंकों की सकल आय में प्रति वर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक का नजरिया संतुलन दर्शाता है।

अजय बग्गा
आर्थिक मामलों के जानकार

रिजर्व बैंक आर्थिक मंदी के जोखिमों से निपटते हुए मुद्रास्फीति को दो से छह फीसदी के भीतर रखने को प्राथमिकता में रख रहा है। यह फैसला वैश्विक मौद्रिक रुझानों के अनुरूप है, जहां विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अस्थिर वैश्विक स्थितियों और अगले वर्ष राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाइयों के कथित जोखिमों के प्रति सतर्क हो रहे हैं। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह दर में कटौती के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने का एक खोया हुआ अवसर हो सकता है, क्योंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 की तीसरी तिमाही में 5.4 फीसदी है, जो सात तिमाहियों का निचला स्तर है। एक लोकप्रिय वित्तीय एजेंसी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 50 में से मात्र सात अर्थशास्त्रियों ने इस बार दरों में कटौती की घोषणा की थी। यह देखते हुए रिजर्व बैंक के पास मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए गुंजाइश है, जैसा कि इसके

घोषित जनादेश में कहा गया है, और लगातार दो महीनों से उपभोक्ता मुद्रास्फीति छह फीसदी की सीमाओं के पार है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रिजर्व बैंक इस बार दरों में कटौती नहीं करेगा।

इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने डॉलर के मजबूत होने, वैश्विक मुद्राओं के कमजोर होने, अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स की पैदावार में उच्च वृद्धि के लिए मंच तैयार किया है। कर कटौती, कम विनियमन, उच्च टैरिफ और समग्र संरक्षणवाद की ट्रंप की अपेक्षित नीति के कारण उभरते बाजारों से धन का प्रवाह अमेरिकी बाजारों में हो रहा है। आरबीआई के सामने यह मुश्किल चुनौती थी कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करे और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दे, जो स्पष्ट रूप से धीमी पड़ रही है और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि भारतीय रुपये पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। भारतीय रुपये में व्यवस्थित अवमूल्यन आरबीआई का अघोषित लक्ष्य है।

लोकसभा चुनाव के कारण, मार्च से जून की अवधि में केंद्र सरकार के बुनियादी ढांचे के खर्च और नई परियोजनाओं को मंजूरी देने में कटौती की गई थी। जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट पारित होने के बाद भी केंद्र सरकार का खर्च कम रहा है और बजटीय अनुमान से नीचे रहा है। केंद्रीय खर्च में यह धीमी वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, कोई कर रियायत नहीं और डेढ़ साल से अधिक समय तक उच्च ब्याज दरें जारी रहने से निजी खपत में गिरावट आई है। उपभोक्ता मांग में इस गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के परिणामों में कॉरपोरेट आय में धीमी वृद्धि हुई। ऐसे में समय की मांग थी कि राजकोषीय और मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर प्रति-चक्रीय (काउंटर-साइक्लिक) प्रोत्साहन दिया जाए। पीछे मुड़कर देखने पर रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को स्थिर रखने की नीतिगत कार्रवाई एक छूटा हुआ अवसर हो सकती है।

वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में सरकारी खर्च में तेजी आने की उम्मीद है। अक्तूबर के त्योहारी मौसम में शुरुआती उछाल के बाद नवंबर में उच्च आवृत्ति के संकेतक लगातार आर्थिक रफ्तार में मंदी का इशारा कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने खाद्य और ऊर्जा की उच्च कीमतों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ा दिया है। हालांकि यह नीतिगत रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को स्थिर करना है।

आर्थिक मंदी और गहरी हो सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए विकास पूर्वानुमान कम कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि रिजर्व बैंक आगामी फरवरी की बैठक से दरों में कटौती पर विचार कर सकता है, जो मुद्रास्फीति के 2 से 6 फीसदी के भीतर रहने पर निर्भर है। राजकोषीय नीति संरेखण, वैश्विक कमोडिटी कीमतें और बाहरी क्षेत्र की स्थिरता जैसे प्रमुख संकेतक किसी भी दर समायोजन के समय का मार्गदर्शन करेंगे। ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयां भी रिजर्व बैंक के कदम को वैश्विक पृष्ठभूमि प्रदान करेंगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अन्य मुद्राओं, खासकर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी या ताकत को प्रभावित करती है। यह प्रभाव कई कारणों से उत्पन्न होता है, जिसमें ब्याज दर फैसला, तरलता प्रबंधन और समग्र आर्थिक माहौल शामिल हैं।

मसलन, जब रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है, तो यह भारतीय मुद्रा को मजबूत बनाता है। उच्च दर भारतीय वित्तीय बाजार (बॉन्ड्स, इक्विटी) में विदेशी निवेश को आकर्षित करती है, क्योंकि निवेशक बेहतर रिटर्न चाहते हैं। भारतीय रुपये की बढ़ती मांग डॉलर के मुकाबले इसके मूल्य को बढ़ाती है। लेकिन ब्याज दरों में कटौती रुपये को कमजोर करती है। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला विदेशों में उच्च लाभ की तलाश में पूंजी के संभावित बहिर्वाह को रोककर रुपया का समर्थन करता है। रिजर्व बैंक की दिसंबर 2024 की नीति दूरदर्शी रूढ़िवाद को दर्शाती है। हालांकि यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन विलंबित प्रोत्साहन मंदी बढ़ा सकता है, जिससे भविष्य की नीतिगत चालों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मुद्रास्फीति और विकास की रफ्तार की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता होगी।

edit@amarujala.com

पर्यावरण

रहने लायक नहीं रहे शहर

विकास के रथ पर सवार देश के बड़े शहर कभी गैस चैंबर बन जाते हैं, तो कभी बाढ़ में डूब जाते हैं। आखिर हम सिंगापुर, सियोल व बीजिंग से सबक क्यों नहीं लेते?

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों व शहरों में निवास करने लगेगी। वर्ष 2001 तक भारत की आबादी का 27.81 फीसदी हिस्सा शहरों में रहता था। वर्ष 2011 तक यह 31.16 फीसदी और वर्ष 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 33.6 फीसदी हो गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 53 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है।

विकास के तेज रथ पर सवार भारत के बड़े-बड़े शहर कभी प्रदूषण के गैस चैंबर बन जाते हैं, तो कभी बाढ़ में डूब जाते हैं। मिसाल के तौर पर वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गिरावट की चिंताजनक दर यातायात की भीड़, व्यापक निर्माण से धूल और औद्योगिक प्रदूषण के कारण होती है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। भीषण गर्मियों के दौरान कूलिंग के लिए बिजली की बढ़ी मांग, भूजल के गिरते जल स्तर और पानी की कमी से इन शहरों की आबादी विकास की चमक-दमक के बावजूद त्राहि-त्राहि करने लगती है। चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर भारत की मिलेनियम सिटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा गुरुग्राम या फिर भारत की व्यापार नगरी मुंबई। दरअसल, भारत के अधिकांश शहर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक जाम, पीने योग्य पानी की कमी और लगातार बढ़ते जहरीले लैंडफिल के कचरे, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय गिरावट और वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यह रहने लायक नहीं बचे हैं। जहां एक तरफ उत्तर भारत के सभी नगरों समेत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में हर साल जाड़े का मौसम आते ही लोग वायु प्रदूषण से बेहाल, दम घोंटू हालात का सामना करने पर मजबूर नजर आते हैं। वहीं बंगलूरू और चेन्नई में, गर्मियों के दौरान पानी की कमी और इसके विपरीत, मानसून के दौरान बाढ़ से सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

सीमा जावेद

पिछले दो दशकों में बंगलूरू एवं पुणे, बेहतर मौसम, अच्छे रोजगार के अवसर, हरियाली और व्यवस्था के चलते आकर्षण का केंद्र व सबसे ज्यादा 'इन डिमांड' रहे। महानगरीय संस्कृति, सुरक्षित माहौल, और काफी मजबूत रोजगार व्यवस्था ने इन्हें प्रिय बना दिया। लेकिन, आज इसी बंगलूरू शहर को प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर पीने के पानी की कमी हो रही है, जो कि शहर की कुल जरूरत का पांचवां हिस्सा है।

वैश्विक यातायात भीड़ सूचकांक 2023 में बंगलूरू को भारत का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर घोषित किया गया था। गर्मी के मौसम में बेतहाशा गर्म तापमान के साथ ही, यहां बार-बार बाढ़ आने से जीवन हर साल अस्त-व्यस्त होता है। कमोबेश यही हाल पुणे का भी है। इस साल गर्मी के मौसम में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पुणे में दिन का तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हाल ही में इस साल, पुणे में भयानक बाढ़ आई थी, जब शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए थे। बंगलूरू शहर सिंगापुर से सबक सीख सकता है, जो 1980 के दशक में पानी की गंभीर कमी से परेशान था। इसने वर्षा जल को एकत्र करने और उसका पुनः उपयोग करने और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। दिल्ली इस मामले में बीजिंग और सियोल से भी सबक ले सकती है। साथ ही क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रोकथाम से लैस शहर अब आज की दुनिया की जरूरत बन चुके हैं।

खेल बहुत प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है, इसलिए जो व्यवसाय नवाचार व एआई की मदद नहीं लेंगे, वे नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। - पॉल डोचेर्टी

एआई के पहलुओं पर विचार करने से पता चलता है कि इसमें निवेश और सहभागिता करने वाले देशों का भविष्य उज्ज्वल है। -विल हर्ड

संयोगों की उपेक्षा न करें

कभी-कभी व्यक्ति को वह मिल जाता है, जिसकी उसे तलाश नहीं होती। यह भी हो सकता है कि एक असाधारण घटना आपको कुछ भी न दे, लेकिन यह भाग्य द्वारा दिया गया संकेत हो, जो आपको किसी महत्वपूर्ण प्रगति की ओर ले जाए।

प्रत्येक दिन की तरह मैं 28 सितंबर, 1928 की सुबह उठा, तो मैंने निश्चित रूप से ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई थी कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज करके पूरे चिकित्सा जगत में एक तरह की क्रांति लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही किया। दरअसल, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जीवन में संयोग का आश्चर्यजनक प्रभाव हो सकता है।

अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

अगर मुझे मेरे युवा प्रयोगशाला कर्मचारी को सलाह देनी हो, तो यह यह होगी कि कभी भी किसी असाधारण घटना की उपेक्षा न करें। क्योंकि कभी-कभी व्यक्ति को वह मिल जाता है, जिसकी उसे तलाश नहीं होती। यह भी हो सकता है कि वास्तव में असाधारण घटना आपको कुछ भी न दे, लेकिन यह भाग्य द्वारा दिया गया संकेत हो सकता है, जो आपको किसी महत्वपूर्ण प्रगति की ओर ले जाता हो। हम सभी इतिहास के पन्नों को बहुत तेजी से पलटकर आगे निकल जाते हैं। आप उन पन्नों पर थोड़ा ठहरिए, तभी आप कुछ नई संभावनाएं देख सकेंगे। कई बार मन अवसर के बढ़े हुए हाथों को नहीं देख पाता। लेकिन न्यूटन ने सेब को गिरते देखा, जेम्स वाट ने केतली को उबलते देखा, रॉन्टजन ने कुछ फोटोग्राफिक प्लेटों पर धुआं फैलाया। और ये लोग बखूबी सामान्य घटनाओं को किसी नई चीज में बदलने की खूबी को जानते थे। किसी विषय में पहला कदम अकेला व्यक्ति ही उठाता है, उसके बाद विवरण तो टीम द्वारा तैयार किए जा सकते हैं।

कभी-कभी तो नियमों को तोड़ना और कुछ ऐसा पाना बहुत ही सुखद होता है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न हो। सच तो यह है कि हम नहीं जानते कि आगे क्या मिलेगा। जीवन ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आप एक चीज खोजने निकलें और अंत में कुछ बिल्कुल अलग ही खोज लें। मैं पहले यह भी दावा कर सकता था कि मैं साहित्य के गंभीर अध्ययन और गहन विचार के परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मूल्यवान जीवाणुरोधी पदार्थ सांचों द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन यह असत्य के सिवाय और कुछ नहीं होता। मैंने सच को चुना और कहा कि पेनिसिलिन की शुरुआत एक संयोगवश अवलोकन के रूप में हुई थी। मेरी एकमात्र योग्यता यह है कि मैंने इस अवलोकन की उपेक्षा नहीं की और मैंने एक जीवाणुविज्ञानी के रूप में इस विषय का अनुसरण किया। हम सोचते हैं कि हम परिस्थिति के स्वामी हैं, पर हम जीवन की विसात पर किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा चलाए जा रहे मोहरे मात्र हैं।

जीवन धारा

एआई खोए प्रियजन की जगह नहीं भर सकता

एआई ने डिजिटल पुनरुत्थान तकनीक की मदद से मृत व्यक्तियों में प्राण भरने चाहे, लेकिन इसने प्रियजनों के खोने के दर्द को और उभार दिया।

डैमियन ट्यूसेट वरेला
ओबर्टा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

इस साल की शुरुआत में स्पेन के एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित हुए कार्यक्रम में लोगों को अपने मृत रिश्तेदारों से बात करते हुए दिखाया गया। दरअसल, ये आवाजें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई द्वारा मृत व्यक्तियों के वास्तविक ऑडियो की मदद से तैयार की गई थीं। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में जिस तरह का जुनून फैला और उनमें जैसी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भड़कीं, उससे ऐसे कार्यक्रमों के औचित्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे। एआई की इस तकनीक को डिजिटल पुनरुत्थान नाम दिया गया।

कइयों के लिए यह काफी मनोरंजक था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, जिनके लिए भावनात्मक रूप से इसे सहन कर पाना भी मुश्किल था। डिजिटल पुनरुत्थान को लेकर जो सवाल उठा, वह यह था कि वास्तव में किसी व्यक्ति के होने का क्या अर्थ है। किसी मृत व्यक्ति की डिजिटल आवाज तैयार कर क्या हम मान सकते हैं कि हमने उस व्यक्ति को दोबारा प्राण दे दिए या फिर हम बस उसकी छाया बना रहे हैं, जिसमें असल का अभाव है। ऐसी नकल के भी खतरे होते हैं, क्योंकि यह कभी असल अनुभव की बराबरी नहीं कर सकता। इसके बजाय यह एक ऐसे दुख को तेजी से उभार देता है, जिसे समय ने प्राकृतिक ढंग से दबा दिया था। जब कोई अपना नहीं रहता है, तो उसकी स्मृतियां हमारे दिमाग में रहती हैं। जब भी हम उसे याद करते हैं, तो वे स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। लेकिन कृत्रिम ढंग से अस्तित्व से छेड़छाड़ करने से प्राथमिक स्मृतियों में भी व्यवधान पड़ता है।

एआई जो कृत्रिम स्मृतियां बनाता है, वह नैतिक भी नहीं हैं, क्योंकि यह किसी तरह की राहत देता नहीं दिखता। एक व्यक्ति की स्मृति अनुभवों व रिश्तों का एक जटिल जाल होती है। लेकिन जब एआई की मदद से हम दोबारा उसे बनाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे प्रयास स्वाभाविक नहीं होते। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और इस क्षति से उबरने के लिए शोक आवश्यक है। डिजिटल पुनरुत्थान के माध्यम से मृतक के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश कर हम इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, जो हमें क्षति को स्वीकारते हुए शांति के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है। दरअसल, तकनीकी चाहे कोई भी हो, उसका एक व्यावसायिक पक्ष होता ही है, जबकि प्रियजन की हानि बेहद निजी, मानवीय और दर्दनाक पक्ष होता है। जाहिर है कि एआई की इन चीजों में घुसपैठ नैतिक सवाल भी पैदा करती है। सैद्धांतिक तौर पर बेशक यह कहा जाए कि एआई का उद्देश्य मनुष्य को राहत देना है, लेकिन व्यावसायिक फायदे के लिए व्यक्ति के जीवन के सबसे कमजोर क्षण का फायदा उठाना कहां तक उचित है। डिजिटल पुनरुत्थान के मूल में एक परेशान करने वाला विरोधाभाष है।

हमें उन लोगों के करीब लाने की कोशिश में, जिन्हें हमने खो दिया है, तकनीक दरअसल हमें उनकी गैर-मौजूदगी की कठोर सच्चाई से फिर से रू-ब-रू कराती है और जीवन का असल रूप दिखा कर विचलित भी करती है। किसी प्रियजन द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने के प्रयास उस व्यक्ति को फिर से पाने की उत्कट इच्छा के साथ हमारे लगातार जारी संघर्ष को गहरा देते हैं। कई बार देखा गया कि लोग एआई की मदद से विवाह जैसे समारोहों में हाल ही में गुजरे अपने पिता या माता का डिजिटल प्रारूप तैयार करवा लेते हैं। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं मालूम होता कि ऐसा करना पूरे माहौल को खराब कर सकता है, क्योंकि एआई कभी खोए हुए प्रियजन की जगह नहीं ले सकता। उल्टे यह उस दुख को और गहरा कर देता है। एआई के डिजिटल पुनरुत्थान प्रयोग से एआई की गंभीर सीमाएं ही जाहिर होती हैं। मृत व्यक्ति का डिजिटल प्रतिनिधित्व सांत्वना कम तकलीफ ज्यादा देता है। (-द कन्वर्सेशन से)

कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट

कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट एआई और मशीन लर्निंग में एक आम समस्या है। यह तब उत्पन्न होती है, जब डाटा के पैटर्न या व्यवहार समय के साथ बदलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो अपने ग्राहकों के खरीदारी पैटर्न पर आधारित भविष्यवाणियां करती है, यदि ग्राहक की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, तो उसे सटीक भविष्यवाणियां करने में समस्या होगी।

कॉबवेब

यह एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्लेटफॉर्म है, जो व्यवसायों को उनके डाटा से मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्वचालित और बेहतर बनाता है। कॉबवेब एआई विशेष रूप से बड़े डाटा संग्रह के विश्लेषण में कुशल है और इसे विभिन्न उद्योगों में लागू किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य, वित्त, और खुदरा। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल डाटा को सरल बनाना और मानव निर्णयों का सहायक बनना है। यह भविष्य की तकनीक की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कंपनियों को तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।